चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

30 सितंबर–06 अक्टूबर 2013

मोदी के साथ कौन है

जब से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, एक बहस शुरू हो गई है कि क्या मोदी का कद वास्तव में इतना बड़ा हो गया है या वे केवल परिस्थितियों की देन हैं. इस उम्मीदवारी के लिए जो भी दावे नरेंद्र मोदी के पक्ष में किए जा रहे हैं, उन पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं. वे विकास पुरुष हैं. इस दावे में हकीकत कम, चालबाजियां ज्यादा हैं. वे ईमानदार हैं. इसका हिसाब मीडिया प्रबंधन और रैलियों के नाम पर लुटाए जा रहे पैसों से मिल जाता है. मोदी अच्छे प्रशासक हैं, तो फिर उन पर हत्याओं का आरोप क्यों है? इन विफलताओं के बाद भी मोदी भाजपा के लिए सफल हैं. हालांकि उनके साथ कौन है, इसका फैसला होना बाकी है क्योंकि तस्वीर पर अभी काफ़ी धूल जमी हुई है.

> मान लेते हैं कि मोदी ने गुजरात के दंगे नहीं कराए या मोदी का गुजरात के दंगों को बढ़ाने में कोई हाथ नहीं था. यह भी माना जा सकता है कि सिर्फ़ मोदी पर दंगों का आरोप लगाना, उनके साथ अन्याय है, क्योंकि दंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में भी बहुत हुए और आज उसी तरह के आरोपों से अखिलेश भी घिरे हुए हैं. मोदी अपने को देश में सबसे ज्यादा विकास करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने लाते हैं. इसलिए मोदी का आकलन विकास को लेकर होना चाहिए, दंगों को लेकर नहीं.

संतोष भारतीय

इस समय देश, नरेंद्र मोदी के साथ कौन है और नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन है, इस पर बंटा हुआ है. मोदी के साथ जो भी लोग हैं, वे देश भक्त हैं और जो साथ नहीं हैं, वे देशभक्त नहीं हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है. इस माहौल पर पंचतंत्र की एक कथा याद आती है, जिसमें एक रंगा हुआ सियार अपने को जंगल का राजा घोषित कर देता है और उसके रंगे होने की वजह से शेर सहित सारे जानवर उसे पहचान नहीं पाते. सियार काफ़ी दिनों तक जंगल पर अपने बहुरुपियेपन या रंगे होने की वजह से राज करता है, पर जब सियारों की एक भीड़ हुआं-हुआं करने लगती है, तो रंगा हुआ सियार भी अपने को रोक नहीं पाता और हुआं-हुआं करने लगता है. इस पर शेर चौंक जाता है और सियार को मारकर खा जाता है. इस कहानी को आज के संदर्भ में ढाल कर देखें, तो संदेश मिलता है कि जो लोग चिल्ला-चिल्ला कर अपने को बड़ा देशभक्त बताते हैं, उनमें देशद्रोही तत्व सबसे ज़्यादा भरे हुए मिलते हैं. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हम नौजवान नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें.

हमारे देश में भेड़चाल बहुत मज़े से चलती है. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने शिगूफ़ा छोड़ा कि बूढ़ों को हटाकर नौजवानों के हाथ में राज सौंपना चाहिए. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पास न तो विश्लेषण की क्षमता है, न ही इतिहास से समझ लेने की अक़्ल. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ अब तक यह नहीं समझ पाया कि जिन बूढ़ों को संघ बेकार कह रहा है उनकी उम्र, उनका अनुभव और उनकी समझदारी ही उनकी असली ताक़त है. पचासों साल की मेहनत के बाद कोई एक लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी बनता है, जिसके सामने सारा देश होता है, जिसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, दलित भी होते हैं और सवर्ण भी. ऐसे लोग सत्य को नकारते नहीं, बल्कि सत्य की भाषा को शालीनता से रखते हैं. ऐसे लोगों के चेहरे और शरीर की भाषा आक्रामक नहीं होती, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली होती है.

अब तक देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए. राजीव गांधी के युवा होने की तारीफ़ कांग्रेस के साथ-साथ संघ ने भी की थी. बहुतों का यह भी मानना है कि उन्होंने देश का बहुत भला किया, पर यह अजीब विडंबना है कि राजीव गांधी ने जितने समझौते किए, उनमें कोई भी अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाया. चाहे राजीव-लोंगोवाल समझौता हो या असम गण परिषद के साथ हुआ समझौता हो.

राजीव गांधी की जल्दबाज़ी ने उनकी मां द्वारा खड़ी की गई लिट्टे नाम की ताक़त को तोड़ दिया. उधर प्रभाकरण के लोग मारे गए, वे भी अपने लोग थे और जो इधर मारे गए, वे भी अपनी सेना के ही लोग थे. हमारे देश का कन्याकुमारी का हिस्सा प्रभाकरण की वजह से ही सुरक्षित था, क्योंकि उसकी वजह से चीन, श्रीलंका में प्रवेश नहीं कर पा रहा था. राजीव गांधी के इस फ़ैसले ने चीन को श्रीलंका में जगह दे दी. इससे हमारी सुरक्षा की एक दीवार गिर गई.

राजीव गांधी के युवा होने की वजह से उनकी जल्दबाज़ी की मानसिकता को अगर कोई बुजुर्ग होता तो वह न अपनाता. नरेंद्र मोदी को भी आडवाणी और जोशी के मुक़ाबले युवा होने का फ़ायदा आरएसएस ने दिया. नरेंद्र मोदी में भी वही उतावलापन और वही जल्दबाज़ी है, जो राजीव गांधी में थी. इसीलिए नरेंद्र मोदी ने प्रचार की बदौलत बाज़ार में एक मायाजाल बुन दिया कि वो गुजरात में बहुत सफ़ल हैं और उन्होंने जो गुजरात में किया, वही सारे देश में करेंगे. बक़ौल मोदी उनके ऊपर सिर्फ एक लांछन है और वो भी गुजरात का.

चलिए मान लेते हैं कि मोदी ने गुजरात के दंगे नहीं कराए या मोदी का गुजरात के दंगों को बढ़ाने में कोई हाथ नहीं था. यह भी माना जा सकता है कि सिर्फ़ नरेंद्र मोदी पर दंगों का आरोप लगाना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि दंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में भी बहुत हुए और आज उसी तरह के आरोपों से अखिलेश यादव भी घिरे हुए हैं. अगर दंगों को आधार मानते हैं, तो वोटों का ध्रुवीकरण होता है. इसलिए नरेंद्र मोदी को दंगों से अलग रखकर बात करते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की नीति दंगे कराने की होती, तो 2002 के बाद भी गुजरात में दंगे हुए होते. मोदी को दंगों के नाम पर बदनाम किया जाता है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? मोदी अपने को देश में सबसे ज्यादा विकास करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने लाते हैं. इसलिए मोदी का आकलन विकास को लेकर होना चाहिए, दंगों को लेकर नहीं.

2014 के चुनाव में कुछ लोग दंगों को पैमाना बनाना चाहते हैं, लेकिन ख़ुद मोदी विकास को पैमाना बनाना चाहते हैं. इसलिए मोदी के इस दावे को जांचने-परख़ने की आवश्यकता है. 50 के दशक से ही औद्योगीकरण की दिशा में गुजरात देश में सबसे आगे था. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस गुजरात में है. हिंदुस्तान की सारी बड़ी रिफाइनरी गुजरात में हैं. सारे बड़े पॉवर प्रोजेक्ट गुजरात में हैं. गुजरात देश का अकेला ऐसा समुद्री तट है, जहां से प्राचीन काल से ही व्यापार होता रहा है. इसलिए स्वाभाविक है कि गुजरात में सबसे ज्यादा औद्योगीकरण होगा ही होगा. यह नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है. यह गुजरात के व्यापार संबंधी पारंपरिक आर्थिक सुदृढ़ता में है. अगर दिल्ली में डेढ़ करोड़ लोग आकर बस रहे हैं, तो इसमें शीला दीक्षित का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि दिल्ली में ही सारे बड़े दफ़्तर हैं. दिल्ली से ही राज-काज चलता है, इसलिए दिल्ली में लोग आएंगे ही और बसेंगे.

नरेंद्र मोदी अगर गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं होते, तो भी गुजरात का विकास होता ही. रिलायंस की फैक्ट्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले लगी. पहले उसकी कैपिसिटी 120 मिलियन टन थी, मोदी के आने के बाद आज भी उतनी ही कैपिसिटी है. अगर प्रगति होती तो नई-नई चीज़ें गुजरात में आतीं. नरेंद्र मोदी के राज में नया क्या आया? नरेंद्र मोदी के राज में टाटा की नैनो आई, जो कि फ्लॉप हो गई. मारुति का नया प्लांट आया. अदानी के कुछ पॉवर प्रोजेक्ट आए. अब इन प्लांट्स की गहराई में जाएं. नरेंद्र मोदी ने उद्योगों को 12 प्रतिशत सेल टैक्स की छूट दे दी. अब अगर इस छूट को कैलकुलेट करें, तो यह प्लांट मुफ़्त का पड़ जाता है. उदाहरण के लिए 10 करोड़ की लागत का एक प्लांट 100 करोड़ का उत्पादन करता है. अगर इस पर 12 प्रतिशत की सेल टैक्स की छूट को देखें, तो उद्योगपति 12 करोड़ की बचत करता है. 10 करोड़ की लागत से लगा हुआ प्लांट अगर 12 करोड़ का मुनाफा सेल टैक्स में छूट से कमा लेता है, तो कौन उद्योग लगाने नहीं जाएगा, क्योंकि प्लांट तो मुफ़्त का हो गया. नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में जितनी घोषणाएं कीं, उनमें से कितनी पूरी हुईं? अभी उन्होंने घोषणा की है कि वे सरदार पटेल की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी बनाएंगे. उन्होंने यह काम बीते 12 सालों के भीतर क्यों नहीं किया, क्या देश में लोहे की कमी थी? सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की बात 2014 के चुनावों के समय ही क्यों उठी? और वो सरदार पटेल, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ को प्रतिबंधित किया था. इसे जांचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास किस क़ीमत पर किया और सरदार पटेल की मूर्ति 12 साल पहले क्यों नहीं बना ली?

नरेंद्र मोदी के ऊपर सिर्फ़ इशरत जहां केस का आरोप ही नहीं है. जांच एजेसियों की रिपोर्टों को देखें, तो हरेन पांड्या का हत्याकांड भी याद आता है. सीबीआई ने फ़ाइनल रिपोर्ट लगा दी थी कि इसका कोई सुराग़ नहीं मिल रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा खोला जा रहा है. इसकी जड़ में तुलसी प्रजापति का केस भी है और अब यह सत्य सामने आने वाला है कि जो पुलिस अधिकारी इशरत जहां केस में शामिल थे, वही अधिकारी हरेन पांड्या के हत्यारों को अपनी गिरफ़्त में लेकर नेपाल बॉर्डर पर उन्हें सुरक्षित छोड़ आए थे. अगर एक भी आरोप साबित हो गया, तो यह माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए अपने साथियों को भी नहीं बख़्शते हैं. कुछ अख़बारों ने तो हत्या के आरोपी प्रधानमंत्री जैसी संभावनाएं भी व्यक्त कर दी हैं. इसका मतलब साफ़ है कि औद्योगीकरण स्वाभाविक रूप से हुआ, न कि इसके पीछे मोदी हैं. जिन नये कारखानों को लाने में वे अपनी प्रगति देखते हैं, वे इसलिए आए, क्योंकि उन्हें मुफ़्त में ज़मीनें और सेल टैक्स में छूट मिली. जहां भी यह सुविधाएं मिलेंगी, वहां उद्योगपति जाएंगे ही, क्योंकि सेज़ के नाम पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पार्ट 2

आधारहीन आधार कार्ड

03

राजस्थान कांग्रेस : हार के कारण

06

सफलता की ओर बढ़ते क़दम

07

साई की महिमा

12

मोदी के साथ कौन है

पृष्ठ एक का शेष

उद्योगपति ही ज़मीनें लूट रहे हैं. जो रिफ़ाइनरी नरेंद्र मोदी के आने से पहले लगीं, वो रिफ़ाइनरी तो उठ कर कहीं जा नहीं सकतीं. अब अगर रिफ़ाइनरी होगी, तो एक लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा ही. अगर रिफ़ाइनरियां रहेंगी, तो तेल का आवागमन बढ़ेगा. पर कैपिटा इनकम होगी, तब इसमें नरेंद्र मोदी का नया कमाल क्या था?

हां, नरेंद्र मोदी का एक नया कमाल है ज़रूर. उन्होंने गुजरात में संघ का सारा ढांचा तोड़ दिया, यानी बाढ़ ही खेत को खा गई. बंजारा की चिट्ठी बताती है कि इशरत जहां को मारने या तुलसी प्रजापति जैसे लोगों को मारने का फ़ैसला उनका नहीं, राज्य सरकार का था और राज्य सरकार से सीधा मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है. सवाल तो खड़ा होता है न! नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस नीति को बनाया, उस नीति का पालन करने वाले सिर्फ़ अफ़सर दोषी क्यों? नीति बनाने वाले भी तो दोषी होने चाहिए और हत्याओं को अगर सुप्रीम कोर्ट सही मान लेता है, तो नीति बनाने वाले लोग भी हत्या के षडयंत्र के हिस्सेदार हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग जेल में हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है. इसका सीधा-सा मतलब है कि या तो डीआईजी, आईजी, होम सेक्रेट्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री एफिडेविट दें कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि इशरत जहां, हरेन पांड्या और तुलसी प्रजापति केस का फ़ैसला दिसंबर तक हो जाएगा. ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर हत्या के संभावित कॉन्सिपिरेटर के तौर पर लगा धब्बा अपने आप हट जाए.

आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने कहा कि मेरे पिताजी ने बलात्कार नहीं किया. सवाल उठता है कि तब रात में आसाराम बापू लड़की के साथ क्या कर रहे थे? अदालत में आसाराम बापू के दोस्त और देश के एक नामी वकील तर्क़ देते हैं कि लड़की को यौन आकर्षण की बीमारी है. क्या यह तर्क़ शोभनीय है. यही बड़े वक़ील नरेंद्र मोदी के भी गहरे दोस्त हैं. उन्हें राज्यसभा में लाने का फ़ैसला नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुआ. वकालत का पेशा करना एक बात है और वकालत के साथ न्याय करना दूसरी बात. जो वकालत का पेशा करते हैं, वे धूर्तता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं. यह वकील साहब नरेंद्र मोदी की टीम का अहम हिस्सा हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आदमियों की पहचान उसके संगी-साथियों से भी होती है.

एक और कमाल हुआ है. अभी तक किसी ने नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछा कि उनकी धारा 370 के बारे में क्या राय है. किसी महान पत्रकार ने यह भी नहीं पूछा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर उनकी क्या राय है. समान सिविल कोड पर भी मोदी ख़ामोश हैं. इन सवालों पर मोदी इसलिए ख़ामोश हैं, क्योंकि जवाब आते ही या तो हिंदू रूठेगा या फिर मुसलमान. और अगर वे जवाब देते हैं कि अदालत के फ़ैसले को मानेंगे, तो वे कट्टर हिंदू हृदय सम्राट नहीं रह जाते. वो पत्रकार, जो इन सवालों को पूछने में अपनी शान समझते थे, आज ख़ामोश बैठे हैं. दरअसल, अभी समुद्र में ज्वार आया हुआ है और जब ज्वार आता है, तो भाटा भी आता है. हिंदुस्तान के मीडिया को एक पप्पू की तलाश होती है और इस समय उन्होंने नरेंद्र मोदी को पप्पू बनाया है. और जब कोई पप्पू बन जाता है, तो वह पप्पू बने रहने के लिए पैसे देता है और उसका विरोधी खेमा पप्पू को डब्बू बनाने के लिए पैसे देता है. मीडिया यही खेल कर रहा है. यह भी जानने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी के दावों में सच्चाई कितनी है. सिर्फ़ एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर वे अच्छे प्रशासक हैं, तो उन पर हत्याएं कराने का आरोप क्यों लग रहा है? अगर अच्छे प्रशासक हैं, तो ज़मीनें मुफ़्त में क्यों दे रहे हैं?

सत्य का एक पहलू यह भी है कि दुनिया का कोई क़ानून किसी की भलाई के लिए नहीं बनता. जो लोग ताक़तवर होते हैं, वे अपनी भलाई के लिए क़ानून बनाते हैं और इस प्रक्रिया में जिसका फ़ायदा होना हो, हो जाए. कुछ लोगों का हो भी जाता है. जैसे दिल्ली में कुछ कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला हुआ. यह फ़ैसला झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया. इसलिए किया गया, ताकि कांग्रेस जीत जाए. इसी बहाने झुग्गी-झोपड़ी वालों को फ़ायदा हो गया. मोदी बहुत जल्दी में थे, उन्होंने सारे देश में एक अच्छे राज्य और प्रशासक का प्रचार कराया. इसके लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों की सेवाएं लीं. मीडिया में इसका प्रचार कराया, जिसमें बड़ा पैसा टेलीविज़न चैनलों पर ख़र्च हुआ. किसी ने नहीं पूछा कि इतना पैसा आ कहां से रहा है. यह पैसा अंबानी, अदानी और रुइया ख़र्च कर रहे हैं या यह पैसा राज्य की योजनाओं के रास्ते बेईमानी से बह रहा है. नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी में एक बड़ी रैली हुई. इस रैली में करोड़ों रुपये ख़र्च हुए. वह पैसा कहां से आया? भाजपा के हमारे मित्र बताते हैं कि कम से कम एक लाख लोगों की सभा कराने का वायदा कोई करे, तो उसे प्रति व्यक्ति एक हज़ार रुपये के हिसाब से ख़र्च गुजरात में एक टीम दे सकती है.

मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न तो कार्यकर्ताओं के दबाव में बने, न ही पार्टी ने उत्साहित होकर बनाया. न ही वे साज़िश का परिणाम हैं और न ही पैसे वाले उन्हें चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनें. परिस्थितियां बन गईं. एक तरफ़ मीडिया पर अंधाधुंध पैसा जिस पर मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया कि यह पैसा कहां से आ रहा है. अन्ना हजारे अगर जनता के बीच घूमें, तो सवाल उठता है कि उनकी कार में पेट्रोल कौन डलवा रहा है. इस पर तुर्रा यह कि मोदी ईमानदार व्यक्ति हैं. शायद ईमानदारी कि परिभाषा बदल गई है. गुलजारीलाल नंदा इस देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी को याद नहीं है. गुलजारीलाल जी निहायत ईमानदार थे. दूसरा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का है, जो मृत्यु के समय बैंकों के कर्ज़े में थे. अब तो यह तय करने का सवाल है कि ईमानदार शब्द नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेगा या गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री के साथ. सवाल उठता है कि कौन मोदी के लिए इतना पैसा ख़र्च कर रहा है?

मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न तो कार्यकर्ताओं के दबाव में बने, न ही पार्टी ने उत्साहित होकर बनाया. न ही वे साजिश का परिणाम हैं और न ही पैसे वाले उन्हें चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनें. परिस्थितियां बन गईं. एक तरफ़ मीडिया पर अंधाधुंध पैसा, जिस पर मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया कि यह पैसा कहां से आ रहा है.

भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर देख चुकी थी और उसकी सीटें कम हुई थीं. इस बार उसके सामने दो ही चेहरे थे. महिलाओं में सुषमा स्वराज और पुरुषों में नरेंद्र मोदी. सुषमा स्वराज के पास पैसा नहीं था. हाइप क्रिएट करने की ताक़त नहीं थी. उनके पास सिर्फ़ उनकी वाणी थी. दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पास सब कुछ था. अरुण जेटली

और उमा भारती किसी कैटिगरी में नहीं आते. इसलिए नरेंद्र मोदी उम्मीदवार बनकर सामने आए. संघ नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना चाहता था. क्योंकि संघ गुजरात में नरेंद्र मोदी की वजह से अपने तंत्र की छिन्न-भिन्नता देख चुका था. नरेंद्र मोदी पूरी तरह से परिस्थिति की देन हैं. नरेंद्र मोदी स्वाभाविक उम्मीदवार कहे जा सकते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक उम्मीदवार हैं नहीं. संघ में संघ को नियंत्रित करने वाले जितने लोग हैं, उन सबकी उम्र आडवाणी जी से कम है. वे न आडवाणी जी से कुछ कह पाते थे, न ही उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर पाते थे. वे लोग आडवाणी नाम के बवाल से छुटकारा भी पाना चाहते थे. इसके लिए उन्हें नरेंद्र मोदी सबसे उपयुक्त पात्र नज़र आए. कहा जा सकता है कि सुषमा स्वराज और मोदी में, मोदी के पास पैसा था और मीडिया को इस्तेमाल करने की चालाकी थी. बीजेपी को एक चेहरे की तलाश थी, ताकि आडवाणी के समय से और कम सीटें न आ सकें. संघ न केवल आडवाणी से छुटकारा पाना चाहता था, बल्कि देश में यह कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करना चाहता था, क्योंकि उसको इस कहावत पर भरोसा था कि बदनाम हुए तो क्या, नाम न हुआ.

भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, जिन्हें इस रणनीति में बहुत बड़ी ख़ामी नज़र आती है. वे कहते हैं कि अगर अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले मोदी के नाम की घोषणा होती, तो जनता दल उनसे दूर नहीं जाता. तब तक ममता बनर्जी और जयललिता से भी पक्की बात हो सकती थी. तब तक आडवाणी जी के नाम का भ्रम बने रहने देना चाहिए था. अब जयललिता ने कह दिया है कि वह चुनाव के बाद गठंबधन पर विचार करेंगी. करुणानिधि ने मोदी से मिलने से मना कर दिया है. ममता बनर्जी मोदी का नाम नहीं सुनना चाहतीं और नीतीश कुमार ने तो खुद को पहले ही अलग कर लिया है. इतना ही नहीं, बिहार में सरकार भी नहीं जाती. अगर बिहार में सरकार नहीं जाती, तो उसका असर दिल्ली पर पड़ता. उस स्थिति में बिहार और पूर्वांचल के सारे वोट भाजपा को मिलते, तो दिल्ली में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाती. राजस्थान में जनता दल यू की उपस्थिति है. वहां वह बीजेपी का साथ देता और आसानी से उनकी सरकार बनती. आज की तारीख़ में वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत बराबरी पर खड़े हैं. राज्यों के चुनाव भी निकल जाते और मोदी का टेस्ट भी नहीं होता. मोदी संभावित अघोषित उम्मीदवार के तौर पर कर्नाटक गए थे. भाजपा वहां बुरी तरह न केवल चुनाव हारी, बल्कि उपचुनाव भी हारी. अगर अचानक घोषणा होती, तो कांग्रेस भी परेशानी में पड़ जाती और उस समय यही हाइप क्रिएट होती, जो आज हुई है, तो मोदी 370 सीटें ला सकते थे. अगर कोई राजनीतिक दिमाग़ फ़ैसला लेता तो ऐसा फ़ैसला लेता. चूंकि यह फ़ैसला परिस्थितिजन्य रहा, इसलिए इन बातों पर विचार ही नहीं हुआ. अगर मान लीजिए चार राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी पिट गई, तो क्या होगा? जब तक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता. मोदी ब्रांड का तब क्या होगा? पिछला लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है. कोई नहीं मानता था कि कांग्रेस 110 या 112 से ऊपर जाएगी, लेकिन कांग्रेस 200 सीटें ले आई.

भारतीय जनता पार्टी में साज़िशें आजकल बहुत होती हैं. दो घंटे बाद नितिन गडकरी को भाजपा के अध्यक्ष पद पर दूसरा कार्यकाल मिलने वाला था. एक इनकम टैक्स अफ़सर नितिन गडकरी के यहां चाय पीने गया और वस्तुत: वह उन्हें एक नोटिस देने वाला था. उसने चाय पीनी शुरू की और इधर सारे देश के चैनलों में यह ख़बर चलनी शुरू हो गई कि गडकरी के यहां छापा पड़ा है. भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता वित्त मंत्री के संपर्क में था और कौन टेलीविज़न चैनलों के संपर्क में था, जो चाय की शुरुआत होते ही सब जगह ख़बरें चलने लगीं कि छापा पड़ा. आडवाणी जी ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि साज़िशी लोगों ने मोहन भागवत से ऐसा बयान दिलवा दिया कि वह अध्यक्ष पद पर डी4 को नहीं चाहते. डी4 यानी आडवाणी जी के साथी. इस देश का मीडिया आज तक तो इतना तेज़ नज़र नहीं आया कि एक इनकम टैक्स का अधिकारी चाय पीने जाए और उन्हें ख़बर मिल जाए. क्या भारतीय जनता पार्टी साज़िशी पार्टी बन गई है. इससे तो यही लगता है कि इस पार्टी में साज़िशें बड़ी ख़ूबसूरती से चलाई जा रही हैं. नरेंद्र मोदी के राज्य में अंबानी, रुइया, अदानी, टाटा सहित व्यापारियों की मजबूरी है कि वे मोदी का साथ दें और नरेंद्र मोदी का फ़ायदा 100 रुपये लगाकर 1000 रुपये कमाएं. शरीर विज्ञान को जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि उछल-उछल कर चलने वाला आदमी सोची-समझी तरक्की करता है और संयोग से नरेंद्र मोदी की चाल उछल-उछल कर चलने वाली ही है. नरेंद्र मोदी ने इस थ्योरी को सही साबित किया है. उनकी शुरुआत राजनीति की सबसे निचली सीढ़ी से हुई और आज वे पहले पायदान पर आ चुके हैं. नरेंद्र मोदी के दिमाग़ की और उनकी रणनीति की बिना शर्त तारीफ़ करनी चाहिए.

देशद्रोह सिर्फ़ देश के बारे में दुश्मनों को समाचार देना ही नहीं होता. लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रहार करना भी देशद्रोह होता है. और अगर हम भारत की सेना में सांप्रदायिकता फ़ैलाने की कोशिश करें, तो यह देशद्रोह से कम नहीं है. अगर 20 करोड़ लोगों को अरब सागर में डुबा देने या 20 करोड़ लोगों की सामूहिक हत्याएं करने की योजना मन में नहीं है, तो 20 करोड़ लोगों को साथ लेकर जीने की और विकास करने की बातें सामने आनी चाहिए. जो अभी तक सामने नहीं आई हैं. इसलिए जो ज्यादा देशप्रेम-देशप्रेम चिल्लाते हैं, दरअसल वे अपनी देशद्रोही वृत्ति को छिपाने के लिए देशप्रेम का नाम लेते हैं. सबसे बड़े यक्षप्रश्न का उत्तर अभी भी भविष्य के गर्भ में है. अगर नरेंद्र मोदी 160-180 या दो सौ सीटें भी जीत जाते हैं, तो बाक़ी 73 सीटें कहां से आएंगी और तब भारतीय जनता पार्टी और संघ को लालकृष्ण आडवाणी के दरवाज़े पर जाना ही पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी में इस समय वही एकमात्र नेता हैं, जिनका ज़्यादातर राजनीतिक दलों में संपर्क है और यही लालकृष्ण आडवाणी की ताक़त है.■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 05 अंक 30
दिल्ली, 30 सितंबर–06 अक्टूबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

बाबुओं पर घोटालों की मार

दिलीप चेरियन

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति का मसला पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. आर एस विर्दी, जो कि इस पद की दौड़ में शामिल थे, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उन्हें 10 वर्ष पुराने एक मामले में दोषी ठहराया है. अब इस मामले के खुलासे के बाद यह तो है कि विर्दी की उम्मीदवारी समाप्त हो रही है. सूत्रों का कहना है कि कार्यवाहक चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार अब इस पद के प्रमुख दावेदार हैं. हालांकि, लोगों का यह भी कहना है कि कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर राधे श्याम भी इस पद के लिए छुपा रुस्तम दावेदार साबित हो सकते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी है. इस बीच विर्दी ने अपना बचाव करते हुए कहा है कि उनकी उम्मीदवारी को रोकने के लिए जबरदस्ती गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है और उन्होंने रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस मामले में मध्यस्थता करने की अपील की है. हालांकि वे इसमे सफल नहीं हुए हैं. इसी तरह की स्थित शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पैदा हुई, जहां एक उम्मीदवार कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व एमडी के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन सीबीआई ने उसकी संलिप्तता एलटीसी स्कैम में बताई. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पिछली जनवरी माह से नेतृत्वविहीन है और पिछले दो वित्तीय वर्षों में घाटे के चलते इसे नवरत्न कंपनियों की सूची से बाहर भी किया जा सकता है.■

पारदर्शिता की मिसाल

नौकरशाही में पारदर्शिता, यह इतना विरोधाभाषी हो गया है कि जब कोई अधिकारी ऐसा करने साहस दिखाता है तो वह चर्चा का विषय बन जाता है. पिछले हफ्ते कर्नाटक में एक ऐसी ही घटना हुई. ग्रामीण विकास कमिश्नर मुनीश मुद्गिल, जोकि मनरेगा स्कीम को राज्य में लागू करने के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना की डेली रिपोर्ट वह लोगों को देंगे.

सत्यमेव जयते

क्या यह केवल वाहवाही के लिए था? नहीं. सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपना वायदा पूरा किया और मीडिया को सारी जानकारी दी. इतना ही नहीं, उन्होंने न केवल सूचनाएं सार्वजनिक कीं,बल्कि एक टोल फ्री नंबर भी लोगों को दिया ताकि लोग नए आवेदन कर सकें और शिकायत दर्ज करा सकें. यह सुनना कितना सुखद है और खासकर तब जब अधिकांश लोग सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं. मुद्गिल का उदाहरण लोगों के लिए मिसाल बनेगा. ■

अधिकारियों को फटकार

कर्नाटक की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शमीम बानो अवैध खनन के मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन भौहें तब तन गईं, जब राज्य के कई आईएएस अधिकारी शमीम बानो के समर्थन में अपना मत प्रकट करने लगे. उनका कहना है कि अवैध खनन मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा बानो को गिरफ्तार नहीं किया जाना था. यही नहीं, कर्नाटक के आईएएस एसोसिएशन ने भी आरोपी के प्रति अपना समर्थन जता दिया. आईएएस एसोसिएशन के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशिक मुखर्जी हैं. इन बाबुओं ने स्पष्ट रूप से आरोपी शमीम बानो की कानूनी मदद करने का निर्णय भी ले लिया है. सार्वजनिक तौर पर बाबुओं का यह सौहार्द्र कर्नाटक हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया. मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के बावजूद आरोपी के प्रति एसोसिएशन के समर्थन पर कोर्ट ने हाल ही में सवाल खड़ा किया. कोर्ट की इस फटकार के बाद ऐसी उम्मीद है कि पुराने सहयोगियों के समर्थन को लेकर बाबू और उत्साहित होंगे.■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

गुप्ता प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ेंगे

1993 बैच के आईपीएस योगेश गुप्ता जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (कोलकाता आंचलिक कार्यालय) में विशेष निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

वर्मा विशेष सचिव बने

1979 बैच के आईएएस आलोक कुमार वर्मा गृहमंत्रालय में विशेष सचिव के तौर पर ज्वाइन करेंगे. आलोक वर्तमान में मिजोरम पुलिस के डीजीपी हैं.

चौधरी नये सीएमडी बनेंगे

एच.एल. चौधरी को राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक पद के लिए चुना गया है. चौधरी वर्तमान में भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवा में जीजीएम हैं.

विवेक कोयला मंत्रालय से जुड़े

1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस विवेक भारद्धाज कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाला है. भारद्धाज को कोयला मंत्रालय में नया पद सृजित करके राज्य कैडर से लाया गया है.

सारंगी भूमि संसाधन विभाग से जुड़ेंगे

1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस प्रभात कुमार सारंगी भूमि संसाधन विभाग से संयुक्त सचिव के रूप में जुड़ेंगे. उनको 1981 बैच के राजस्थान कैडर के आईएफएस सविता आनंद के स्थान पर नियुक्त किया गया है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

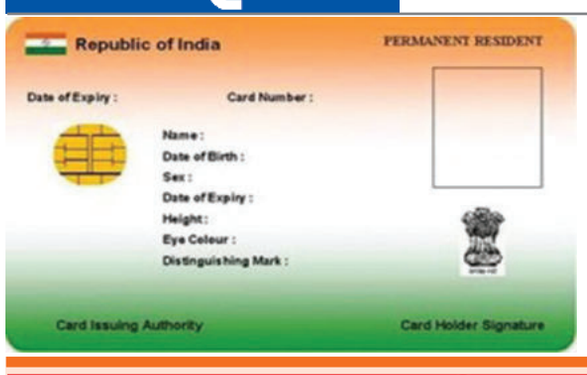

चौथी दुनिया शुरू से ही यूआईडी को जनता के लिए ख़तरा बता रही है. यह देश के लोगों के मानवाधिकार पर एक कुठाराघात है. इसके जरिये देश के नागरिकों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर विदेशी एजेंसियों के हाथ में सौंप देने की तैयारी है. सरकार अब तक इस परियोजना को लेकर रहस्यात्मक रुख अपनाए हुए है. आख़िर ऐसी क्या बात है, जिसे सरकार जनता से छुपाना चाहती है.

पार्ट–2

आधारहीन आधार कार्ड

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

डॉ. मनीष कुमार

यूआईडी यानी आधार के मामले में यूपीए सरकार का रवैया अजीबोग़रीब है. सरकार संसद के अंदर कुछ कहती है. संसद के बाहर मीडिया से कुछ और कहती है और अदालत के अंदर जाकर बिल्कुल ही अगल बात कहती है. सरकार की अलग–अलग एजेंसियां यह भ्रम फैलाती हैं कि यूआईडी हर सरकारी काम के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोर्ट में जाकर मुकर जाती हैं. सरकार से जब यह पूछा जाता है कि इस स्कीम पर कितने पैसे ख़र्च होगें, तो सरकार का जवाब बस इतना होता है कि सरकार ने अब तक तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर दिया है. यह आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इस स्कीम पर कितने ख़र्च होंगे. आधार के सर्वेसर्वा नंदन मनोहर नेलकेणी से जब यह पूछा गया कि क्या इस यूआईडी का ख़ुफ़िया विभाग या काउंटर इंटेलिजेंस जैसी एजेंसी से कोई रिश्ता है या नहीं, तो उनका जवाब था नो कमेंट्स. सवाल यह है कि यूआईडी यानी आधार को लेकर सरकार इतनी रहस्यात्मक मुद्रा में क्यों है? क्या छिपाया जा रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है?

कई सालों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआईए) ने विदेशी कंपनियों के साथ हुए समझौते को छिपा कर रखा. कई लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला. प्राधिकरण ने यह कभी नहीं बताया कि इसने एल–1 आईडेंटिटी सोल्युशन, एसेंचर और दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ क्या समझौता हुआ है. मामला सीआईसी तक पहुंचा और सीआईसी ने प्राधिकरण को यह आदेश दिया कि भारत सरकार के द्वारा किसी विदेशी कंपनी के साथ अगर कोई समझौता होता है तो वह भारत के लोगों की तरफ से होता है, इसलिए प्राधिकरण को आधार से जुड़ी जानकारियां देनी पड़ेंगी. इस आदेश के बाद सिविल लिबर्टी एक्टिविस्ट गोपाल कृष्ण को इन समझौते का क़ाग़ज़ात उपलब्ध कराए गए, लेकिन यहां भी प्राधिकरण ने एक धोखा कर दिया. उन क़ाग़ज़ातों में सारी चीज़ें हैं, लेकिन एल1 आईडेंटिटी सोल्युशन और एसेंचर के साथ किए क़रार का तकनीकी व व्यावसायिक हिस्सा ग़ायब है. अब सवाल उठता है कि इन क़रारों में ऐसी क्या बात है, जिसे छुपाया जा रहा है.

दरअसल, 1 सितंबर, 2010 को भारत और एसेंचर कंपनी में क़रार हुआ था. हालांकि, इस बात का ख़ुलासा नहीं किया गया कि एसेंचर सर्विस लिमिटेड एक अमेरिकी कंपनी की सहायक कंपनी है, जो आयरलैंड के डबलिन से ऑपरेट करती है. एल–1 आईडेंटिटी सोल्युशन भी एक अमेरिकी कंपनी है, जिसमें अमेरिका के ख़ुफ़िया और सैन्य अधिकारी इसके बोर्ड मेम्बर हैं और यह कंपनी अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के साथ काम करती आई है. अब इस कंपनी का फ्रांस के साफ्रान ग्रुप में विलय हो चुका है. देश में लोगों का सारा बायोमीट्रिक डाटा इन्हीं दोनों कंपनियों को सौंपा जाएगा, क्योंकि इन क़रारों के मुताबिक़ यूआईडी की डाटा का ऑपरेशन इन्ही कंपनियों के हाथ में है. हैरानी की बात यह है कि साफ्रान ग्रुप में फ्रांस की सरकार की हिस्सेदारी है और साथ–साथ अगले चालीस साल तक चीन के साथ इनकी पार्टनरशिप है. कहने का मतलब यह कि जो डाटा यूआईडी के नाम पर जमा किया जा रहा है, वह सुरक्षित नहीं है. यह डाटा अमेरिका, फ्रांस और चीन के हाथ लग सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे किसी और देश को नहीं बेचा जा सकता है. इन जानकारियों का ग़लत इस्तेमाल हो सकता है. इसका उदाहरण पाकिस्तान है. वहां भी यूआईडी की तरह पाकिस्तान के लोगों को परिचय पत्र दिया गया. वहां इसे नाड्रा कहा जाता है. बायोमैट्रिक जानकारियां ली गईं. पाकिस्तान की मूर्खता देखिए ये पूरी जानकारी अमेरिका को दे दी गई. इसके बदले में नाड्रा के चीफ मोहम्मद तारीक मलिक को इन देशों में काफ़ी पुरस्कार मिला. जिस तरह का आभामंडल भारत में नंदन नेलकेणी का है, वैसा ही पाकिस्तान के लोग मोहम्मद तारीक मलिक के बारे सोचते थे. अब हाल यह है कि पाकिस्तान के बारे में आईएसआई से ज्यादा सीआईए को पता रहता है. अमेरिका इन जानकारियों के चलते पाकिस्तान के लोगों पर नज़र रखने में कामयाब हो गया. अफ़सोस इस बात का है कि जो अवॉर्ड मोहम्मद तारीक मलिक को मिला, एक साल बाद वो हमारे नंदन नेलकेणी साहब को मिला है. मीडिया में यूआईडी का प्रचार जमकर होता है, अख़बार और टीवी को इससे पैसे मिलते हैं, इसलिए यूआईडी के इस डार्क साइड को कोई कुरेदने की कोशिश नहीं करता है. अफ़सोस इस बात का है कि यूपीए की सरकार को इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं है.

राज्यसभा में सरकार से एक सांसद ने सवाल पूछा कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए क्या यूआईडी अनिवार्य है? इस सावल के जवाब में केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने साफ़–साफ़ मना कर दिया कि नहीं, यूआईडी किसी भी योजना के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ठीक दो घंटे के बाद वो संसद के बाहर आए और मीडिया में यह बयान दे दिया कि नहीं–नहीं... फिलहाल यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में अनिवार्य किया जाएगा. वैसे यह सरकार एक ही मुंह से दो तरह की बातें करने में एक्सपर्ट है. यह आधिकारिक तौर पर तो यह कहने से बचती है कि यूआईडी को अनिवार्य किया जाएगा, लेकिन इसे पिछले दरवाज़े से लागू कराने में सतत प्रयास कर रही है. सरकार के हर विभाग, हर इलाके में यूआईडी को अनिवार्य घोषित किया जा रहा है. चाहे वो ट्रेन टिकट हो, गैस सिलिंडर हो, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो, यहां तक कि राशनकार्ड बनाने के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है या फिर कोशिश हो रही है, जो सरासर ग़ैरक़ानूनी है.

आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है. यह देश का अकेला कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. आज तक आधार योजना को हरी झंडी देना वाला क़ानून नहीं बना है, लेकिन हर दिन टीवी पर हमें दिखाया जा रहा है कि इतने करोड़ कार्ड बना दिए गए हैं. असलियत यह है कि यूपीए सरकार इस क़ानून को संसद में पास भी नहीं करा सकती है, क्योंकि संसदीय कमेटी ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. संसदीय कमेटी ने कहा है कि आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है. आधार के ख़िलाफ़ केस करने वाले स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज रहे हैं. जस्टिस के एस पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की है. इस पिटिशन पर देश के कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने सहमति दिखाई है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमीट्रिक्स को जमा किया जा रहा है. देश में मौजूद सारे क़ानूनों को खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून सिर्फ जेल मैन्युल में है. यह सिर्फ़ क़ैदियों का लिया जा सकता है. और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वो क़ैदी रिहा होगा, उसके बायोमीट्रिक्स से जुड़ी फ़ाइलों को जला दी जाएगा, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां जमा कर रही है और विदेश भेजने पर तुली है. ये गंभीर सवाल है, जिसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है. वैसे सांसद रमा जोयस ने 19.1.2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी. इस चिट्ठी में उन्होंने आधार योजना की संवैधानिकता पर सवाल उठाया था. इस चिट्ठी के जवाब में प्रधानमंत्री की भी चिट्ठी आई, लेकिन इसमें सिर्फ़ यह लिखा था कि आपकी चिट्ठी मिल गई है. सवालों के जवाब नहीं थे.

अब तक आधार को लेकर सरकार झूठ ही बोलती आई है. पहले दावा किया गया कि यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है. यह दावा भी झूठा निकला. कई नकली और फ़र्ज़ी यूआईडी कार्ड की ख़बर सामने आ चुकी है. ऐसी भी ख़बर आ चुकी है कि एक ही व्यक्ति ने कई यूआईडी कार्ड बना लिए हैं. निजी कंपनियों को पैसा कमाने के लिए देश की जनता पर प्रयोग करने का किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है. समझने वाली बात यह है कि कई देशों में अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के कहने पर इस तरह के पहचान पत्र की योजना शुरू की. जब ब्रिटेन में यह काम शुरु हुआ तो भारत में भी नंदन नेलकेणी ने इसे उदाहरण बना कर भारत में इसकी शुरुआत की, लेकिन जैसे ही उन देशों को पता चला कि यह योजना लोगों के सिविल राइट्स के लिए ख़तरनाक है तो उन्होंने इसे बंद कर दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ. निजी कंपनियों के साथ सांठगाठ कर इस योजना पर काम शुरू हो गया, वो भी बिना संवैधानिक वैधता के. सवाल यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को दुनिया भर में पुरस्कार मिले, इसके लिए क्या लोगों के अधिकार को ख़तरे में डाला जा सकता है. दरअसल, बात यहीं पर आकर रुक गई है, क्योंकि इस योजना को चालू रखने की न तो कोई दलील है, न कोई क़ानून है और न ही यह न्यायसंगत है. सरकार को यह जवाब देना होगा कि जब हमारे पास 16 विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र पहले से ही हैं तो 17 वें की क्या जरूरत है.

दरअसल, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को विदेशी दबाव के अंदर काम करने की लत लग गई है. निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ़ करना ही एक अच्छी सरकार की निशानी है. दरअसल, सरकार की मानसिकता ही दूषित हो चुकी है, इसलिए जनता का कल्याण ताक पर रख दिया गया है. कल यूआईडी योजना के अंदर ही कोई घोटाला निकले तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए. चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यूआईडी पर भी विवाद होगा, बहस होगी. राजनीतिक दलों को अपना स्टैंड साफ़ करना होगा कि क्या वो देश के लोगों की जानकारी को विदेशी कंपनियों व सरकारों को सौंपने के पक्ष में हैं या विरोध में. वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ा ख़ुश हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सुपरमैन नंदन मनोहर नेलकेणी राजनीति में आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां आईटी प्रोफेशनल की आबादी ज़्यादा है. अच्छे लोग राजनीति में आएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे लोग कौन हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर देश को अमेरिका, फ्रांस और इज़राइल की ख़ुफ़िया एजेंसियों के इशारे पर देश के लोगों की गोपनीय जानकारियां विदेश भेजना, देश की ग़रीब जनता को विदेशी कंपनियों को निगलने के लिए रास्ता बनाना अच्छाई है तो वर्तमान संसद में 167 दाग़ी सासंद क्या बुरे हैं? ■

manish@chauthiduniya.com

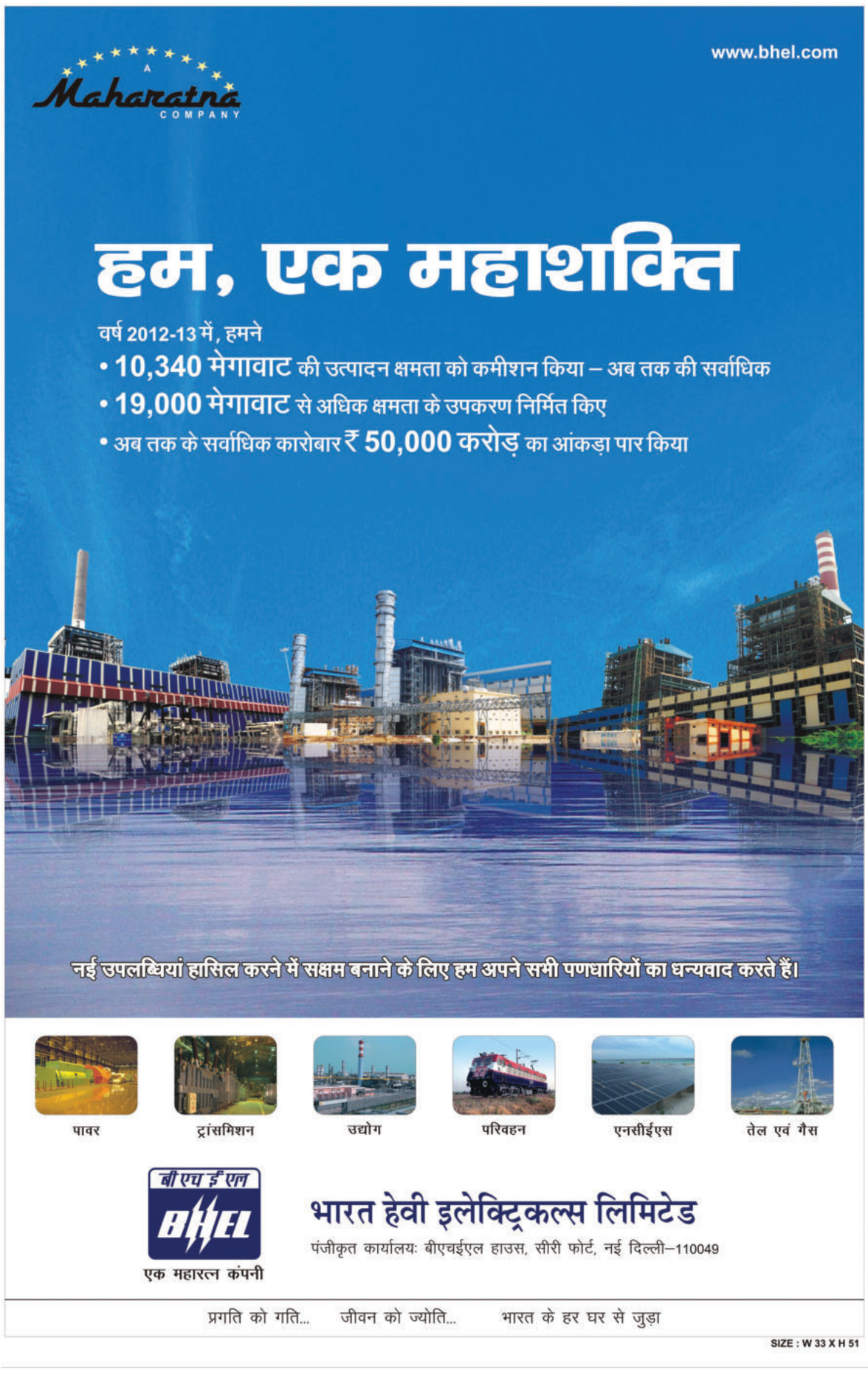

भाजपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यह बात भली–भांति जान रहे होंगे कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने के लिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से जो नाराज़गी मोल ली है, नतीजे ठीक–ठाक नहीं आने पर ये नेता उन्हें कहीं का नही छोड़ेंगे. भले ही राजनाथ की पीठ पर संघ का हाथ हो, लेकिन मोर्चे पर राजनाथ को ही कौशल दिखाना होगा.

उत्तर प्रदेश में तैयार है राजनीतिक जमीन

मोदी माया मुलायम का महाभारत

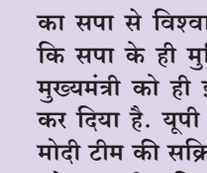

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में राजनीति की धारा पूरे देश से अलग बहती है. यहां पिछले दो दशकों से कोई भी चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया है. ऐसा ही नज़ारा इस बार भी देखने को मिलेगा. इसकी संभावनाएं प्रबल होने लगी हैं. सभी दल चाहते हैं कि वे मुख्य मुक़ाबले में रहें. इसके लिए साज़िशों और लोक–लुभावन वायदों का दौर चल रहा है. किसी को पुचकारा जा रहा है तो किसी को दुत्कारा जा रहा है. 20 करोड़ से अधिक जनता वाले प्रदेश को ओछी राजनीति ने खंड–खंड कर दिया है. अखिलेश सरकार की नाकामी और प्रदेश में फैलता जातीय–धार्मिक विद्वेष समाजवादी पार्टी के लिए ग्रहण बन गया है, जो आग सपा नेताओं ने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए लगाई थी, उस आग में सपा के ही हाथ झुलसने लगे हैं. मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा के बाद सूबे की सियासत में सफलता के लिए तमाम राजनीतिक दांव–पेंच आज़माए जा रहे हैं. मुजफ्फरनगर से सपा के लोकसभा प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री ने चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया है. अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा पर ड्रामेबाजी हुई, जिसके चलते सपा–भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगे और मुसलमानों का सपा से विश्वास हिला. बड़ी बात यह है कि सपा के ही मुस्लिम मंत्री आज़म ख़ान ने मुख्यमंत्री को ही इसके लिए कठघरे में खड़ा कर दिया है. यूपी में सधे हुए क़दमों के साथ मोदी टीम की सक्रियता बढ़ रही है. भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह के यूपी की ज़िम्मेदारी संभालते ही हिंदुत्व का ज्वार फिर उठ रहा है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के यूपी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. कांग्रेस द्वारा सपा–भाजपा को एक ही साथ खड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है. बसपा द्वारा अखिलेश सरकार की नाकामी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है. वोट बैंक की राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया तथा राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जो एक संप्रदाय तक ही सीमित रहा. ये ऐसे दांव हैं, जिसकी बदौलत हर पार्टी सियासत में एक–दूसरे को शिकस्त देने के सपने देख रहा है.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी की सक्रियता से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कान कुछ ज्यादा ही खड़े हो गए हैं. हालांकि, नरेंद्र मोदी की सक्रियता भाजपा को कोई सफलता दिलाएगी, इसमें संदेह ही है, क्योंकि मोदी गुजरात के विकास का नारा लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस सूबे की राजनीति में अब तक विकास कोई मुद्दा नहीं है. यहां पर अभी भी चुनाव जाति और धर्म के आधार पर लड़ा जाता है. यह महज संयोग नहीं है कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में नमो का नारा बुलंद किया, तब तक वहां पर अखिलेश सरकार सूबे की जनता को 104 दंगे अता कर चुकी थी और ये सभी दंगे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए. इतने दंगे न तो नरेंद्र मोदी के गुजरात में हुए, न ही उत्तर प्रदेश में ही भाजपा के शासनकाल में. दूसरे, नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के दौरान ही विहिप ने राममंदिर का मुद्दा उठाया और सपा सरकार के फैसलों के चलते माहौल गरमाने में उसे मदद ही मिली. एक तरह से देखा जाए तो भाजपा राममंदिर का सांप्रदायिक मुद्दा अब भी छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है. सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का विकास का नारा यूपी में मुद्दा बनेगा या फिर इस बार भी हिंदू–मुस्लिम और जात–पात ही चुनावी मुद्दे होंगे?

इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में मोदी के प्रवेश करते ही वहां पर दंगे शुरू हो गए. सूबे में मोदी के आने के पहले पूरे साल सांप्रदायिक माहौल बना रहा. मोदी के आने से भाजपा की बढ़त की संभावना देखते ही सपा भी अपने धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिक कार्ड खेलने पर आमादा है. मुजफ्फरनगर दंगों में सपा के आला नेताओं की संदिग्ध भूमिका, प्रशासन को पंगु करके उन्मादी जनता को उनके हाल पर छोड़ना और आरोपी विधायकों पर कार्रवाई न होने जैसी घटनाएं बताती हैं कि अगले चुनाव में सभी पार्टियां उन्हीं पुराने मुद्दों का सहारा लेकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेंगी.

सपा के कुछ प्रत्याशी तो बदले माहौल में सपा के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने तक से कतराने लगे हैं. मुजफ्फरनगर से सपा के घोषित प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमपाल सिंह ने दंगों के बाद टिकट वापस कर दिया है. इसी तरह से गोंडा के सपा उम्मीदवार नंदिता शुक्ला, जो अपने टिकट को लेकर काफी उत्साहित थी, बदले माहौल (दंगा और मोदी) में परेशान दिख रही हैं. उनके कुछ करीबी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की सपा से नाराजगी के बाद नंदिता किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में देखने का सपना पाल बैठी हैं. जब यह चर्चा आम हुई तो सपा आलाकमान ने उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कर यह घोषणा कराई कि वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी. कैसरगंज से सपा के उम्मीदवार बृजभूषण शरण के बारे में भी कुछ इसी तरह की चर्चा है. उनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वह अपने कुछ राजनीतिक क्षत्रिय दोस्तों के साथ दिल में कमल खिला रहे हैं.

भाजपा खेमे का ऐसी खबरों से उत्साहित होना गलत नहीं है. सब जानते हैं कि 2004 में भाजपा की केंद्रीय सत्ता में वापसी नहीं हुई तो इसकी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही था. अबकी बार प्रदेश भाजपा हिसाब बराबर कर देना चाहती है. भाजपा आलाकमान द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है. हालात बदलने के लिए यूपी से मोदी ही नहीं अमित शाह, उमा भारती जैसे हिंदुत्व के चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है. भाजपा साम–दाम–दंड–भेद, किसी भी तरह से यहां से लोकसभा में अधिक से अधिक सांसद भेजना चाहती है.

इसके पीछे कारण भी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यह बात भली–भांति जान रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने के लिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज से जो नाराजगी मोल ली है, नतीजे ठीक–ठाक नहीं आने पर ये नेता उन्हें कहीं का नही छोड़ेंगे. भले ही राजनाथ की पीठ पर संघ का हाथ हो, लेकिन मोर्चे पर राजनाथ को ही कौशल दिखाना होगा. उन्हें यूपी के हालात का भी अच्छी तरह से अंदाजा है. वैसे तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनने के बाद ही मोदी और राजनाथ सिंह के एजेंडे में उत्तर प्रदेश आ चुका था. उन्होंने अपने नजदीकी और विश्वासपात्र अमित शाह को प्रदेश का प्रभारी बनाकर इसके संकेत भी दे दिए थे, पर अब जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया है तो उनके लिए यह जिम्मेदारी और अधिक गंभीर हो गई है. जरा सी चूक उनको दिल्ली के ताज से दूर कर सकती है. वह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछले एक दशक से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है. सांगठनिक ढांचा चरमराया हुआ है. गुटबाजी चरम पर है. पुरानी पीढ़ी ने नई पौधों को आगे नहीं आने दिया है. पार्टी के कई वरिष्ठ और जमीन से जुड़े नेताओं ने एक तरह से पार्टी से किनारा कर लिया है.

मोदी अतीत से भी सीखना चाह रहे हैं. 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के गांधीनगर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक साथ चुनाव लड़कर दिल्ली में भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता खोला था. भले ही 13 दिन के लिए सही, भाजपा ने वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई जरूर. दोनों ही राज्यों में भाजपा को अच्छी संख्या में सीटें मिली थीं. बाद में अटल ने गांधीनगर से त्यागपत्र दे दिया था. संघ नेतृत्व ने जब मोदी के जरिये दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर भगवा सरकार स्थापित करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है तो यह चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या मोदी भी उसी राह पर चलते हुए गुजरात व उत्तर प्रदेश से एक साथ चुनाव लड़ेंगे? पार्टी के छोटे–बड़े सभी नेता इस सवाल का जबाव हां में देते हैं. कानपुर भाजपा के नेताओं ने तो प्रस्ताव तक पास करके दिल्ली भेज दिया है. वहीं लखनऊ–वाराणसी से भी मोदी का नाम सुर्खियों में है.

बात आंकड़ों की करें तो नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं नजर आते हैं. मोदी जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं. इसके विपरीत यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन यहां उसके सदस्यों की संख्या दस तक ही सीमित है. विधानसभा में भी वह तीसरे नंबर की पार्टी है. वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 1998 के लोकसभा चुनाव में 36.48 प्रतिशत वोट लेकर 57 सीटें पाने वाली भाजपा, 2002 में न सिर्फ वोट प्रतिशत में, बल्कि सीटों की संख्या भी नीचे गिरती चली गई. 2004 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मात्र 22.17 प्रतिशत वोट और 10 सीटें मिली थीं. विधानसभा के 2012 के चुनाव में पार्टी को लगभग 15.21 प्रतिशत वोटों से ही संतोष करना पड़ा. यह दयनीय स्थिति थी. उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास अभी 10 सीटें हैं. जाहिर है कि 40 का आंकड़ा छूने के लिए मोदी को इन सीटों को बरकरार रखते हुए 30 अन्य सीटों का इंतजाम करना होगा, जो सिर्फ उनके नाम से नहीं हो सकता. इसके लिए संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने, गुटबाजी पर विराम लगाने के अलावा जिताऊ प्रत्याशी तलाशने के अलावा राजनीतिक जमीन भी तैयार करनी होगी.

मुजफ्फनगर दंगों से यदि कोई सबसे अधिक आहत है तो वह सपा प्रमुख और खुद को प्रधानमंत्री की रेस में शामिल मानने वाले मुलायम सिंह यादव हैं. वह विधानसभा–2012 वाला प्रदर्शन लोकसभा में भी दोहराना चाहते थे, लेकिन प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, फिर चौरासी कोसी परिक्रमा पर विवादास्पद निर्णय और अब दंगों ने तो उनकी इच्छाओं पर आखिरी कील ठोंक दी. वह यहां तक कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मैं शामिल नहीं हूं. मुसलमानों के बीच सपा की विश्वसनीयता गिरने से मायावती को जरूर राहत मिली. वह डंके की चोट पर कहने लगी हैं कि उनके राज में मुसलमानों का बाल भी बांका नहीं होता था. भाजपा और सपा अल्पसंख्यकों को डरा रही हैं, ताकि दोनों के वोट बैंक मजबूत हो सकें. कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन 2012 में राहुल को नकार चुकी प्रदेश की जनता उन्हें अब भी गंभीरता से नहीं ले रही है. ■

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

भाजपा खेमे का ऐसी ख़बरों से उत्साहित होना ग़लत नहीं है. सब जानते हैं कि 2004 में भाजपा की केंद्रीय सत्ता में वापसी नहीं हुई तो इसकी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही था. अबकी बार प्रदेश भाजपा हिसाब बराबर कर देना चाहती है. भाजपा आलाक़मान द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कमर कस ली है.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर नरेंद्र मोदी की सक्रियता से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कान कुछ ज़्यादा ही खड़े हो गए हैं. हालांकि, नरेंद्र मोदी की सक्रियता भाजपा को कोई सफ़लता दिलाएगी, इसमें संदेह ही है, क्योंकि मोदी गुजरात के विकास का नारा लेकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस सूबे की राजनीति में अब तक विकास कोई मुद्दा नहीं है. यहां पर अभी भी चुनाव जाति और धर्म के आधार पर लड़ा जाता है.

दारुल उलूम की कोई प्रतिक्रिया नहीं

अल्पसख्यकों पर मजबूत पकड़ रखने वाला दारुल उलूम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़पोशी पर मुंह नहीं खोल रहा है. वहीं कई प्रमुख मुस्लिम संगठन जानना चाहते हैं कि मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों के लिए उनका क्या एजेंडा होगा. बात दारुल उलूम की है तो उसका साफ कहना है कि मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर वह कुछ नहीं कहना चाहेगी. उनकी संस्था मजहबी और गैर सियासी है. राजनीतिक मामलों पर हम अपनी राय नहीं देते हैं. दारुल उलूम के अशरफ उस्मानी कहते हैं कि हमेशा से ही हमारी संस्था द्धारा सियासी मामलों पर राय नहीं देने की परंपरा रही है. यहां बता देना जरूरी है कि कुछ समय पूर्व दारुल उलूम के एक मोहतमिम मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी को मोदी समर्थन के कारण अपना पद गंवाना पड़ा था. इसके बाद से उलेमा मोदी का नाम लेने से भी परहेज करते हैं. यह स्थिति तब है, जबकि आम मुसलमान उनकी तरफ काफी उम्मीदों के साथ देख रहा है. एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ समर्थन भी. राष्ट्रीय एकता अंबेडकर सोसायटी के संयोजक नवाब अख्तर ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में भाजपा केंद्र में अगली सरकार बनाने में सफल रहेगी. मुस्लिम मजलिस के प्रांतीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बदर काजमी ने कहा कि देश के मुस्लिमों ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधामनंत्री के रूप में सराहा और कबूल किया था. मुस्लिमों की अपेक्षा है कि मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा किरदार पेश करते हैं और उसमें सफल रहते हैं तो यह भाजपा की सियासत का सकारात्मक पहलू होगा. ■

तुलनात्मक रूप से भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा बाजी मारती दिख रही है. भाजपा ने अपनी विकास यात्रा पूरी कर ली है. रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव अभियान समिति बन गई है. छत्तीसगढ़ भाजपा, प्रत्याशियों का फ़ैसला अपने आधार पर कर रही है. नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट के मुताबिक, राज्य के सभी ज़िलों में आईटी सेल सक्रिय हो गई है. गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह रमन सरकार भी चुनाव को आईटी वार में तब्दील करने में लगी है.

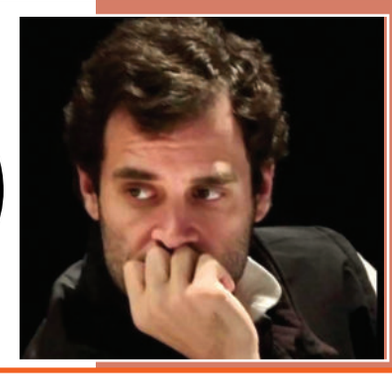

छत्तीसगढ़

भाजपा में उत्साह कांग्रेस निराश

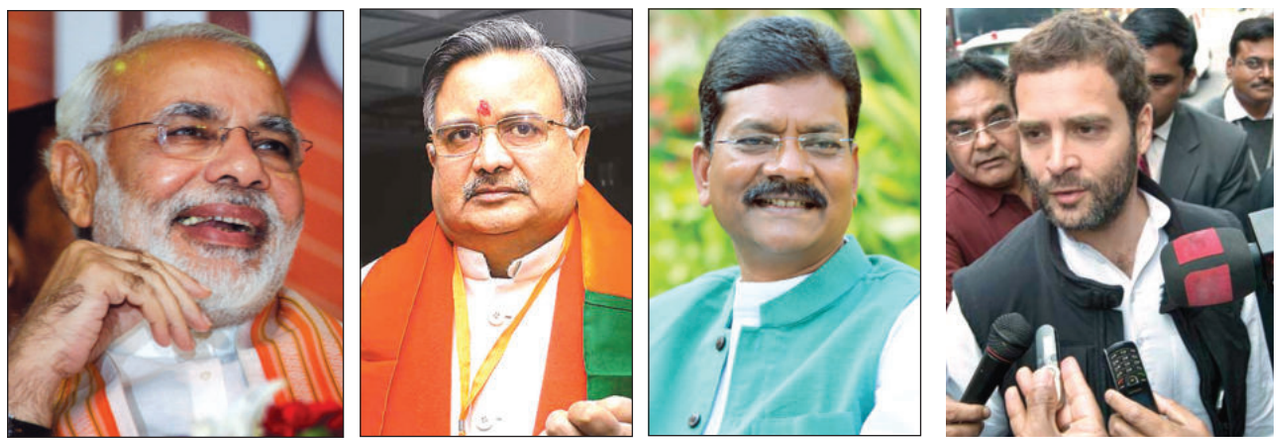

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वहां पर तीसरा विधानसभा चुनाव होना है. भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों की ही तरह रमन सिंह भी विकास का नारा देकर जनता का दिल जीतने की कोशिश में लगे हैं. इस चुनाव में भाजपा जहां तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ज़ोर लगाएगी, वहीं कांग्रेस भाजपा को मात देकर सत्ता में आने की कोशिश करेगी. फ़िलहाल चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा जहां बाज़ी मारती दिख रही है, वहीं कांग्रेसी आपसी कलह में उलझे हुए हैं. राज्य कांग्रेस से लेकर आलाकमान तक के क़द्दावर नेता अजीत जोगी को मनाने में जुटे हैं.

कृष्णकांत

जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह भाजपा व कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है. मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने का न सिर्फ़ सपना देख रही है, बल्कि वह इस अभियान में जी-जान से जुट भी गई है. रमन की विकास यात्रा पूरी हो गई है. एक महीने में अपने सिपहसालारों के साथ रमन गांव-गांव में घूमकर अपने विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाने के प्रयास में लगे हैं. रमन सिंह सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर जनता को संदेश दे चुके हैं. उनके सभी मंत्रियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में यात्रा आयोजित कर जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की. दो कार्यकाल सत्ता में रहने के बाद अपने विकास कार्यों और मौजूदा राजनीतिक माहौल को लेकर भाजपाई ख़ासे उत्साहित हैं. इसके उलट दस साल तक सत्ता से बाहर रहने वाले कांग्रेसी आपसी कलह में उलझे हुए हैं. प्रदेश के आला कांग्रेसी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं. अजीत जोगी कम महत्व मिलने से नाराज़ चल रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रयासरत हैं. छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुर्सी की आपसी खींचतान ने पार्टी में जहां निराशा का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं रमन सिंह के विकास ने नारे और मोदी की लहर की वजह से भाजपाइयों में उत्साह है.

हाल ही में रमन सिंह की विकास यात्रा की शुरुआत और अंत में मोदी की दो सभाएं रखी गईं. मोदी के लिए एक मॉडल लालकिला बनाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई. भाजपा छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन और विकास की स्थिति बेहतर है. विकास यात्रा के दौरान रमन सिंह ने जूता, साड़ी, लैपटॉप और साइकिल बांटकर भी जनता को लुभाने की कोशिश की. इसके उलट कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, जो झीरम घाटी नक्सली हमले के कारण स्थगित हो गई थी, दोबारा शुरू नहीं हो सकी. हालांकि, हमले के तुरंत बाद कांग्रेस ने कहा था कि यात्रा फिर वहीं से शुरू की जाएगी, लेकिन पार्टी के भीतर कलह के चलते ही यह यात्रा पूरी नहीं हुई.

हालांकि कांग्रेस को यह भरोसा है कि रमन सिंह के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों और झीरम घाटी नक्सली हमले के बाद वह चुनावी सफलता गांठने में कामयाब रहेगी. इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले मामले में रमन सिंह और उनके मंत्रियों पर करोड़ों रुपये घूस खाने के आरोप हैं. जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने एक सीडी जारी की, जिसमें प्रियदर्शिनी बैंक के तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा नार्को टेस्ट के दौरान यह दावा कर रहे हैं कि बैंक की चेयरमैन रीता तिवारी के आदेश पर उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह और चार अन्य मंत्रियों को उन्होंने एक-एक करोड़ रुपये दिए. कांग्रेस इस मामले को लगातार मुद्दा बनाकर बढ़त लेने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस को यह भी भरोसा है कि नक्सली हमले में नंदकुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल समेत आला पार्टी नेताओं की हत्या से उसे जनता की सहानुभूति मिलेगी. इसे भुनाने के लिए मारे गए नेताओं के बेटों को टिकट दिए गए हैं. नक्सली हमले मामले में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की संदिग्ध भूमिका के बावजूद पार्टी की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि उसके लिए रमन सरकार ज़िम्मेदार है. हालांकि, पार्टी न तो अभी तक ढंग से हमलावर हो सकी है, न ही अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकी है. पार्टी अभी 90 सीटों में से सिर्फ 40 पर ही प्रत्याशी तय कर सकी है, जिनमें ज़्यादातर नक्सल हमले में मारे गए नेताओं के परिजन हैं या फिर वे नेता हैं, जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है.

यदि तुलनात्मक रूप से भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा बाज़ी मारती दिख रही है. भाजपा ने अपनी विकास यात्रा पूरी कर ली है. रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव अभियान समिति बन गई है. छत्तीसगढ़ भाजपा प्रत्याशियों का फ़ैसला अपने आधार पर कर रही है. नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट के मुताबिक, राज्य के सभी जिलों में आईटी सेल सक्रिय हो गई है. गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह रमन सरकार भी चुनाव को आईटी वार में तब्दील करने में लगी है. मोबाइल, इंटरनेट-सोशल मीडिया के ज़रिये भी लोगों तक पहुंचने का उपक्रम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हो पाई है. मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देने की गरज़ से कलश यात्रा ज़रूर पूरी कर ली. अजीत जोगी के नाराज़ होने और उन्हें मनाने से लेकर पार्टी के प्रत्याशी चयन में उलझी पार्टी चुनाव समितियों के गठन और अन्य तैयारियों में मात खा रही है. पार्टी नेता एक-दूसरे के ख़िलाफ़ दिल्ली में मोर्चा संभाले हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के नक्सली हमले में मारे जाने के बाद अजीत जोगी अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, लेकिन चरणदास महंत को अध्यक्ष बना दिया गया. बाद में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद पर उन्होंने दावेदारी ठोंकी, लेकिन उसे भी पार्टी ने नकार दिया. इसके बाद से जोगी नाराज़ चल रहे हैं. पहले जोगी के अलग पार्टी बनाने की अफवाहें सामने आईं. फिर उनमें और पार्टी अध्यक्ष चरणदास महंत में सुलह होने की बातें कही गईं. इसी बीच पार्टी से अलग प्रचार के लिए जोगी एक्सप्रेस चलाई गई. महीने भर से पार्टी जोगी प्रकरण में उलझी हुई है. इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. हाल ही में पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद को एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही जोगी ने झिड़क दिया था और हरिप्रसाद की नाराज़गी के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. महंत जोगी को मनाने के लिए रायपुर से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं. पार्टी आलाकमान को भी यह पता है कि यदि जोगी पार्टी से किनारा कर लेते हैं तो कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है. कह सकते हैं कि पार्टी की चुनावी गतिविधियां जोगी के फ़ैसलों पर टिकी हुई हैं. पार्टी छिटपुट कार्यक्रम करके एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़मीनी तौर पर बिना मज़बूती से मैदान में उतरे रमन सरकार को हटा पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा. अब पार्टी जगदलपुर में राहुल गांधी की अगुआई में अजीत जोगी, चरणदास महंत, बीके हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष रवींद्र चौबे और मोतीलाल वोरा समेत सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटी है. पार्टी आलाकमान की ओर से जोगी को मनाने का उपक्रम जारी है और जोगी फ़िलहाल चुपचाप हैं. वे कांग्रेस के अंतिम फ़ैसले का इंतजार कर रहे हैं. ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान जोगी को लोकसभा चुनाव लड़ाकर प्रदेश की राजनीति से दूर रखना चाह रहा है, जबकि जोगी प्रदेश की राजनीति में अपना जमा-जमाया पैर हिलने नहीं देना चाहते. अब अगर फ़ैसला जोगी के पक्ष में नहीं रहा तो जोगी अलग रास्ता भी अख़्तियार कर सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

हमने दिखाई राह दूसरों के अनुसरण के लिए

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्षीय अभिभाषण, 17 सितम्बर, 2013

"लगभग 26,000 दक्ष और वचनबद्ध 'टीम एनटीपीसी' सदस्यों की ओर से मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारे संपूर्ण समर्पण और अथक प्रयासों का आश्वासन देता हूँ।"

प्रिय शेयरधारक साथियों,

आपकी कंपनी की इस 37वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है।

पिछले दिनों अनेक चुनौतियों के बीच आपकी कंपनी की वृद्धि में पर्याप्त तेजी आने से मुझे यह आश्वासन देने का बढ़ावा मिला है कि कंपनी आने वाले वर्षों में अपनी वृद्धि जारी रखेगी और वैश्विक तथा राष्ट्रीय व्यापार के क्षितिज में उठने वाले मुद्दों के बावजूद तरक्की करेगी।

आर्थिक चिंताओं के बीच ठोस वृद्धि का दृष्टिकोण

पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं सहित भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट के अब तक सामने आते आघातों की पकड़ में है जो 2008 में शुरू हुआ था। वैश्विक संकट से निपटते हुए आरंभिक नम्यता दर्शाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी अधोगामी तल में पहुंच गई है।

एनटीपीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने संकट की कुछ तरंगों से निपटने में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दिखाए गए लचीलेपन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।

मेरे पास इसे मानने का सशक्त आधार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चाहे तूफान का सामना करे, यह एनटीपीसी जैसे उद्यमों की सहायता से वांछित वृद्धि प्रक्षेपण दोबारा प्राप्त कर लेगी। वर्तमान आर्थिक मंदी के बावजूद देश को अपनी वृद्धि की गति दोबारा अर्जित करने के लिए कार्य करना है। एनटीपीसी इस प्रक्रिया के वृद्धि प्रेरकों में से एक होगी।

सभी अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच ऐसे कुछ बहुत सशक्त कारक हैं जो विद्युत क्षेत्र और आपकी कंपनी के लिए एक मज़बूत वृद्धि दृष्टिकोण रखते हैं :

- बढ़ती जनसंख्या में वृद्धि, जीवन के स्तर में वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण भारत में बिजली की मांग बढ़ना अनिवार्य है।
- भारत की विशाल विद्युत क्षमता की आवश्यकता 2032 तक 9 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 960 गीगावॉट और 8 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि के लिए 778 गीगावॉट के रूप में आकलित की गई है।
- विद्युत क्षेत्र में बड़े निवेश की संकल्पना की गई है (12वीं योजना में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए। 12वीं योजना का क्षमता वर्धन लक्ष्य लगभग 88,500 मेगावॉट है।)

2012–13 में ठोस समग्र निष्पादन का स्तर ऊपर उठाना

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी के निष्पादन से प्रदर्शित हुआ है कि हम वृद्धि और उत्कृष्टता के उच्च स्तर तक पहुंच रहे हैं। समग्र ठोस निष्पादन के कुछ विशेष बिन्दु हैं :

- एक अकेले वर्ष में अब तक के उच्चतम स्तर तक 4,170 मेगावॉट क्षमता का वर्धन।
- 8,521 मेगावॉट के कार्य के लिए संविदाएं सौंपना।
- पिछले वर्ष से 24.58 प्रतिशत से अधिक 19,925.53 करोड़ रु. का पूंजी व्यय (कैपेक्स)।
- अखिल भारतीय 69.95 प्रतिशत पीएलएफ की तुलना में 6 स्टेशनों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ के साथ 83.08 प्रतिशत औसत पीएलएफ।
- पिछले वर्ष के पीएटी में 36.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12,619.39 करोड़ रु. का अब तक का सबसे अधिक कर पश्चात निवल लाभ (पीएटी)।
- आज शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 5.75 प्रति शेयर (कुल 4,741.16 करोड़ रुपए) का अब तक का सबसे अधिक लाभांश।
- भारत सरकार की 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए "बिक्री प्रस्ताव" के दौरान 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (11,469.39 करोड़ रु.) की रकम संचित की गई, जिसे विदेशी निवेशकों से आने वाली 45 प्रतिशत राशि के साथ 1.7 गुना ओवर सबस्क्राइब किया गया।
- कैबिनेट द्वारा लंबे समय से लंबित डेसू की 2520.07 करोड़ रु. की राशि के भुगतान को मंजूरी।

तीव्र क्षमता वर्धन, उच्च दक्षता और प्रतिस्पर्द्धी लागत पर विद्युत के माध्यम से क्षेत्र का स्थायी नेतृत्व

आप जानना चाहेंगे कि कंपनी ने अपनी शुरूआती 10,000 मेगावॉट क्षमता के निर्माण में 10 वर्ष का समय लिया, अगले 10,000 मेगावॉट क्षमता के निर्माण में 11 वर्ष का समय लिया और तीसरे ब्लॉक में 10,000 मेगावॉट क्षमता के निर्माण में 7 वर्ष का समय लिया तथा 40,000 मेगावॉट से अधिक की कंपनी बनने के लिए अंतिम लगभग 10,000 मेगावॉट के निर्माण में केवल 3 वर्ष और 3 माह का समय लिया। इस प्रकार पिछले 39 माह में 41,184 मेगावॉट की कुल क्षमता का लगभग एक चौथाई भाग कमिशन किया गया है।

आपकी कंपनी अपने आकार और दक्षता के संदर्भों में भारतीय विद्युत क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है और यह अत्यंत उच्च दक्षता कारक दर्शाते हुए देश की कुल क्षमता में 18.44 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ कुल विद्युत उत्पादन में 27 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है।

आपकी कंपनी भारत में विद्युत की अल्पतम लागत वाली उत्पादक कंपनी है जिसका समग्र प्रशुल्क 2.96 रुपए प्रति यूनिट है।

आपकी कंपनी 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 32 में विद्युत पहुंचाती है। जिससे यह भौगोलिक दृष्टि से विविध ग्राहक आधार के साथ सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विद्युत कंपनी बन गई है।

निवेश के स्तरों में अपार वृद्धि और भावी सशक्त वृद्धि

आपकी कंपनी का वर्षवार कैपेक्स 2009–10 में लगभग 10,500 करोड़ रुपए के स्तर से 2012–13 में लगभग 20,000 करोड़ रु. हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 19,926 करोड़ रुपए (स्टैंड एलोन) के रिकॉर्ड कैपेक्स की तुलना वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 15,994 करोड़ रुपए के साथ करने पर इसमें लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी के पास निविदा अधीन लगभग 5,000 मेगावॉट और 20,579 मेगावॉट की क्षमता निर्माणाधीन है।

विश्वसनीय और किफायती विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घ अवधि ईंधन सुरक्षा

आपकी कंपनी में 31.03.2009 तक कमिशन की गई 23,895 मेगावॉट यूनिटों के लिए दीर्घ अवधि कोयला आपूर्ति करार (सीएसए) है। इस अवधि के दौरान कमिशन की जाने वाली 13,510 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता के लिए (3890 मेगावॉट संयुक्त उद्यम क्षमता सहित) 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान आपकी कंपनी की व्यापार इकाइयों में कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों के साथ सीएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोयला खनन परियोजनाओं का विकास

आपकी कंपनी को दो बिलियन टन के अनुमानित भौगोलिक आरक्षित भंडार के साथ चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। पिछले समय में एनटीपीसी को आवंटित 3.7 बिलियन टन के अनुमानित भौगोलिक भंडारों के साथ इसमें 6 कोयला खनन ब्लॉक जोड़े गए, इन नए खनन ब्लॉकों से आपकी कंपनी का कोयला आरक्षित भंडार 5.7 बिलियन टन तक पहुंच गया है।

वृद्धि की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ ग्रह के प्रति संवेदनशीलता

विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी लाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा किए गए समग्र उपायों से 34 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोका गया है, जिसमें से 2.15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वर्ष 2012–13 में रोकी गई है।

आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वच्छ उत्पादन

औसतन सब क्रिटिकल (उपक्रांतिक) संयंत्रों में लगभग 35 प्रतिशत रूपांतरण दक्षता स्तरों से आपकी कंपनी सीपत में (3×660) मेगावॉट यूनिटों से आरंभ करते हुए अपने विद्युत स्टेशनों में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाकर 38–39 प्रतिशत दक्षता स्तर तक पहुंच गई है।

आपकी कंपनी की योजना 13वीं योजना के दौरान 45 प्रतिशत की रेंज में रूपांतरण दक्षता स्तर तक पहुंचने की है।

यह उल्लेखनीय है कि रूपांतरण दक्षता में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2.5 प्रतिशत की कमी होती है।

आप यह जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) और बीएचईएल के सहयोग से अत्यधिक रूपांतरण दक्षता के साथ उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत उच्च ग्रेड की सामग्री के विकास में संलग्न है।

यह प्रयास पूरी दुनिया में किए जाने वाले तीन प्रयासों में से एक है, अन्य दो अमेरिका और जापान में हैं।

संवेदनशीलता के साथ और सचेत रहकर पर्यावरण का प्रबंधन

पर्यावरण संबंधी अन्य प्रयासों के अलावा लगभग 19 मिलियन पेड़ लगाने से बनी अपार हरित संपदा से हमें एनटीपीसी पावर स्टेशनों में और इनके आस-पास पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने में सहायता मिली है।

समावेश के साथ वृद्धि

आपकी कंपनी की वृद्धि कार्यनीति के साथ मूल संरचना विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, जल आपूर्ति, सेनिटेशन, महिला सशक्तीकरण आदि के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयासों के साथ सामाजिक समावेश एक मार्गदर्शक विशेषता हैं। आपकी कंपनी व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से रोज़गार परकता को बढ़ावा देने में निवेश करती है। इन प्रयासों से परियोजना स्थलों के आस-पास रहने वाली आबादी को लाभ मिला है।

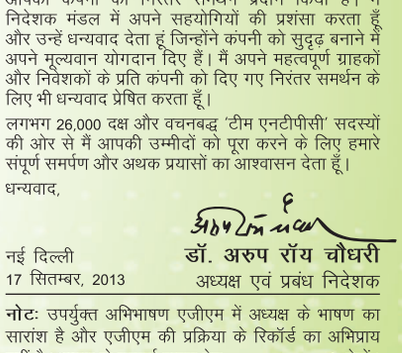

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए आपकी कंपनी का प्रयास सशक्त जुनून और प्रयोजन के साथ जारी है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लाभ मिला है।

शासन के साथ वृद्धि, नैतिकता के साथ उत्कृष्टता

आपकी कंपनी द्वारा नैगम शासन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। यह यहां पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य बनाए जाने से पहले इसे बढ़ावा देने के अनेक कदम उठाए गए हैं। इस सक्रिय मार्ग से इसे अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं तथा इससे भी महत्वपूर्ण, स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही निवेशकों सहित पणधारियों के बीच इसकी एक ठोस कॉर्पोरेट छवि बनी है।

टीम एनटीपीसी की सामूहिक वचनबद्धता

कर्मचारियों की उत्पादकता मानव – मेगावॉट अनुपात वर्ष दर वर्ष में लगातार कमी और प्रति कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि से प्रदर्शित होती है। आपकी कंपनी एक मात्र ऐसी पीएसयू है जो प्रतिष्ठित सर्वेक्षणों में 10 सर्वोत्तम नियोक्ताओं के बीच स्थान रखती है।

आभार अभिव्यक्ति

मैं भारत सरकार, खासतौर पर विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों, हमारे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपकी कंपनी को निरंतर समर्थन प्रदान किया है। मैं निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कंपनी को सुदृढ़ बनाने में अपने मूल्यवान योगदान दिए हैं। मैं अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों और निवेशकों के प्रति कंपनी को दिए गए निरंतर समर्थन के लिए भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ।

लगभग 26,000 दक्ष और वचनबद्ध 'टीम एनटीपीसी' सदस्यों की ओर से मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारे संपूर्ण समर्पण और अथक प्रयासों का आश्वासन देता हूँ।

धन्यवाद,

नई दिल्ली
17 सितम्बर, 2013

डॉ. अरुप रॉय चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोटः उपर्युक्त अभिभाषण एजीएम में अध्यक्ष के भाषण का सारांश है और एजीएम की प्रक्रिया के रिकॉर्ड का अभिप्राय नहीं है। भाषण के सम्पूर्ण पाठ्य हेतु ***www.ntpc.co.in*** देखें।

एनटीपीसी NTPC
एक महारत्न कम्पनी

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 वेबसाइट : www.ntpc.co.in

कांग्रेस नेतृत्व ने सी.पी. जोशी की इन्हीं बग़ावती हरक़तों से तंग आकर उन्हें मंत्री पद से हटाया, ताकि वे कमज़ोर हो सकें. सी. पी. जोशी को बिहार का प्रभारी बना कर भेज दिया गया. बावजूद इसके, उन्होंने राजस्थान में अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, पर उनके तिकड़मों का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला. सी.पी. जोशी मेवाड़ को अपनी जागीर मानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के टिकट बंटवारे में जोशी के बजाय गिरिजा व्यास और रघुवीर मीणा की ही भूमिका रही.

गिरिजा व्यास

राजस्थान कांग्रेस

हार के कारण

रूबी अरुण

यूं तो राजस्थान की सियासी फ़िज़ा में अशोक नहीं ये आंधी है, मारवाड़ का गांधी है, के नारे गूंजने लगे हैं और कांग्रेस हाईकमान ने भी यह घोषित कर रखा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी अशोक गहलोत की ही होगी, पर हकीकत ये है कि कांग्रेस और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वास्तव में हालात इतने सुखद नहीं हैं. राजस्थान से संबंध रखने वाले सभी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के बीच ज़बरदस्त धींगामुश्ती मची हुई है. खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सी.पी. जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सी.पी. जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज के तरीके की खुलेआम आलोचना करते नज़र आते हैं. पिछले दिनों जयपुर में हुई चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने ही जोशी और अशोक गहलोत एक–दूसरे से भिड़ गए. जोशी ने बड़े ही कड़े लहजे में कहा कि सीएम साहब आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, सभी को साथ लेकर चलेंगे तो ही सत्ता में आ सकेंगे, वरना हार जाएंगे. जोशी ने अशोक गहलोत को यह सलाह भी दे डाली कि चुनाव जीतने के लिए आपको जहर का घूंट पीकर फैसले लेने होंगे. जोशी की सलाह और उनके व्यवहार पर अशोक गहलोत भड़क उठे. उन्होंने तुरंत जोशी पर पलटवार करते हुए कटाक्ष के लहजे में कहा कि मैं जहर का घूंट पीता हूं, आपकी तरह गुस्सा नहीं करता, तभी तो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं. दोनों के बीच तकरार इस हद तक बढ़ने लगी कि प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव गुरदास कामत को बीच–बचाव करना पड़ा.

दरअसल, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां कांग्रेस के कम से कम पांच बड़े कद्दावर नेता हैं. उनके नाम हैं एआईसीसी के महासचिव सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास और शीशराम ओला, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट. कमाल की बात ये है कि सभी के सभी कबीलाई नेता हैं. जितेंद्र सिंह मेवात से बाहर कोई खास प्रभाव नहीं रखते. सीपी जोशी और गिरिजा व्यास का प्रभाव भी मेवाड़ के बाहर जाकर ख़त्म हो जाता है. राजेश पायलट जिस तरह गुर्जरों के एकछत्र नेता हुआ करते थे, वैसा प्रभाव उनके बेटे सचिन पायलट नहीं पैदा कर पाए. सचिन पायलट की दुश्वारी यह भी है कि वे अभी तक अपने ही क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के किसी नेता का पूरे प्रदेश में प्रभाव है तो वे हैं अशोक गहलोत, पर अशोक गहलोत के साथ विडंबना यह है कि उनकी सरकार के मंत्रियों के कार्यकलाप और सांसदों से लेकर कार्यकर्ताओं तक में आपसी खींचतान है, जिसके खराब नतीजे विधानसभा चुनाव के पहले ही नज़र आने लगे हैं, जो अशोक गहलोत की फिर से ताजपोशी की राह में रोड़ा बन रहा है.

केन्द्रीय मंत्री शीशराम ओला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें राज्य में कांग्रेस की बिगड़ी स्थिति से अवगत भी करा दिया है. जानकारी के मुताबिक, शीशराम ओला ने सोनिया गांधी को साफ़ तौर पर यह कह दिया है कि राजस्थान में नवम्बर में चुनाव होने हैं और गांवों में पार्टी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. राज्य सरकार सही रणनीति बना कर काम नहीं कर रही है. राज्य के मंत्रियों के कामकाज का तरीका ठीक नहीं है और पार्टी में गहरा मतभेद है. इन सारी वज़हों से कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है. अगर पार्टी को जीत दिलानी है तो उसे अभी से ही कड़े फैसले लेने होंगे.

इसी के तहत चुनाव समिति ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देने, पिछला विधानसभा चुनाव 20 हजार से अधिक वोटों से हारने वाले नेताओं, लगातार दो चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं देने और अन्य दलों से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को टिकट नहीं देने के फैसले पर अमल किया.

पार्टी कार्यकर्ताओं की आपसी कलह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए तब और भी मुश्किलें खड़ी कर दीं, जब राज्य के दो सौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारियां तय की जाने लगीं, क्योंकि उनके विरोधी खेमे के नेता सी.पी. जोशी ने अपना सारा जोर अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में लगा दिया. चूंकि ज़ाहिर तौर पर उम्मीदवार तय करने की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा, गिरिजा व्यास, सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.चन्द्रभान ने निभाई. अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भरोसा प्राप्त है. लिहाज़ा, उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी सहमति अशोक गहलोत की ही रही. फिर भी कहते हैं न की सियासत तो बस सियासत ही होती है. चाहे जितनी नीतियां बना लीजिए, जितने भी नियम लागू कर दीजिए. यह जानते हुए भी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वरदहस्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्राप्त है, सीपी जोशी ने अपना विरोध जारी रखा.

कांग्रेस नेतृत्व ने सी.पी. जोशी की इन्हीं बगावती हरक़तों से तंग आकर उन्हें मंत्री पद से हटाया, ताकि वे कमज़ोर हो सकें. सी पी जोशी को बिहार का प्रभारी बना कर भेज दिया गया. बावजूद इसके, सी.पी. जोशी ने राजस्थान में अपनी कोशिशें नहीं छोड़ीं, पर उनकी तिकड़मों का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला. सी.पी. जोशी मेवाड़ को अपनी जागीर मानते हैं. इसके बाद भी उस क्षेत्र के टिकट बंटवारे में सी.पी. जोशी की बजाय गिरिजा व्यास और रघुवीर मीणा की भूमिका ज्यादा रही. कांग्रेस को मेवाड़ से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं. ऐसे में अगर कांग्रेस इस क्षेत्र में सी.पी. जोशी को ज्यादा महत्व देती तो वह वहां सी.पी. जोशी के मुकाबले खुद कमज़ोर पड़ जाती और अशोक गहलोत भी असमंजस की स्थिति में होते, जो कांग्रेस कतई नहीं चाहती थी. यही वज़ह रही कि टिकट बंटवारे के वक़्त कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली से राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी के रूप में गुरुदास कामत को खासतौर पर अशोक गहलोत की ढाल बना कर भेजा, ताकि वे मुखालफत करनेवाले कांग्रेस के नेताओं से सख्ती से निपटें. कामत को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है. मकसद यह भी रहा कि सभी नेताओं तक यह संदेश चला जाए कि कोई भी अशोक गहलोत को कमज़ोर करने वाला कदम न उठाए. कांग्रेस आलाकमान के सभी एहतियाती कदमों के बाद भी प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच की खटास ख़त्म नहीं हो पा रही है .

शीशराम ओला सरीखे बेहद वरिष्ट नेता और केन्द्रीय मंत्री भी गाहे–बगाहे अशोक गहलोत की मुखालफत कर रहे हैं. वैसे भी राजस्थान की राजनीति में शीशराम ओला जाटों के बड़े प्रभावशाली नेता और अशोक गहलोत के ज़बरदस्त विरोधियों में शुमार होते हैं. जब 2009 के चुनावों के बाद ओला केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, तब अशोक गहलोत ने उनकी राह में टांग फंसा दी थी और उन्हीं के क्षेत्र शेखावाटी के सीकर से सांसद और जाट नेता महादेव सिंह खंडेला को केंद्र में राज्यमंत्री बनवा दिया था. शीशराम ओला को और कमज़ोर करने की नीयत से अशोक गहलोत ने ओला के गृह जिले झुंझुनू के रहने वाले ओला विरोधी कांग्रेस नेता डॉक्टर चंद्रभान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवा दिया था, तब से अभी तक अशोक गहलोत और शीशराम ओला के बीच छत्तीस का आंकड़ा है. यह बात अलग है कि बाद में शीशराम ओला ने कांग्रेस आलाकमान को अपनी शक्ति का अंदाजा कराया और केंद्र में मंत्री बन गए, पर उनकी टीस नहीं गई. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यकीनन अशोक गहलोत राजस्थान में सबसे बड़े कद के नेता हैं और उन्हें कमोबेश जनता का भरोसा भी मिला हुआ है. राजनीति में कोई ऐसा पद नहीं रहा, जिस पर गहलोत काबिज़ न हुए हों. वे दो बार सीएम, चार बार केंद्र में मंत्री, पांच बार सांसद, दो बार विधायक, दो बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के साथ एआईसीसी के महासचिव भी रहे. समय–समय पर अपनी सरकार की योजनाओं को जनता को समझाने–बताने के लिए निकाली गई उनकी यात्राओं ने जनता के दिलों में उनकी जगह भी बनाई. सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी उनके सामर्थ्य और उनके साथ की जनशक्ति को समझा और महत्व दिया.इसी के बूते कांग्रेस प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाने का सपना भी संजोए बैठी है, पर अपनी ही पार्टी के नेताओं की असंतुष्टि भीतरघात का काम कर रही है, जो कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीत की राह दुश्वार कर सकती है. ■

केन्द्रीय मंत्री शीशराम ओला ने सोनिया गांधी को साफ़ तौर पर यह कह दिया है कि राजस्थान में नवम्बर में चुनाव होने हैं और गांवों में पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है. राज्य सरकार सही रणनीति बना कर काम नहीं कर रही है. राज्य के मंत्रियों के कामकाज का तरीक़ा ठीक नहीं है और पार्टी में गहरा मतभेद है. इन सारी वजहों से कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है.

डॉ. सीपी जोशी

अशोक गहलोत

शीशराम ओला

नमो नारायण मीणा

गुरुदास कामत

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां कांग्रेस के कम से कम पांच बड़े क़द्दावर नेता हैं. उनके नाम हैं एआईसीसी के महासचिव सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास और शीशराम ओला, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट. कमाल की बात ये है कि सभी के सभी क़बीलाई नेता हैं. जितेंद्र सिंह मेवात से बाहर कोई ख़ास प्रभाव नहीं रखते. सी.पी. जोशी और गिरिजा व्यास का प्रभाव भी मेवाड़ के बाहर जाकर ख़त्म हो जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए मोरारका फ़ाउंडेशन की ओर से एक योजना ऑर्गेनिक टिफिन भी चलाई जा रही है. इस योजना के तहत छात्र, नौकरीपेशा लोग, अस्पतालों या कचहरी में आने वाले लोगों तक ऑर्गेनिक टिफिन पहुंचाया जाता है और उनसे 1200 रुपये महीने लिए जाते हैं. ज़ाहिर है आर्गेनिक खेती से तैयार टिफिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण यह योजना भी सफलतापूर्वक चल रही है.

महिला सशक्तिकरण

सफलता की ओर बढ़ते क़दम

मोरारका फ़ाउंडेशन ने राजस्थान के शेख़ावटी की महिलाओं की दशा और दिशा में सुधार के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महत्वपूर्ण पहल की थी, उसके सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. शेखावटी की महिलाएं घर की चहारदीवारी में रहकर भी परिवार के भरण–पोषण के लिए पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं. यह अनुकरणीय है.

वसीम अहमद

मोरारका फ़ाउंडेशन जैविक खेती को विकसित करने के साथ–साथ महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ऐसी महिलाएं, जो काम करने की इच्छुक हैं, उनके लिए फाउंडेशन ने स्वयं सहायता समूह बनाकर रोज़गार का नया अवसर उपलब्ध कराया है. ख़ास बात यह है कि इस फ़ाउंडेशन से तमाम समुदायों की महिलाएं बिना किसी भेदभाव के लाभ उठा रही हैं.

मोरारका फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहले स्वयं सहायता समूह की स्थापना 1993 में की गई, जिसका उद्देश्य दूर–दराज़ के गांवों में ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं को रोज़गार से जोड़ना है. शेख़ावटी के नवलगढ़ और झुंझुनू क्षेत्र के घोड़ीवारा कलां, मोहब्बत श्री, जाटवाली, मुकुंदगढ़, घोड़ीवालाख़ुर्द, अजीतपुर, तीतरा, मझाइ, ढानी, नाहिर सिंघानी, ढगाल, बलवंतपुरा, चौलासी, कसीरो और सांगासी के अलावा अन्य गांवों में यह काम तेज़ी से जारी है. मोरारका फाउंडेशन को सन् 2000 में नाबार्ड प्रोजेक्ट मिला, जिसके तहत 100 स्वयं सहायता समूह बनाए गए. बैंक में उनके बचत खाते खुलवाए गए. आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को बैंक से क़र्ज़ दिलवाए गए. ये समूह लोगों में इतने लोकप्रिय हुए कि ग़रीब महिलाएं इससे तेज़ी से जुड़ने लगीं. अब इस समूह की संख्या 600 तक पहुंच गई है, जिसके हज़ारों सदस्य बन चुके हैं.

मोरारका फाउंडेशन द्वारा नवलगढ़, उदयपुर, झुंझुनूं और सीकर में जारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट बनाना, बूंदी, बंधेज, फूल, गोटे बनाना, बूंटी, दरी, पेपर बैग, पायदान, झूला, पापड़, मंगूड़ी बनाने जैसे काम शामिल हैं.

मोरारका फ़ाउंडेशन ने महिलाओं को पेपर बैग बनाने के काम से जोड़ा. इस समय लगभग 120 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं, जिनकी आय प्रतिमाह 1000 से 1500 रुपये तक है. मोरारका फाउंडेशन ने इन महिलाओं को बंधेज बनाने, सब्ज़ियां बेचने जैसे कार्यों से भी जोड़ा, ताकि वे अपनी आय से खुद की जरूरतें पूरी कर सकें. फाउंडेशन इन महिलाओं को क़र्ज़ भी देता है. महिलाओं को अगर अपने काम को बढ़ाने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है तो स्वयं सहायता समूह उन्हें शेख़ावटी ग्रामीण बैंक से क़र्ज़ दिलाने में मदद करता है. 1993 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो महिलाओं को दो हज़ार रुपये का क़र्ज़ उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के उत्साह और कारोबार में मुनाफ़े को देखते हुए बैंक ने इस राशि को लाखों में देना शुरू कर दिया है.

अभी हाल ही में नाहिर सिंघानी गांव में बैंक ने 22 समूहों को 50 हज़ार से 2 लाख रुपये तक कुल 45 लाख रुपये क़र्ज़ महज़ एक प्रतिशत सूद पर दिया है, जबकि इससे पहले कुल 133 स्वयं सहायता समूहों से लगभग 2510 महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं, जिन्हें बैंक से 95 लाख 74 हज़ार रुपये का कर्ज़ दिलवाया गया और इंटरलोन एक करोड़ 20 लाख रुपये का दिया गया. इस राशि को समूह से जुड़ी ज़रूरतमंद महिलाओं को आवश्यकतानुसार दिया जाता है. मुकुंदगढ़ की कमला देवी गणपति स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. इस समूह में 14 सदस्य हैं. कमला देवी की एक सहेली संतोष भी इसी समूह की सदस्य हैं. कमला देवी कहती हैं कि 20 मई, 2011 को उन्होंने समूह से 50 हज़ार का क़र्ज़ लेकर एक कीराना की दुकान खोली और जिससे उन्हें मासिक 6 हज़ार रुपये की आमदनी होने लगी. इस मुनाफ़े से वह वह क़र्ज़ की किस्त भी देती हैं और घर का ख़र्च भी चलाती हैं. इसके बाद उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने 11 सितंबर, 2013 को 80 हज़ार रुपये का कर्ज़ लेकर दुकान में थोड़ी बढ़ोत्तरी कर ली. वे कहती हैं कि आज मोरारका फाउंडेशन की मेहरबानी से उनके घर में ख़ुशहाली आ गई है.

केसरो गांव में चल रहे माताजी स्वयं सहायता समूह में 13 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षा शांति देवी हैं. शांति देवी ने अपने समूह का खाता मुकुंदगढ़ मंडी शेख़ावटी ग्रामीण बैंक में खुलवाया. समय–समय पर समूह ने बैंक में पैसे जमा करवाए. शांति देवी ने बैंक मैनेजर को अपने समूह की आमदनी के बारे में विवरण दिया और गांव आकर समूह की समीक्षा करने के लिए कहा. समूह के साथ मीटिंग के बाद बैंक मैनेजर ने समूह के तीन सदस्यों को एक लाख रुपये का बैंक लोन दिया. शांति देवी ने 40 हज़ार रुपये में एक गाय ख़रीदी और उसका दूध बेचकर बैंक का क़र्ज़ चुका दिया. दूसरी सदस्य सोनम और संतोष ने 30–30 हज़ार रुपये का क़र्ज़ लिया, जिससे अपने बेटे को नर्सिंग का कोर्स करवाया.

नवलगढ़ में गणपति स्वयं सहायता समूह है. इसमें मोरारका फ़ाउंडेशन की ओर से 16 महिलाओं को बचत खाता और इंटरलोन के बारे में बैठक में जानकारी उपलब्ध कराई गई. समूह की सदस्यों में एक भागवती देवी भी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं. समूह की अध्यक्षा रजनी देवी ने भागवती देवी को 50 हज़ार का लोन दिया. इस लोन से भागवती देवी ने छोटी सी दुकान खोली. इस काम में उन्हें असल पूंजी के अलावा 1000 रुपये की कमाई हुई. इसके बाद भागवती देवी ने आईटीआई में नंबर आने पर स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए समूह से 20 हज़ार रुपये का कर्ज़ लिया, जिसे समय पर चुका भी दिया. भागवती देवी कहती हैं कि समूह की सहायता से आज उनका जीवन पूरी तरह समृद्ध है. इसी प्रकार नवलगढ़ के वार्ड नंबर 22 में कोमली देवी के घर पर मोरारका फाउंडेशन की ओर से महिलाओं की बैठक हुई. बैठक में 13 महिला सदस्य शामिल हुईं. इन सदस्यों में संतोष देवी की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी. वे सदस्यों की मीटिंग में हर महीने 100 रुपये जमा करने लगीं. आखिरकार संतोष अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने लगीं.

सायरा बानो, जो नाहिर सिंधानी की बैठक में उपस्थित थीं, एक समूह की महासचिव हैं. वे मोरारका फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए स्वयं सहायता समूह को घर–परिवार के विकास के लिए महत्वपूर्ण क़दम बताती हैं. दिलवर सिंह, जो इसी गांव के एक किसान हैं, कहते हैं कि पहले घर का सारा ख़र्च उनकी कमाई पर निर्भर था, लेकिन जब से उनकी पत्नी इस समूह से जुड़ी हैं, छोटे–मोटे काम घर में ही करके अच्छी कमाई कर लेते हैं. किसान वर्जन लाल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह ने कुछ महिलाओं का एक समूह बना दिया है, जो हर महीने 110 रुपये जमा करती हैं. एक वर्ष बाद कुछ राशि जमा हो गई तो समूह ने ग्रामीण बैंक से लोन दिलवा दिया, जिससे मेरी पत्नी ने अपना काम बढ़ा लिया. अब उनकी पत्नी अच्छी आमदनी कर लेती हैं. इसी गांव के अशोक शर्मा ने कहा कि इस समूह से जुड़ने के बाद मेरी पत्नी को अपनी और बच्चों की छोटी–मोटी आवश्यकताओं के लिए मुझसे पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. वह ख़ुद ही अपने कमाये हुए पैसे से यह सब करती हैं.

इसके अलावा मोरारका फाउंडेशन की ओर से साझा किचन की भी एक योजना चलाई जा रही है. वर्तमान में लगभग 40 ऐसे साझा रसोई चलाई जा रही हैं, जिनमें गांव वालों के लिए खाना तैयार किया जाता है. हर रसोई में 3 महिलाओं को लगाया जाता है. प्रत्येक महिला 4 परिवार के लिए खाना तैयार करती हैं और बदले में उन्हें प्रत्येक परिवार की ओर से प्रतिदिन 10 रुपये दिए जाते हैं. प्रत्येक रसोई में एक हेड निर्धारित होती हैं, जो उनके लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे गैस सिलेंडर आदि की व्यवस्था करती हैं और इसका वेतन मोरारका फ़ाउंडेशन की ओर से दिया जाता है. इस योजना से पहले महिलाएं लकड़ी और उपलों पर खाना बनाया करती थीं, जिस कारण ईंधन पर 1500 से 2 हज़ार तक की लागत आती थी और तरह–तरह की परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन अब उनका काम केवल एक सिलेंडर की क़ीमत में चल जाता है.

महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए मोरारका फ़ाउंडेशन की ओर से एक योजना ऑर्गेनिक टिफिन भी चलाई जा रही है. इस योजना के तहत छात्र, नौकरीपेशा लोग, अस्पतालों या कचहरी में आने वाले लोगों तक ऑर्गेनिक टिफिन पहुंचाया जाता है और उनसे 1200 रुपये महीने लिए जाते हैं. ज़ाहिर है आर्गेनिक खेती से तैयार टिफिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण यह योजना भी सफलतापूर्वक चल रही है.

ये सभी ऐसे काम हैं, जिनसे अधिकतर महिलाएं जुड़ी हुई हैं. जो लड़कियां इस प्रकार के काम करना पसंद नहीं करती हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी मोरारका फ़ाउंडेशन ने कुछ योजनाएं बनाई हैं. अब इन योजनाओं से पढ़ी–लिखी और नये जमाने की लड़कियां लाभ उठा रही हैं. 2010 में मोरारका फाउंडेशन ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की थी, जो अब शेख़ावटी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं. इस सेंटर में काम करने के लिए इन लड़कियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है. इस सेंटर से किसानों को खेती की जानकारियां भी दी जाती हैं. ये लड़कियां स्थानीय भाषा में कृषकों को खेती के बारे में समझाती हैं और उनकी समस्या का हल बताती हैं. अगर ऐसी समस्या सामने आ जाए, जिसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है तो पूछने वाले का नाम और नंबर लिख लिया जाता है और फिर उसका विवरण मुख्यालय से लेने के बाद उसके नंबर पर संपर्क करके उक्त हल के बारे सूचित किया जाता है.

कॉल सेंटर से जुड़ी लड़कियों को आर्थिक, शैक्षणिक लाभ तो हो ही रहा है, उनकी हिचकिचाहट भी दूर हो रही है. कॉल सेंटर से जुड़ी कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें पढ़ने के बाद घर में बैठा दिया गया था, लेकिन जब से मोरारका फाउंडेशन ने उन्हें कॉल सेंटर पर काम करने का अवसर दिया तो उसके बाद उन्हें लगने लगा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं. मोरारका फाउंडेशन ने जहां आम महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वयं सहायता समूह लाइन के द्वारा रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं, वहीं विकलांग लोगों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया है. फाउंडेशन ने विकलांग लोगों के लिए सोलर लालटेन की व्यवस्था की है. ये विकलांग लोग इन लालटेनों को चार्ज कर लेते हैं और जिन्हें आवश्यकता होती है, वह इनसे किराये पर ले जाते हैं. शादी के अवसरों पर भी इन लालटेनों का अच्छा इस्तेमाल होता है. सोलर लालटेनों के लिए घोड़ीवाला ख़ुर्द, कोलसिया, कटरासर और इसके आस–पास के क्षेत्रों में 25 सेंटर बनाए गए हैं, जहां से ज़रूरतमंदों को लालटेनें उपलब्ध कराई जाती हैं. एक लालटेन के लिए 10 रुपये किराये पर लिए जाते हैं. इस प्रकार इन विकलांगों को रोज़गार मिल जाता है.

मोरारका फाउंडेशन ने महिलाओं में रोज़गार को विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी महत्वपूर्ण काम किया है. गांव की महिलाओं को पर्यटकों को गाइड करने का प्रशिक्षण दिया जाता है. राज्य की सैंकड़ों महिलाओं को इस काम का प्रशिक्षण दिया गया है. लिहाज़ा, जब कोई पर्यटक यहां आता है तो उन्हें गांव की खुली हवा, ऑर्गेनिक खेती और हरियाली बहुत प्रभावित करती है. इससे आकर्षित होकर वे दोबारा यहां आना चाहते हैं. पर्यटकों से जो आमदनी होती है, उससे ये महिलाएं अपने घर–परिवार के विकास में हिस्सेदारी निभाती हैं. ■

मोरारका फाउंडेशन द्वारा नवलगढ़, उदयपुर, झुंझुनूं और सीकर में जारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट बनाना, बूंदी, बंधेज, फूल, गोटे बनाना, बूंटी, दरी, पेपर बैग, पायदान, झूला, पापड़, मंगूड़ी बनाने जैसे काम शामिल हैं. मोरारका फ़ाउंडेशन ने महिलाओं को पेपर बैग बनाने के काम से जोड़ा. इस समय लगभग 120 महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं, जिनकी आय प्रतिमाह 1000 से 1500 रुपये तक है.

feedback@chauthiduniya.com

कमल मोरारका

जो बंटवारा चाहते हों उन्हें मत चुनिए

आप जनता की भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते. लोगों को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश एक क्षुद्र सोच है, जो कि लंबे समय तक काम नहीं कर सकती. मैं मानता हूं कि देश का युवा अब जागेगा और यह तय करेगा कि केवल वही लोग चुने जाएं, जो ज़िम्मेदार हों.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगे कई मायनों में अलग हैं. भारत में वर्षों से छोटे-बड़े स्तर पर सांप्रदायिक टकराव होते रहे हैं. कई बार इन टकरावों ने बड़ा घृणित रूप अख़्तियार कर लिया है. जैसे अहमदाबाद, जमशेदपुर व कुछ अन्य जगहों पर, लेकिन मुज़फ़्फ़रनगर दंगा इन सबसे अलग है. सबसे पहले, तो यह कोई हिंदू-मुस्लिम के बीच का मसला नहीं है. यह टकराव जाटों और मुसलमानों के बीच का है, जोकि पिछले कई दशकों से मुज़फ़्फ़रनगर के गांवों में साथ-साथ रह रहे हैं. उनके बीच पहले किसी तरह का कोई विवाद या मन-मुटाव नहीं हुआ. दूसरे, अहमदाबाद, जमशेदपुर या मुंबई जैसे शहरों में हुए दंगों से अगर तुलना करें, यहां पर स्थिति एकदम अलग है, क्योंकि इन दंगों में लोगों को सुरक्षा की तलाश में गांवों से बाहर शहर की ओर भागना पड़ा. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था.

ऐसा क्यों हुआ? मैं किसी भी जांच के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तो एकदम स्पष्ट है कि इन दंगों के पीछे राजनीतिक दलों का ही हाथ है. आम धारणा है कि हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने असामाजिक तत्वों को मुस्लिमों पर निशाना साधने के लिए उकसाया है. साथ ही धारणा यह भी है कि उत्तर प्रदेश में यहां की सरकार मुस्लिमों को सुरक्षा में देने में असफल रही है. यह स्थिति बड़ी ही दुखद है. हम सभी प्रशासनिक गतिविधियों से वाकिफ़ हैं. कहीं पर भी अगर दंगे हों और प्रशासन सजग हो तो वह दो घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते. और वह भी तब, जबकि दंगा बड़े पैमाने पर हो. यह दंगा कोई बड़ा दंगा नहीं था, फिर भी हज़ारों लोगों को अपने गांव छोड़कर और ज़रूरत का समान सिर पर लादकर शहर की ओर भागना पड़ा. हमेशा की तरह एक बार फिर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ग़ैर-ज़िम्मेदाराना ही रही.

अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दंगाग्रस्त इलाक़ों का दौरा न करते, तो विरोधी कहते कि वे तो उन इलाक़ों में गए ही नहीं. अब जबकि उन्होंने उन इलाक़ों का दौरा किया, तो भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक पर्यटन की संज्ञा दे रही है. क्या मुसलमानों को समाज से अलग कर दिया जाए? या बीजेपी यह कहना चाहती है कि मुसलमान प्रताड़ित होते रहें, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए और कोई उनके पास न जाए. क्या देश के प्रधानमंत्री को वहां जाकर हालात का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? वास्तव में बीजेपी अब अपना असली रंग दिखा रही है. नरेंद्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना, जोकि खुद ही अपने को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं, यह भी समूचे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन जब कोई मुश्किल में पड़े मुसलमानों से मिलने के लिए जाता है, तो आप उसे सांप्रदायिक पर्यटन कहते हैं. इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी एक ख़राब छवि के तौर पर उभर कर आई है. उत्तर प्रदेश के एक विधायक संगीत सोम, जिनके ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के कारण एफ़आईआर दर्ज हुई है, वह टीवी पर कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी किसी को नहीं उकसाया. आप चाहें, तो मेरे भाषणों की जांच कर सकते हैं. मैंने कभी कोई उत्तेजक वक्तव्य नहीं दिया. उनकी बात सही हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अब थोड़ी अलग नीतियों पर चल रही है. अपने भाषणों में वे कोई ऐसी बात नहीं कहते, जिस पर आपको कोई आपत्ति हो, लेकिन कार्यशैली अलग है. वे ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदू-मुस्लिमों को विभाजित करे. जो आक्रामक हो और मुसलमानों को प्रताड़ित करे. वे मुसलामन विरोधी तस्वीरों और पोस्टर के वितरण को बढ़ावा दे रहे हैं. यह कहना बहुत आसान है कि आप मेरे भाषणों पर गौर करिए, उन्हें रिकॉर्ड करवा लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जोकि किसी के लिए अपमानजनक हो, लेकिन साथ ही वे ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं. मैं उस जिलाधिकारी की बात पर हैरान हूं. एक अधिकारी टीवी पर बातचीत के दौरान कहता है कि आज़म ख़ान ने हमें आज्ञा नहीं दी, नहीं तो हम ज़रूर कार्रवाई करते. यह कोई तरीक़ा हुआ? ऐसे अधिकारी को सरकारी सर्विस नहीं करनी चाहिए. हां, यह बात सही है कि कई बार राजनीतिक दबाव होता है, लेकिन किसी नागरिक का जीवन उस दबाव से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे अधिकारी जोकि सरकारी दबाव नहीं झेल सकते, वे अधिकारी ऐसे संवेदनशील इलाक़ों में काम नहीं कर सकते.

जहां तक मेरी जानकारी है, मुज़फ़्फ़रनगर ऐसे दंगे का कभी भी गवाह नहीं रहा और वो भी खासकर गांवों में. मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री इस दिशा में क्या क़दम उठाएंगे, लेकिन यह सबसे ज़रूरी समय है कि वे संबंधित लोगों, उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ-साथ एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भाजपा से भी बात करें. आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगला चुनाव हिंदू-मुस्लिम के आधार पर लड़ा जाए. बीजेपी आख़िर क्या चाहती है?

मुझे लगता है कि अब जब आगामी लोकसभा चुनावों को तक़रीबन सात महीने बचे हैं, तब माहौल बद से बदतर होता जाएगा. मेरा मानना है कि तीसरे मोर्चे के नेताओं, जैसे-नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक को अब आगे आना होगा और एक मज़बूत फ्रंट बनाना होगा, जहां सांप्रदायिक ताक़तों का बोलबाला न हो. दुर्भाग्य से कांग्रेस को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी हुई है. बावजूद इसके, कोई ग़ैर-सांप्रदायिक सरकार सत्ता में आ सकती है, अगर आख़िरी वक़्त तक इस दिशा में प्रयास किए जाएं. तीसरे मोर्चे की सरकार ही संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित कर सकती है. लोग इस पर गौर नहीं करते कि भले ही राजनीतिक दल अलग-अलग हों, लेकिन संविधान तो एक ही है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी संविधान का अनुपालन किया था और उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी कि देश में मुस्लिम सुरक्षित रहें.

बेशक गोधरा कांड हुआ और प्रधानमंत्री व भाजपा नरेंद्र मोदी को हटाने में विफल रही. वास्तव में तब आडवाणी जी ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने मोदी को बचाया था. आज वे आडवाणी जी के ही विरोध में खड़े हो गए. सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आप एक सरकार को अंध-राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं चला सकते. देश को सिद्धांतों पर चलना चाहिए और सिद्धांतों पर चलने का फल एक दिन में नहीं मिल सकता. हर कोई जल्दी में दिख रहा है और चुनावी माहौल इतना ख़राब होता जा रहा है कि यह काफ़ी दुखद स्थिति होगी, अगर देश जलने लगता है. सभी को बुद्धिमानी के साथ काम करना होगा. अगर मोदी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए. आप जनता की भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते. लोगों को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश एक क्षुद्र सोच है, जो कि लंबे समय तक काम नहीं कर सकती.

लोगों का मानना है कि देश की 60 से 70 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से कम आयु के लोगों की है. देश में युवाओं की संख्या बढ़ रही है. मैं मानता हूं कि देश का युवा अब जागेगा और यह तय करेगा कि केवल वही लोग चुने जाएं, जो ज़िम्मेदार हों. ग़ैर-ज़िम्मेदार लोग, जो अंध-राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं और संप्रदायों में बंटवारा करना चाहते हों, उन्हें नहीं चुनना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस क्रूरता को प्रोत्साहन मिल रहा है

ठाकुर दास बंग

आजकल आंदोलनों या इस तरह की चीजों को दबाने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों का अधिकाधिक नृशंसता से इस्तेमाल करने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति हो गई है. अक्सर उन्हें एकदम ग़ैरक़ानूनी ढंग से पेश आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. उदाहरण के लिए 1989 में उड़ीसा में विद्यार्थी आंदोलन के दौरान भुवनेश्वर में होने वाले एक प्रदर्शन को विफल करने के लिए विद्यार्थी की तरह दिखाई पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को भुवनेश्वर आने वाली ट्रेन पर चढ़ने से रोका गया और बस या ट्रेन से आए विद्यार्थियों को पुलिस गाड़ियों में भर-भर कर उन्हें भुवनेश्वर से बीस या तीस किलोमीटर रास्ते से दूर जगहों में उतार दिया गया. यह सब ग़ैरक़ानूनी था. दिल्ली में एशियाई खेल-कूदों के विरुद्ध सिख-प्रदर्शन की धमकी को भी विफल करने के लिए ऐसी ही चालों का इस्तेमाल किया गया.

भागलपुर में विचाराधीन क़ैदियों की आंख फोड़े जाने की घटना तो बदनाम हो गई है. सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री को इसके बारे में फाइलों के जरिए छह महीने पहले से खबर थी, लेकिन वह उन्हें दबाए बैठे रहे. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को विफल करने की भरसक कोशिश की. भागलपुर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट, जिसने इस क्रूरता के प्रति मानवीय रुख अख़्तियार किया, सरकारी कोप का शिकार बने. उन्हें मामूली आरोपों के आधार पर मुअत्तल कर दिया गया. नक्सलवादी और डाकू बताकर नकली मुठभेड़ द्वारा लोगों के मारे जाने की घटनाएं काफ़ी प्रकाश में आ चुकीं हैं. पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज नामक संगठन ने नाम और पतों के साथ 1229 ऐसे लोगों की सूची प्रकाशित की है जो छह राज्यों में 1989 से अब तक मारे जा चुके हैं. ज्यादातर राज्यों में यह एक सामान्य पद्धति बन गई है, लेकिन ऐसे कानून भी बने हैं, जिनके अनुसार ऐसी हत्याएं कानूनी हैं. ऐसे एक क़ानून का उदाहरण सामने है. अशांत क्षेत्र (विशेष शक्ति) क़ानून ऐसा है, जिसके अनुसार पुलिस एवं फौज़ी लोगों को किसी पूछताछ या क़ानूनी कार्रवाई की गिरफ़्त में आए बिना लोगों को मारने और उनके मकान आदि नष्ट करने का अधिकार है. इन शक्तियों का असम, मणिपुर, और मिजोरम में खुल कर इस्तेमाल हो रहा है. पुलिस एवं फौजियों द्वारा जवान लोगों को मकान से बाहर खींच कर लाए जाने और उन्हें मार डाले जाने की भयावह रपटें मौजूद रही हैं. वास्तव में मणिपुर की स्त्रियां अपने लड़कों और भाइयों की इतनी बुद्धिहीन हत्याओं के विरुद्ध अपने को संगठित करती हैं.

दूसरे क़ानूनों में भी पूलिस के हाथ में मनमाने अधिकार दे दिए हैं. मध्य प्रदेश में एक डाकू उन्मूलन क़ानून है, जिसके अनुसार पुलिस किसी भी ऐसे आदमी को पकड़कर चार महीने के लिए हवालात में बंद कर सकती है, जिसके ऊपर उसे शुबहा हो कि वह डाकुओं से मिला है या उनकी मदद कर रहा है. यह क़ानून राज्य के 11 ज़िलों में लागू है. जिसका नतीजा है कि डाकू-समस्या के मुक़ाबले पुलिस आतंक कहीं अधिक बढ़ गया है. हज़ारों निर्दोष आदमी गिरफ़्तार हुए हैं और पैसा न देने वालों को हिरासत की धमकी देकर पुलिस लाखों रुपये बनाती रही है. केवल छतरपुर ज़िले में ऐसे आठ सौ आदमी गिरफ़्तार किए गए थे, लेकिन जब उनका मामला ज़िला जज के सामने आया तो वे सबके सब छोड़ दिए गए.

एक भारतीय वन क़ानून है जिसका 1980 में प्रारूप तैयार हुआ था और जो पार्लियामेंट के सामने किसी भी समय आ सकता है. विधेयक में प्रावधान है कि जंगल विभाग के अफसर उस किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे वे जंगल को हानि पहुंचाने वाला मानते हों, लेकिन स्वयं उनके ख़िलाफ़ कोई जांच या कार्रवाई नहीं होगी. क़ानूनी सूत्रों के अनुसार ऐसी कार्रवाई में मार डालना भी शामिल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भागलपुर में विचाराधीन क़ैदियों की आंख फोड़े जाने की घटना तो बदनाम हो गई है. सबसे बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री को इसके बारे में फाइलों के जरिये छह महीने पहले से खबर थी, लेकिन वह उन्हें दबाए बैठे रहे. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को विफल करने की भरसक कोशिश की. भागलपुर जेल के सुपरिटेंडेंट, जिसने इस क्रूरता के प्रति मानवीय रुख अख़्तियार किया, सरकारी कोप का शिकार बने. उन्हें मामूली आरोपों के आधार पर मुअत्तल कर दिया गया.

पाठकों की दुनिया

सरकार की खोखली नीति

राजकोषीय और चालू घाटे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी कटौती के लिए जिन उपायों की घोषणा की है, उनसे उसके लचीलेपन का पता चलता है. नई भर्तियों और पांच सितारा होटलों में होने वाली सरकारी बैठकों, अधिकारियों की एक्जिक्यूटिव श्रेणी में विमान यात्राओं पर रोक लगाने से क्या सरकारी खर्चों में कोई कमी आ जाएगी? यह सरकार की गलतफहमी है. वित्त मंत्रालय ने एक पत्र जारी करके इन उपाओं के बारे में जानकारी दी, जिनके जरिए योजनागत खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. आर्थिक सलाहकारों को यह भी पता होना चाहिए कि सरकार ने पहले भी ऐसे ही उपाय किए थे, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ. सरकरी खर्चे को रोकने के लिए, रिक्त पदों पर नई भर्तियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. यह बेरोजगारी का मार झेल रहे युवाओं के प्रति सरकार की एक और निष्क्रियता का उदाहरण है. सरकार शायद अपने दिन-प्रतिदिन हो रहे घोटालों पर रोक लगाती, तो शायद यह संकट आता ही नहीं. सरकार जानती है कि उसने पहले भी कई ऐसे उपाय किए हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार ने केवल जनता को दिखाने के लिए यह खोखले उपाय किए हैं, जिससे लोगों को लगे कि सरकार अनावश्यक खर्च के प्रति कितनी गंभीर हैं. सरकार कब तक लोगों को मूर्ख बनाती रहेगी. अब तो सरकार को समझ में आ जाना चाहिए की जनता उसके सारे कारनामों से वाकिफ है.

-धर्मेंद्र, बनारस

दंगों की राजनीति

उत्तर प्रदेश में दिन-प्रतिदन दंगों की खबरें आती रहती हैं, जिससे सरकार की निष्क्रियता का पता चलता है. राजनीतिक पार्टियां वोटों के फायदे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं. कांग्रेस और अन्य पार्टियां मुजफ्फरपुर में हुए दंगों को भाजपा और सपा के बीच मैच फिक्सिंग करार दे रहीं है. सरकार को चाहिए कि दंगों में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन पीड़ितों को लाभ पहुंचाने का काम करे न कि उसका राजनीतिक लाभ उठाए. एक टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन में जिस प्रकार सपा सरकार में मंत्री आजम खां का नाम आया है कि उन्होंने ही हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने के लिए कहा और जो हो रहा उसे होने दो, ऐसा पुलिस को आदेश दिया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस स्टिंग आपरेशन को एक सोचा समझा एजेंडा बता रहे हैं, जो साजिश के तहत किया गया है. अखिलेश ने यह नहीं बताया कि आजम खां ने ऐसा नहीं कहा था. उत्तर प्रदेश सरकार बार-बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए-नए बहाने अपनाती रहती है. सरकार पर जो आरोप लगे हैं अब वह जल्दी नहीं धुलने वाले सरकार को अपनी छवि सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उसे बेहतर करना होगा, तभी उसकी छवि लोगों के बीच सुधर पाएगी और जनता के बीच सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जागेगा. वोटों की राजनीति के लिए राजनीतिक पार्टियां दंगों की राजनीति करने से बाज नहीं आती. यह पहली बार नहीं कि किसी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है ऐसे कई बार और कई पार्टियों पर दंगे का दाग लग चुका है, यह घिनौना खेल कब तक ऐसे ही चलता रहेगा?

-राजकुमार सिंह, पटना

आडवाणी की नाराजगी

नरेंद्र मोदी को भाजपा का चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने तक भाजपा के पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी खबरें आ रही थीं. आडवाणी कुर्सी की मोह में नरेंद्र मोदी के नाम का विरोध कर रहे थे. पहले उन्होंने जदयू के बहाने नरेंद्र मोदी की दावेदारी को रोकना चाहा, लेकिन जदयू ने भाजपा का साथ छोड़ दिया. उसके बाद आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के विरोधियों के सहारे मोदी की खिलाफत करते रहे. राजनाथ सिंह ने आडवाणी को दरकिनार करते हुए मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो आडवाणी को लगा कि अब यदि वह नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, तो उनकी ही छवि को नुकसान पहुंचेगा. आडवाणी ने इस पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली घर के उद्घाटन के बाद आडवाणी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी की जमकर तरीफ की. अब आडवाणी को भी समझ में आ गया है, जो लोकप्रिय होता है, वही सबसे बड़ा नेता होता है.

-नीरज तिवारी, दिल्ली

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे काफ़ी कुछ सीख देते हैं. पहले यह कहा जा रहा था कि मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे बिना किसी आर्थिक कारण के हो गए. यह भी कहा गया कि मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इतने ज़्यादा फैले. और यह भी कहा गया कि यहां पर हिंदूवादी ताक़तें ज़्यादा प्रबल हैं, इसीलिए दंगे हुए. इस देश में दंगों की रिपोर्टिंग जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा की, उनमें एम. जे. अकबर अभी जीवित हैं. उदयन शर्मा हमारे बीच से चले गए. उदयन शर्मा को दंगों की रिपोर्ट करने में महारत हासिल थी और वे दंगों को एक छिद्रान्वेषी नज़र से देखते थे और उसकी परतें-दर-परतें अलग कर देते थे. दंगों को रिपोर्ट करने का थोड़ा-बहुत अनुभव मुझे भी है. मेरा मानना है कि मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे देश में सही तरह से रिपोर्ट नहीं हुए. हमारे मीडिया के लोग, मेरा मतलब प्रिंट या टेलीविज़न दोनों से है, मुज़फ़्फ़रनगर के एक होटल में जाकर रुक गए. सरकार ने उन्हें सुविधाएं दीं और उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर शहर से बैठकर दंगों को रिपोर्ट किया. शहर में कर्फ़्यू था और मीडिया कर्फ़्यू को रिपोर्ट कर रहा था. वे शहर में सूनसान सड़कें दिखा रहे थे, बंद दुकानें दिखा रहे थे, लेकिन मुज़फ़्फ़रनगर का दंगा शहर का दंगा नहीं था. मुज़फ़्फ़रनगर का दंगा, तो गांव का दंगा था और हमारे माहिर साथी गांवों में गए ही नहीं. यही मेरे लिए सबसे बड़े अफ़सोस की बात है.

यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है

मुज़फ़्फ़रनगर के गांवों में दंगों की तहकीक़ात के बाद जो चीज़ें सामने आती हैं, वो यह कि यह पूरा इलाक़ा दो तरह के परस्पर विरोधी चरित्रों से भरा हुआ है. इस पूरे इलाक़े में भारतीय जनता पार्टी का कम, लेकिन आर्य समाज का ज़्यादा प्रभाव है. यहां आर्य समाज कब कट्टर हिंदुत्व में बदल गया, यह स्वयं आर्य समाज के लोगों को भी नहीं पता. पिछले तीन महीने में ऐसे मुसलमान जो ऊंचा पायजामा पहनते हैं, बड़ी दाढ़ी रखते हैं और टोपी लगाते हैं, ऐसे लोगों को चुन-चुनकर फ़ब्तियों का शिकार होना पड़ा और कुछ जगहों पर लोगों के हमलों का भी शिकार होना पड़ा. ट्रेन में या स्टेशनों पर ज़बरदस्ती दाढ़ी-टोपी वाले मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें काफ़ी बढ़ गई थीं. यह सारी जानकारी ज़िला प्रशासन को थी. ज़िला प्रशासन ने राज्य स्तर पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह जानकारी भेजी या नहीं भेजी, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस इलाक़े में सिर्फ़ मुज़फ़्फ़रनगर में ही नहीं, आसपास के कुछ और ज़िलों-सहारनपुर, मेरठ, शामली, बागपत में भी ये घटनाएं हो रही थीं. इन घटनाओं को रोकने की कोई कोशिश प्रशासन ने नहीं की. उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना वक़्त ही नहीं है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, उसके बारे में वो अधिकारियों की बैठक बुलाए और सख़्त प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दे.

यह पूरा इलाक़ा एक दूसरे चरित्र के लोगों से भी भरा हुआ है, जो निरामिष नहीं हैं, सामिष हैं. यहां पर मुसलमानों की एक बिरादरी के लोगों के पास पैसा आया और उन्होंने ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कीं. हिंदुस्तान के गांवों में जिस तरह की समाज व्यवस्था है, उसमें पैसा हो न हो, लेकिन जाति का अभिमान यहां के लोगों के सिर पर पागलों की तरह नाचता है. जिन लोगों की ज़मीन कुरैश बिरादरी के लोगों ने ख़रीदनी शुरू कीं, उन लोगों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन पैसा लेने के बाद अपनी जमीन के ऊपर बनते मकान या लहलहाती खेती को देखना इन लोगों के लिए चिढ़ का कारण बन गया. इस पूरे इलाक़े में तनाव का यह दूसरा कारण रहा. मज़े की बात कि गांवों में दंगे हुए, जिसमें ग़रीब मुसलमानों के घर ज़मींदोज कर दिए गए और कुछ जगहों पर कब्ज़ा करके वहां मकान बनाने शुरू हो गए, लेकिन उसी गांव में रहने वाले बड़ी जाति के मुसलमानों के ऊपर दंगों का एक छींटा तक नहीं पहुंचा. न किसी ने उन्हें गालियां दीं, न किसी ने उन्हें परेशान किया, न ही उनके ऊपर एक पत्थर फेंका, गोली की बात तो बहुत दूर. बड़ी जाति के मुसलमान जो गुर्जर और जाट मुसलमान हैं, वे अपने घरों में ही रहे. घर से निकले ही नहीं. उन्होंने छोटी जाति के मुसलमानों की मदद नहीं की. अगर सारे मुसलमान एक साथ खड़े हो जाते, तो यह दंगा नहीं फ़ैलता. दंगाई गांव में नहीं आते, लेकिन बड़ी जाति के मुसलमानों ने छोटी जाति के मुसलमानों का साथ नहीं दिया.

दूसरी तरफ़ यह कहना कि हर जाति का आदमी इस दंगे में शामिल था, यह ग़लत है. इस दंगे में सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 प्रतिशत से ज़्यादा जाट बिरादरी के लोग शामिल थे. जाट बिरादरी के लोगों को कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने यह कहकर भड़काया कि तुम्हारी बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, का मतलब ऐसा लगा कि मानो यहां पर जाटों की बहू-बेटियों पर ग़ैर-जाटों का हमला होने वाला है या हमला हो रहा है, जोकि निहायत ग़लत और असत्य की परिभाषा से भी परे अगर कोई असत्य हो सकता है, तो यह असत्य था. आजकल के नौजवान चाहे वे जाटों में हों, मुसलमानों में हों, दलितों में हों, वे धर्म का बंधन बहुत ज्यादा नहीं मानते. जाति का बंधन वे तोड़ रहे हैं. हालांकि बहुत सारी जगहों पर चाहे मुसलमानों की पंचायतें हों, जाटों की पंचायतें हों, ऐसे प्यार करने वाले लोगों की हत्या का आदेश तक दे रहे हैं. मैं फिर कह रहा हूं कि यह दोनों तरफ हो रहा है. मुसलमान भी अपने यहां प्यार करने वाले नौजवानों के ख़िलाफ़ पंचायतें करते हैं, दूसरी तरफ़ जाट भी ऐसी पंचायतें करते हैं. वे अपने नौजवानों को आज के टेलीविज़न और सूचना की दुनिया में फैलने वाली जानकारी से दूर रखना चाहते हैं. जब घर में टेलीविज़न से बाहरी दुनिया दिखाई देती है, तो नौजवान लड़के-लड़कियों का मन आसमान में उड़ने के लिए बेक़रार हो जाता है. और जब वे उड़ना चाहते हैं, तो उनकी जान के दुश्मन उन्हीं के परिवार और उनके समाज के लोग हो जाते हैं. इस घटना में भी यही हुआ. एक घटना या दो घटना को पूरे जाट समाज की इज़्ज़त से जोड़ दिया गया. नतीजतन एक तरफ जाट संगठित हुए, उन्होंने मुसलमानों को जहां देखा मारा और दूसरी तरफ सिर्फ़ शुरुआती दिनों में जहां पर मुसलमानों को अपने आस-पास जाता हुआ कोई हिंदू व्यक्ति दिखाई दिया, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया. मैं फिर साफ़ कर दूं कि बड़ी जाति के मुसलमान इस दंगे की आंच से दूर भी रहे और उन्होंने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया. उसी तरीक़े से ग़ैर-मुसलमानों की 80 प्रतिशत आबादी इससे दूर रही. सिर्फ़ जाट समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए. वे भी इस बहकावे और भड़कावे में आकर कि उनकी बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. देश में इस तरह से रिपोर्ट प्रसारित हुईं, मानो सारा दंगा मुज़फ़्फ़रनगर शहर में हो रहा है. आज़ादी के बाद पहली बार देश के गांवों में दंगा फैला. मैं इस दंगे के इस पहलू से ज़्यादा चिंतित हूं. हिंदुस्तान के गांवों में हिंदू बच्चे, जिनमें हम सब शामिल रहे हैं, जुम्मन चाचा, रहीम चाचा, गौहर अम्मा, इस तरह के संबोधनों से मुसलमानों को पुकारते थे. उसी तरह मुसलमान भी संजय ताऊ, बिट्टा खाला इस तरह इज़्ज़त के रिश्ते से एक-दूसरे को बुलाते थे. हमने यह देखा है कि जब भी कोई त्यौहार होता था, मुसलमानों के घरों में थालियां भेजी जाती थीं. ईद में मुसलमानों के घरों से सिवइयां आती थीं. यह सब हमारे देश में अभी तीस साल पहले तक होता था. तीस साल पहले तक हिंदुस्तान के गांवों में ज़्यादातर स्कूलों को मदरसा कहा जाता था और हम सब मदरसों में पढ़े हैं. मैं प्राइमरी स्कूल में नहीं गया हूं. मेरी उम्र के जितने लोग हैं, वे प्राइमरी स्कूल में नहीं, मदरसों में पढ़े हैं. जिसको आज प्राइमरी स्कूल कहते हैं, उसको पहले मदरसा ही कहते थे. हिंदुस्तान की अदालतों का सारा काम हिंदी या अंग्रेज़ी में नहीं, उर्दू में होता था. हमारी तहजीब गंगा-जमुनी तहजीब थी और अब भी है. एक दूसरे के सुख-दुख में आंसू बहाने का और खिलखिला कर हंसने का मौसम हमेशा हिंदुस्तान में रहा, लेकिन सद्भाव के इस माहौल पर जब से सांप्रदायिक ताक़तों की नज़र लगी, तब से उन्हें लग रहा है कि अगर किसी तरीक़े से वैमनस्यता गहरी हो जाए और इस तहजीब को ख़त्म कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान में आसानी से राज किया जा सकता है. मैं एक बात पर क़ायम हूं और मैं अपने साथी पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे दंगे के समय, जिसमें नफ़रत फैलाने वाले खुलेआम घूमते हों, उस समय इस बात की ज़रूरत है कि रिपोर्ट सही और सेंसिटिव हो. साथ ही सही कारणों के साथ हो, ताकि लोगों को लगे कि सब लोग उसमें शामिल नहीं हैं. यह कुछ लोगों के भड़काने पर एक छोटी या बड़ी संख्या भड़क गई और उसने एक कारनामे को अंजाम दिया. इस घटना को शास्वत बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जोकि आज हमारे साथियों के द्वारा हो रही है. बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिसमें हिंदू खड़े हो गए मुसलमानों की रक्षा में और मुसलमान खड़े हो गए हिंदुओं की रक्षा में. क्या यह घटनाएं हममें यह आशा नहीं जगातीं कि अभी भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग धर्म के आधार पर बंटेंगे नहीं और जो बांटने की कोशिश करेगा, वह आख़िर में मुंह की खाएगा. मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपकी भाषा में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से बड़ी ख़ुशी का क्षण नहीं आ सकता. बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस देश में चुनाव हुए, जब बाबरी मस्जिद गिरी नहीं थी, उस समय चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरने के बाद तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्त हो गया. राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत जी आए, लेकिन वे अपने करिश्मे की वजह से आए, न कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से. हिंदुस्तान का वोटर सांप्रदायिक आधार पर वोट नहीं देता और मैं अपने इस कॉलम के जरिये इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, ताकि वो लोग जो देश को बांटने के लिए दंगों की साज़िश करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि देश कभी भी सांप्रदायिक आधार पर बंटेगा नहीं. अगर बंट जाएगा, तो यह देश बदल जाएगा. मैं बार-बार भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहता हूं कि इस चुनाव में इस दबी हुई इच्छा की परीक्षा हो जानी चाहिए. मुसलमानों से और हिंदुओं से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि हमारा एजेंडा है धारा 370 ख़त्म करना. हमारा एजेंडा है राम मंदिर बनाना. हमारा एजेंडा है कॉमन सिविल कोड लागू करना. हमारा एजेंडा है मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखना, जैसा हिंदू पाकिस्तान में है. यह बात खुलकर कहनी चाहिए और अगर भारतीय जनता पार्टी यह बात खुलकर नहीं कहती, तो यह मानना चाहिए कि इससे बड़ी हिप्पोक्रैट पार्टी देश में कोई हो ही नहीं सकती. जो बातें आप छुप-छुपकर कमरों में या अफ़वाहों के ज़रिये करते हैं, उसे आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्यों नहीं डालते? अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह सारी चीज़ें अपने घोषणा पत्र में डाले और यह वायदा करे कि यह देश के लिए आख़िरी मौक़ा है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, धारा 370 ख़त्म हो जाएगी. उर्दू का कोई स्थान नहीं रहेगा और राम मंदिर बनेगा. बाबरी मस्जिद कहीं बननी है तो बने, न बननी है तो न बने. इसके ऊपर अगर देश में चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को सलाम करेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह ऐलान करना चाहिए कि फिर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे. यह मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें नकार दिया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को सख़्ती के साथ उन ताक़तों को रोकना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश का अमन-चैन बर्बाद करने के लिए क़सम खाए बैठी हैं और उन्हें पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है. शर्त सिर्फ़ इतनी है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते एक्ट करें, न कि एक ग़ैर-ज़िम्मेदार नौजवान के नाते. लोग अब कहने लगे हैं कि अखिलेश नौजवान हों, समझदार हों, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि वे एक असफल मुख्यमंत्री हैं.

मुज़फ़्फ़रनगर के दंगे बढ़ने नहीं चाहिए. हालांकि इस बात की पूरी तैयारी है कि इन दंगों को सीरीज़ की तरह आगे बढ़ाया जाए. हम इन चीज़ों को पिछले चार महीने से देख रहे थे, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार आज तक नहीं देख पाई है. हमने अख़बार में हिम्मत के साथ लिखा था *दंगे होने वाले हैं*. यह अख़बार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के पास गया, उन्होंने हमारे इस आकलन का मज़ाक उड़ाया. सबने हमारे इन तथ्यों का मज़ाक उड़ाया. आज जब वे तथ्य और वे आकलन नंगे रूप में उनके सामने खड़े हैं, तो उन्हें बगलें झांकने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों को सख़्ती के साथ उन ताक़तों को रोकना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश का अमन-चैन बर्बाद करने के लिए क़सम खाए बैठी हैं और उन्हें पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है. शर्त सिर्फ़ इतनी है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते एक्ट करें, न कि एक ग़ैर-ज़िम्मेदार नौजवान के नाते. सारे देश में अखिलेश यादव सफल होंगे या असफल, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही थीं. अब वे कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव नौजवान हों, समझदार हों, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि वे एक असफल मुख्यमंत्री हैं. मेरा अखिलेश यादव से विनम्र निवेदन है. अभी भी वक़्त है. अपने को साबित करिए और देश में लोगों का विश्वास नौजवानों के प्रति, ख़ासकर नौजवान मुख्यमंत्री के प्रति दोबारा स्थापित कीजिए. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राजनीति में विश्वसनीयता ज़रूरी

यूपीए सरकार की सभी असफलताओं के बाद भी भाजपा की हालिया नीतियां उसे चुनाव हरा सकती हैं. भले ही मोदी चाहते हों कि यह चुनाव गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी में कुछ नेताओं की अभी भी यह सोच बनी हुई है कि हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को उभारकर और उन्हें हवा देकर ही पार्टी उत्तर प्रदेश में ख़ुद को सुरक्षित कर सकती है. इसी सोच के साथ विश्व हिंदू परिषद ने परिक्रमा शुरू की, लेकिन देश के भाग्य से वह रोक दी गई. मुज़फ़्फ़रनगर प्रकरण के बाद लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि भाजपा क्या कभी आधुनिक पार्टी बन भी पाएगी या अपनी मध्यकालीन मानसिकता में ही फंसी रहेगी?

ताश के पत्तों के खेल का पहला नियम है कि अपने पत्ते आख़िर तक मत खोलिए और विशेषकर तब, जब आपका पक्ष कमज़ोर हो. मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में यही खेल खेला और जीत हासिल की, जबकि वे उस दौर में अलग-थलग पड़ चुके थे.

आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र देखा जाए, तो हर कोई किसी न किसी निर्णय की ओर भाग रहा है, जोकि उसके लिए घातक निर्णय साबित हो सकता है. इस क्रम में जनता दल-यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच एलाएंस के अलग होने को इसी नज़रिए से देखा जा सकता है. अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने इस वर्ष के आख़िर तक इंतज़ार क्यों नहीं किया, जबकि पहले वह यही कह रहे थे. उनके इस फ़ैसले के पीछे यह सोच नज़र आती है कि वे लालू प्रसाद यादव को जो फ़ायदा मिलता दिख रहा है, उस लाभ को अपने पाले में लाना चाहते हैं.

2014 लोकसभा चुनावों को लेकर एक पूर्वानुमान और है कि यह चुनाव उसी तरह लड़ा जाएगा जैसाकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है. क्यों? कांग्रेस के सामने एक मुश्किल है, जोकि पिछले दस वर्षों से है. सोनिया गांधी ने यह मान लिया है (मेरे विचार में बिना कोई विचार किए) कि उनका विदेशी होना उनके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के रास्ते में रोड़ा है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री पद को पिछले दस वर्षों से कमतर आंका जा रहा है. जैसा कि रूस में है. हर कोई जानता है कि राजनीतिक शक्तियां किसके हाथ में हैं. चाहे ब्लादिमिर पुतिन राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री. कांग्रेस क्यों आखिर इस बात की परवाह करे कि प्रधानमंत्री कौन है.

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने ऐसी ही अनावश्यक जल्दबाज़ी दिखाते हुए मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया. फिर से वही सवाल कि इसकी जल्दी क्या थी? वे पार्टी के मुख्य प्रचारक हैं और देश के सामने एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं. जब सीटों की गणना होगी तब इस बात का निर्णय करने का सही वक़्त होगा कि क्या किया जाए. अगर भारतीय जनता पार्टी को तक़रीबन 180 सीटें मिलती हैं, तब व्यवहारिक तर्क़ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे मोर्चे पर नियंत्रण करके 273 सीटों का समर्थन नहीं हासिल कर सकते.

कुछ लोगों का तर्क़ है कि मोदी की क्षमता से अभी लोग परिचित नहीं है. अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री इस पद तक नहीं पहुंचा है, जिसकी कार्यवधि दिल्ली में न रही हो. हो सकता है कि इसी तर्क़ की काट खोजते हुए मोदी के नाम की घोषणा पहले कर दी गई है, ताकि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी पहचान पर मुहर लगाई जा सके.

राहुल गांधी की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है. देश के किसी भी राजवंश का उत्तराधिकारी चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आया है. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही दुखद असामयिक निधन के चलते प्रधानमंत्री बने. 1967 में जब इंदिरा गांधी ने पहला चुनाव लड़ा तो पिछले तीन चुनावों में जितनी सीटें उनके पिता को हासिल हुई थीं, उससे कम सीटें मिलीं. राजीव गांधी को सहानुभूति के चलते 1984 के चुनावों में वोट मिले, लेकिन उसकी क्षण भंगुरता 1984 के चुनावों में सामने आ गई. किसी भी परिवार का वंशज होना वोट हासिल करने का फॉर्मूला नहीं हो सकता. कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अब प्रमुखता से ज़िम्मेदारी लें लेकिन हो सकता है कि वे इसी वजह से हिचक रहे हों.

यूपीए सरकार की सभी असफलताओं के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की हालिया नीतियां उसे चुनाव हरा सकती हैं. भले ही मोदी चाहते हों कि यह चुनाव गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ा जाए लेकिन बीजेपी में कुछ नेताओं की अभी भी यह सोच बनी हुई है कि हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को उभारकर और उन्हें हवा देकर ही पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित कर सकती है. इसी सोच के साथ विश्व हिंदू परिषद ने परिक्रमा शुरू की, लेकिन देश के भाग्य से वह रोक दी गई. पर मुज़फ़्फ़रनगर प्रकरण के बाद लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि भाजपा क्या कभी आधुनिक पार्टी बन भी पाएगी या अपनी मध्यकालीन मानसिकता में ही फंसी रहेगी?

कांग्रेस अपने हक के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से दांव लगा रही है. हो सकता है कि यह दांव अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ख़तरा बन जाए. हो सकता है कि इसके चलते मुद्रास्फीति और बजट घाटा नियंत्रण के बाहर चले जाएं और विकास दर रसातल में. आप लोगों को खोखले वायदों का पिटारा और कुछ सस्ती भेंट दीजिए और बदले में उनसे वोट की उम्मीद करिए. लेकिन इसका ख़तरा भी है और राजनेताओं को इस ख़तरे का आभास भी है. उन्हें पता है कि अगर ग़रीब मज़बूत हो गया तो उनका वोट बैंक ख़तरे में पड़ जाएगा. यही वजह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की गति काफ़ी धीमी है. नेता चुनाव जीत सकता है लेकिन अगर उसकी और पार्टी की विश्वसनीयता चली गई तो वापस नहीं मिल सकती. यह बनी है तो इसे मत गंवाइए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

अगर न मिले स्कूल ड्रेस या किताब

चौथी दुनिया ब्यूरो

सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आएं, इसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं. जैसे यूनीफॉर्म और किताबों का वितरण. उक्त योजनाएं दरअसल वैसे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, जो ग़रीबी की वजह से अपने बच्चों की शिक्षा पर आने वाले ख़र्च को उठा पाने में सक्षम नहीं होते. सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को यूनीफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. योजना के तहत एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को यूनीफॉर्म दी जाती है. इसकेलिए सर्व शिक्षा अभियान को मुख्यालय से एससी-एसटी छात्रा कोष से बजट आवंटित किया जाता है. इसी तरह देश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें देने की व्यवस्था है, लेकिन कई बार अधिकारियों और अध्यापकों की मिलीभगत के कारण यह सुविधा बच्चों तक नहीं पहुंच पाती.

अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए. ज़ाहिर है, हम अपने अधिकार को अपनी आंखों के सामने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते तो नहीं देख सकते. अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों का हौसला बढ़ता जाएगा. इसलिए इस अव्यवस्था और बेईमानी के ख़िलाफ़ संघर्ष करना ही होगा. इस काम में आपका सबसे बड़ा हथियार सूचना का अधिकार क़ानून है. इसके तहत आप एक आवेदन बनाएं और संबंधित विभाग में जमा करें. आप यह पूछें कि यूनीफॉर्म और किताबें कब वितरित की गईं. जिन्हें यह सुविधा मिली, उनके नाम आदि के बारे में सूचना मांगें. आप वितरण रजिस्टर की प्रतिलिपि भी मांग सकते हैं. आरटीआई (सूचना क़ानून) के पास इतनी ताक़त है, जिससे भ्रष्ट, बेईमान और असंवेदनशील अधिकारियों को रास्ते पर लाया जा सकता है. बशर्ते आप ख़ुद जागरूक हो जाएं और जंग लगी व्यवस्था से सवाल पूछकर उन्हें अपनी ताक़त का एहसास कराएं. चौथी दुनिया आपकी लड़ाई में हर क़दम पर आपके साथ है. हमारा विश्वास है कि आरटीआई आवेदन डालते ही अधिकारी हरकत में आएंगे. यदि कोई और समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं. ■

आवेदन का प्रारूप
(युनिफार्म/ किताबों वितरण का विवरण)

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

............स्थित विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. क्या वर्ष..........एवं वर्ष.......के लिए उपरोक्त विद्यालय में छात्रों को यूनीफॉर्म/किताबें वितरित कर दी गई हैं? यदि हां तो कितने छात्र-छात्राओं को वितरित की गई हैं? जिन छात्रों को यूनीफॉर्म/किताबें दी गई हैं, उनकी सूची निम्न विवरण के साथ दें:
   (क) छात्र-छात्रा का नाम
   (ख) यूनीफॉर्म/किताबें किस तारीख को दी गईं
   (ग) प्राप्ति रजिस्टर की प्रतिलिपि
2. यदि यूनीफॉर्म/किताबें वितरित नहीं की गई हैं तो निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएं:
   (क) अभी तक यूनीफॉर्म क्यों नहीं बांटी गई?
   (ख) नियमों के अनुसार सत्र शुरू होने के कितने समय के अंदर यूनीफॉर्म वितरित कर दी जानी चाहिए?
   (ग) यूनीफॉर्म वितरण सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी किन अधिकारियों की थी? उनके नाम एवं पद बताएं?
3. विद्यालयों में यूनीफॉर्म/किताबों के वितरण के संबंध में जारी किए गए सभी शासनादेशों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.
4. अब तक यूनीफॉर्म/किताबें न बांटे जाने के कारण छात्र-छात्राओं को जो परेशानी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद बताएं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक?
5. छात्रों को यूनीफॉर्म/किताबें कब तक मिल जाएंगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम....................
पता....................
फोन नंबर..............
संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष

21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह पैत्रिक संपत्ति से सम्बंधित आप किसी नए विवाद में पड़ सकते हैं. आपका पहले से चला आ रहा किसी से मनमुटाव दूर होगा. पारिवारिक लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और नौकरीपेशा वाले लोग अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ज्यादा मसालादार खाना खाने से बचें.

वृष

21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह आप कई नई परियोजनाओं पर कार्य करेंगे और आपके धन में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा. व्यापारियों के लिए अच्छा समय है. परिवार में ख़ुशी के आप मुख्य स्रोत होंगे. आप संयम और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे.

मिथुन

21 मई से 20 जून

इस सप्ताह आप की मुलाकात प्रतिष्ठित लोगों से होगी. राजनीतिक व्यक्ति से आपको मदद मिलेगी. आप काफी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे और अपनी सूझ-बूझ से कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेगें. विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी और प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क

21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह आपका पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बढ़ेगा. आप घरेलू और व्यवसाय में अच्छा कार्य करेगें. निवेश करने से पहले विश्लेषण कर लें और कोई भी निर्णय क्रोध में न लें. यात्रा का योग है और आप को लाभ होगा. परिवार में बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

सिंह

21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आपकी उपलब्धि बढ़ेगी, जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे और कोई प्रतिक्रिया जल्द न दें. अपने मन की कोई सोची रणनीति को सबके सामने न रखें. असफलता से परेशान न हो और अपने आपको किसी सामूहिक कार्यों में लगाएं. बुजुर्गों की सेवा करें इससे आपको लाभ होगा.

कन्या

21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आपको लोगों की मदद करने में खुशी महसूस होगी. अपने ऊपर आई नई जिम्मेदारियों से परेशान होंगे, लेकिन आपकी प्रतिभा आपको सफलता दिलाएगी. भाग-दौड़ रहेगी और आलस्य महसूस करेंगे. अपने और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला

21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह धैर्य से काय करें और कोई जल्दबाजी न करें. कोई भी कार्य सूझ-बूझ से करें और नई संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतें. सहयोगियों के साथ तालमेल बना कर रखें. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. अपने मानसिक स्थिति को मजबूत रखें और दृढ़ निश्चय के साथ कोई निर्णय लें.

वृश्चिक

21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहेगें. तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें. व्यवसायिओं को कार्य में फायदा होगा. नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए संयम रखने का समय है, नहीं तो नुकसान हो सकता है. जीवन साथी के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. भावनाओं में आकर कोई कार्य न करें.

धनु

21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह घरेलू मामलों को उलझने न दें. कलात्मक चीजों में रुचि बढ़ेगी और आर्थिक कार्यों में सावधानी बरतें. सबकी बातों को सुनने के बाद अपने से निर्णय लें. आपसी प्रेम से नकारात्मक चीजों को दूर करें. अपने जमा किए हुए पैसे का दुरुपयोग न करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर

21 दिसंबर से 20 जनवरी

यह सप्ताह पारिवारिक सुख देने वाला होगा. कुछ मानसिक समस्याएं हो सकती हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं. नौकरी करने वाले और व्यापारी दोनों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है. माता-पिता के साथ प्यार से रहे और उनका आशीर्वाद ले. कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ

21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह आपका पराक्रम बढ़ेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों को आर्थिक मजबूती मिलेगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. लंबी यात्रा करने से बचें. अंधविश्वास में आकर कोई कार्य न करें और शत्रुओं से सावधान रहें.

मीन

21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह पारिवारिक सुख रहेगा. परिवार और मित्रों से मतभेद न होने दें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा. आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय शुभ रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. यह सप्ताह आपको मिले-जुले फल देने वाला होगा.

ज़रा हट के

हिफ़ाज़त करेगी ये साइबर डिवाइस

महिलाओं को अब यौन शोषण और अन्य हिंसक घटनाओं से बचने के लिए मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है. केरल में युवा साइबर सुरक्षा पेशेवरों ने अब एक अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण का आविष्कार किया है और इसे नाम दिया है अमृता निजी सुरक्षा प्रणाली. कोल्लम स्थित अमृता विश्वविद्यालय के साइबर सुरक्षा प्रणाली एवं नेटवर्क केंद्र (सेंटर फॉर साइबर सेक्युरिटी एंड नेटवर्क) की निदेशक डॉ. कृष्णाश्री अच्युतन ने कहा कि एपीएसएस दिखाई नहीं देने वाला, पहनने योग्य और आसानी से चलाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी मदद से संकट के समय में महिलाओं को परिवार और पुलिस के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस डिवाइस को अपराधी नहीं देख पाएंगे और इस कारण उपयोगकर्ता इसे कई विकल्पों के साथ आसानी से गुप्त और सुरक्षित ढंग से घटना या उसकी आशंका के बारे में अपने परिजनों या पुलिस को तुरंत सूचना दे सकती हैं. हाल ही में दिल्ली आए डॉ. अच्युतन ने बताया कि एक बटन को दबाने या एसएमएस और वॉयस कॉल के इस्तेमाल से तुरंत कई जगहों पर बातचीत और संवाद कायम करने और उसे रिकॉर्ड करने की क्षमता के साथ यह डिवाइस पीड़ित के नजदीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल और फायर स्टेशन में भी स्वचालित सूचना प्रदान करता है ताकि उसे तत्काल मदद मिल सके. साइबर सुरक्षा अमृता केंद्र यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि इस उपकरण को सुरक्षित रूप से एक अंगूठी में फिट किया जा सके. इसे इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है, ताकि यह सस्ती और सबकी पहुंच में हो. इस डिवाइस को जल्द ही ऐसी प्रौद्योगिकी से लैस किया जाएगा, जिससे घटनाओं की वीडियो टेपिंग की जा सके. एपीएसएस की एक विशेषता यह भी है कि यह वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य कर सकता हैं जहां संचार की गति बहुत कम है. 29 अमेरिकी पेटेंट की लेखिका डॉ. अच्युतन ने कहा कि इस अनुकूलन डिवाइस की डिजाइन इस प्रकार की गई है जिससे इसे पहनना सुविधाजनक है, और यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित 15 से अधिक सुविधाओं से लैस है. गौरतलब है कि इसे कई मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसकी मदद से जल्द ही अपने निवास की पहचान कर सकते हैं. ■

शाकाहारी अंडे

अब शाकाहारी लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है. अभी तक शायद ही लोगों ने शाकाहारी अंडे के बारे में सुना होगा. अब आपको शाकाहारी अंडे भी मिलेगें. एक अमेरिकी कंपनी ने शाकाहारी अंडे का आविष्कार किया है. इस कृत्रिम अंडे को पूरी तरह से पौधों से बनाया गया है. अब यह शाकाहारी लोगों के लिए यह नया तोहफा है. कंपनी ने सफलता-पूर्वक फॉक्स मेयोनेज और कई तरह की बेक्ड चीजों को मिलाकर अंडे का सब्सिट्यूट तैयार किया है. इन अंडे को बहुत ही साधारण तरीके से लेकिन मटर की अद्भुत प्रजातियों, ज्वार और 11 अन्य तरह के पौधों से मिलकर बनाया गया है. फॉक्सन्यूज डॉट कॉम ने कंपनी के सीईओ जोश टेटरिक ने यह बात कही. टेटरिक ने इसके लिए टीवी शो टॉप शेफ के कंटेस्टेंट क्रिस जोन्स और बायोकेमिस्ट जोशुआ क्लेन की मदद ली. जिसमें उन्होंने एक ऐसा अंडा बनाने में उनकी मदद मांगी जो पूरी तरह से असली अंडे की तरह दिखे, एग फ्री प्रोडक्ट हो. टेटरिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि पौधों से तैयार यह अंडा सिर्फ शाकाहारियों के लिए ही नहीं सभी के लिए है. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि इससे अंडा या पोल्ट्री इंडस्ट्री किसी तरह प्रभावित नहीं होगी. वास्तविक रूप से यह कोई पोल्ट्री इंडस्ट्री के महत्व को कम भी नहीं करेगा. अमेरिका में एग्रीकल्चर रिसर्च फिजियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के रेमंड ग्लाहन ने बताया कि यह प्रोडक्ट लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा. वहीं उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि प्लांट बेस्ड फूड होने के कारण इस अंडे की न्यूट्रीशनल वेल्यू बहुत अधिक होगी. सैन फ्रांसिस्को स्टार्टअप हैम्पटन क्त्रीक फूड्स वेबसाइट ने दावा किया है कि यह प्रोडक्ट न सिर्फ अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि सामान्य अंडों से इसकी कीमत 19 प्रतिशत कम भी होगी. टेटरिक ने कहा कि कंपनी का यह नया प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है और बाजार में भी उपलब्ध है. इसमें प्राकृतिक अंडे जैसी ही पौष्टिकता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

ये अनोखा पेड़ है

लोगों को कभी रास्ते में कहीं जाते समय ऐसे पेड़ दिख जाते होंगे जिन्हें देखकर एक डर-सा लगता है. जिन पर चमगादड़ लटके रहते हैं, खाली घोंसले टंगे रहते हैं, लेकिन एक पेड़ है जो इन सबसे अलग है. इस पेड़ को देखकर भले ही आपको किसी भूत वाली फिल्म का सीन याद आने लगे, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे. यह पेड़ अलग-सा इसलिए नजर आता है, क्योंकि ये चारों ओर से रेशम से ढका हुआ होता है. जी हां, बीहड़ में खड़े मुर्दा पेड़ से अलग इस पेड़ को हजारों रेशम के कीड़ों ने अपनी लार से निकलने वाले रेशम के धागे से लपेट रखा है. डेलीमेल में छपी एक खबर के अनुसार, फोटोग्राफर थॉमस मारेंट अपने एक दोस्त के साथ टहल रहे थे और उसी समय उन्होंने ये फोटो ली. दरअसल आपको पेड़ पर रेशम के धागे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कीड़ों ने सारी पत्तियां चबा डाली हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

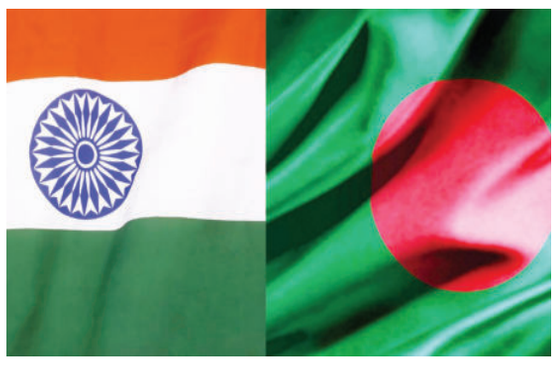

सत्ता में आते ही शेख हसीना सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर अमल करना शुरू किया, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं. 1971 के बाद से अदालतों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का फ़रमान जारी किया गया. इसका परिणाम यह हुआ कि दोषियों को सज़ा मिलनी शुरू हो गई. दूसरी तरफ़ देश को तोड़ने वाले अवांछित तत्वों में यह संदेश भी गया कि अब उनकी नापाक़ हरकतों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बांग्लादेश चुनाव

भारत के लिए कौन होगा फ़ायदेमंद

शेख हसीना हमेशा से ही भारत से मित्रता की पक्षधर रही हैं. दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया की पार्टी में कट्टरपंथियों और भारत विरोधी तत्वों का वर्चस्व है, जो भारतीय हितों के ख़िलाफ़ है. ऐसे में बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार न सिर्फ भारतीयों के लिए, बल्कि बांग्लादेशियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

खालिदा ज़िया

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया फिर से कट्टरपंथी लोगों का साथ पाकर बांग्लादेश की सत्ता हथियाना चाहती हैं. खालिदा जिया जब भी बांग्लादेश की सत्ता में आईं, कट्टरपंथियों ने सिर चढ़कर बोला. सबसे बड़ी बात यह है कि खालिदा के शासन में हमेशा से ही आतंकवाद और उग्रवाद भारत के लिए सिरदर्द बना रहा. कट्टरपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ हैं. इसी पार्टी की नेता हैं खालिदा जिया. देखा जाए तो इस पार्टी और खालिदा जिया की नीतियों में ही ख़ामी है. खालिदा उन्हीं जियाउर्रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने सैनिक तख़्ता पलट कर मुजीब की हत्या के बाद गद्दी हथियाई थी.

शेख हसीना

शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं. उनके पिता, मां और तीन भाई 1975 के स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे. शेख हसीना बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की वाहक मानी जाती हैं, जो भारतीय हितों के अनुकूल है. शेख हसीना ने सत्ता में आते ही अपने वादे के मुताबिक बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध अपराधियों को दंड दिलवाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई तेज़ कर दी है. शेख हसीना की ही देन है कि हाल के वर्षों में एक भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई और तत्परतापूर्वक उन सभी आतंकी और चरमपंथी समूहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है, जो अपनी गतिविधियां बांग्लादेश की ज़मीन से संचालित कर रहे थे.

राजीव रंजन

बांग्लादेश की वर्तमान संसद का कार्यकाल 25 अक्टूबर, 2013 को समाप्त हो जाएगा. बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, 90 दिन के भीतर चुनाव होना जरूरी है. बांग्लादेश में 26 अक्टूबर से 24 जनवरी, 2014 तक चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया ने एक-दूसरे को अब तक बराबर का टक्कर दिया है. 1991 और 2001 में खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और 1996 में और उसके बाद 2009 से अब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं. हालांकि बांग्लादेश की जनता में शेख हसीना की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन बांग्लादेश की सियासत में कौन किसको मात दे दे, कहा नहीं जा सकता.

भारत के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा की 4,095 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है. सिर्फ सीमा से ही बांग्लादेश का जुड़ाव भारत से नहीं है, बल्कि वहां की भाषा, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रवाद का जुड़ाव भी भारतीय इतिहास और संस्कृति से है. इसलिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में अमन और शांति भारत के लिए बेहद जरूरी है. और यह तभी संभव है, जब शेख हसीना फिर से सत्ता में आएं. हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्त्तमान हसीना सरकार ने भारत-बांग्लादेश संबंध को जो नये आयाम दिए हैं, उसकी उम्मीद हम कभी भी खालिदा जिया से नहीं कर सकते और न ही खालिदा जिया सरकार ही कभी भारत की उम्मीदों पर खरी उतरी.

शेख हसीना जनवरी, 2009 में जब देश की प्रधानमंत्री बनीं, उसके महज चार दिन बाद ही भारत यात्रा कर भारत विरोधियों को सीधा संदेश दिया कि आनेवाले वक्त में भारत के साथ उनका संबंध कैसा होगा. शेख हसीना ने लंबे समय से चले आ रहे भारत-बांग्लादेश की चिंताओं को कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर कर दूर भी कर दिया. शेख हसीना की सरकार भारत के लिए कई मायनों में खास है. हसीना ने इस बार सत्ता में आने के बाद दशकों से चले आ रहे भारत और बांग्लादेश के बीच 4,156 किलोमीटर लम्बी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को अंतिम रूप दिया और नक्शों पर हस्ताक्षर किए. सीमा विवाद का सुलझना दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है. पूर्वोत्तर के सात राज्यों से शेष भारत को एक संकरी-सी पट्टी जोड़ती है, जिसे चिकन्स नेक कहते हैं. भारत चाहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश एक रास्ता दे, यह काम शेख हसीना कर सकती ही इन मुद्दों का समुचित समाधान निकाल सकती है. जो मुद्दे लंबित हैं, उनमें हैं गंगा जल विवाद, चकमा विस्थापितों की समस्या, बांग्लादेश को तीन बीघा कॉरिडोर का हस्तांतरण, असम व अन्य उत्तरी-पूर्वी राज्यों के उग्रवादियों को बांग्लादेश में शरण देने का मसला और हरकत-उल-जिहाद-इस्लामी जैसे आंतकवादी संगठनों को बांग्लादेश में प्रश्रय मिलना. भारत और खुद बांग्लादेश की उम्मीदों को सिर्फ शेख हसीना ही पंख लगा सकती हैं.

दूसरी ओर कट्टरपंथी व भारत विरोधी विचारधारा वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो अक्सर भारत पर दक्षिण एशिया में दादागिरी करने का आरोप लगाती रही है. बांग्लादेश में आम चुनाव सामने है. उम्र कैद की सजा पाए जमात के नेता अब्दुल कादर मौला को मीरपुर का कसाई कहा जाता है. कट्टर पार्टी जमात का बांग्लादेश की राजनीति में चार प्रतिशत वोट है. जमात की तरह जितनी भी पार्टियां हैं मसलन बीएनपी, वह सब शेख हसीना को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसीलिए वे एक-दूसरे के साथ मिल गई हैं. आज जो कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति का विरोध किया था. वे देश को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर ले जाने के विरोधी हैं. पिछले एक दशक में बांग्लादेश की चीन

हैं. शेख हसीना को यह पता है कि बांग्लादेश कई तरह के कट्टरपंथी संगठनों का पनाहगार है, जो उनके देश के विकास में बाधक है. सत्ता में आते ही जिस तरह से उन्होंने इन संगठनों पर नकेल कसनी शुरू की, उससे यह साफ है. सत्ता में आते ही शेख हसीना की सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर अमल करना शुरू किया, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं. भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की भूमिका भी है. शेख हसीना ने 1971 के बाद से अदालतों में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का फरमान जारी किया. दोषियों को सजा मिली. दूसरी तरफ अवांछित तत्वों में यह संदेश भी गया कि देश को तोड़ने वाली नापाक हरकतों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिस तरह से शेख हसीना ने अपने प्रयासों से भारत का दिल जीता, भारत ने भी बांग्लादेश की बेहतरी के लिए अपनी ओर से हर संभव मदद दी. वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए भारत ने बांग्लादेश से होने वाले निर्यात को कई तरह की छूट दी. यही कारण है कि शेख हसीना सरकार के आने के बाद बांग्लादेश का निर्यात पिछले कुछ सालों में लगभग 6 गुना बढ़ गया है. शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग ने कट्टरपंथी राजनीति के खिलाफ अपनी रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि भारत के साथ अपने सहयोगी रिश्तों पर जोर भी दिया.भले ही जनवरी 2009 में सत्ता में आते ही शेख हसीना सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच ढेर सारे मुद्दों को हल किया था, लेकिन अभी भी कई मुद्दे हैं, जिसे लेकर भारत यह सोचता है कि शेख हसीना सरकार के साथ मित्रता बढ़ी है, जिसके पीछे खालिदा जिया की पार्टी की अहम भूमिका है. आज के दौर में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है. चीन द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण रोजमर्रा की बात हो गई है. चीन की मंशा है कि वह बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे और इस काम को वह बखूबी कर भी रहा है. इसलिए खालिदा जिया का सत्ता में आने का मतलब होगा बांग्लादेश में कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद का फिर से सिर उठाना और चीन को भारत के दुश्मन के तौर पर और अधिक सशक्त करना.

खालिदा जिया पिछले साल भारत यात्रा पर आईं थीं. अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया था कि अगर वे अगली बार सत्ता में आईं तो पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को अंजाम देने में कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगी. हालांकि खालिदा की बातों पर विश्वास करना भारत के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कार्यवाहक सरकार के शेख हसीना सरकार के फैसले को देखते हुए खालिदा जिया ने कट्टरपंथियों को फिर से उकसा दिया है, जिससे बांग्लादेश में माहौल फिर से खराब हो गया है. अब तक के अनुभवों से यह जाहिर है कि शेख हसीना का भारत के प्रति दोस्ताना रवैया खालिदा जिया को कभी रास नहीं आया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनके सहयोगी दलों में कट्टरपंथियों के प्रभाव के कारण विदेश नीति को घरेलू राजनीति की प्रतिद्वंद्विता से अलग रखने की परिपक्वता खालिदा जिया कभी नहीं दिखा सकीं, क्योंकि कट्टरपंथी कभी नहीं चाहते कि भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिशें हों. बांग्लादेश के लोगों को यह बात पता है कि भारत के सहयोग से वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है. पिछली बार खालिदा जिया ने खुल कर कट्टरपंथी ताकतों को प्रश्रय दिया था और इसके चलते देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थीं. उन्हें पता है कि बांग्लादेश में चुनाव वह पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी तबके की भावनाएं भड़का कर ही जीत सकती हैं. खालिदा जिया पर यह आरोप भी लगता रहा है कि जब उनकी सरकार थी, तब पाकिस्तान के साथ मिल कर भारत के खिलाफ विध्वंसात्मक गतिविधियों को खूब बढ़ावा दिया गया था. आरोप यह भी है कि चटगांव में पकड़े गए अवैध हथियारों और बड़ी तादाद में कारतूसों से भरे दस ट्रक तत्कालीन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) जमाते इस्लामी की गठबंधन सरकार की शह पर भारत भेजे गए थे. यही कारण है कि बांग्लादेश के भारत के साथ 2007 से बीएनपी-जमात सरकार के कार्यकाल में अच्छे संबंध नहीं रहे. खालिदा जिया के इसी रवैये की वजह से उनके शासनकाल में दोनों देशों के रिश्ते खराब रहे और सुरक्षा के नजरिये से बांग्लादेश भारत के लिए सिरदर्द बना रहा.

इस तरह से हम देखें तो शेख हसीना की बांग्लादेश की सत्ता में फिर से वापसी भारत के लिए फायदेमंद है, जिसकी संभावना भी प्रबल है, क्योंकि खालिदा जिया को उनकी हरकतों के कारण बांग्लादेशियों की एक जमात देशद्रोही भी मानती है, जो किसी भी नेता के लिए उसके चुनावों में हार की बड़ी वजह बन सकती है.

हमारे यहां भी लोकसभा चुनाव होनेवाले हैं. ऐसे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन हर सरकार को अपने निजी स्वार्थों और वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर देश हित के बारे में सोचना होगा. बांग्लादेश से संबंध का अच्छा या बुरा होना, काफी हद तक भारत की विदेश नीति पर भी निर्भर करता है. संबंधों को नये आयाम देने के लिए भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ अपनी सारी समस्याओं को बिना किसी घरेलू दबाव के सुलझाने की कोशिश करे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जब भी कोई समस्या सामने आती है तो उस पर घरेलू राजनीति होनी शुरू हो जाती है, जो किसी के हित में नहीं है. तिस्ता जल विवाद पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से रोड़ा बनीं, यह सभी को पता है. चूंकि दोनों देशों को एक-दूसरे की जरूरत है, इसलिए ये देश हमेशा विवादों में उलझ कर नहीं चल सकते. जरूरत है सहयोग के रास्ते पर चलने की. भारत विश्व राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है और दूसरी तरफ उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ अनबन भी रहती है. ऐसे में वह विश्व महाशक्तियों के बीच मजबूती से कैसे अपना पक्ष रख सकता है. ■

बांग्लादेश में आम चुनाव सामने है. उम्र कैद की सज़ा पाए जमात के नेता अब्दुल कादर मौला को मीरपुर का कसाई कहा जाता है. कट्टर पार्टी जमात का बांग्लादेश की राजनीति में चार प्रतिशत वोट है. जमात की तरह जितनी भी पार्टियां हैं मसलन बीएनपी, वह सब शेख हसीना को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसीलिए वे एक-दूसरे के साथ मिल गई हैं. ऐसे में यह साफ़ है कि बांग्लादेश में उदारवादी अवामी लीग की सरकार का बने रहना कितना महत्वपूर्ण है.

feedback@chauthiduniya.com

साई

बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबड़ाओ नहीं, शान्त चित्त से बेलापुर में चार दिन सुखपूर्वक रहकर सब सम्बंन्धियों से मिलो और उसके बाद शिरडी आ जाना. बाबा के शब्द इतने सामयिक थे कि निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई. हस्तरेखा ज्ञाता होने के कारण मुले शास्त्री ने बाबा से उनका हाथ देखने की प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने उनकी प्रार्थना न सुनकर उन्हें चार केले दिए उसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए.

एक बार...

साई के लिए सब एक समान

चौथी दुनिया ब्यूरो

हम सभी जानते है कि ईश्वर का अवतार मानव कल्याण और दुष्टों के संहार के लिए होता है. भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर हमेशा उपस्थित रहते हैं. साई बाबा भी उसी कोटि में है, जो कि भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए थे. वे ज्ञानज्योति स्वरुप थे और उनकी दिव्यप्रभा अपूर्व थी . उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था .वे निष्काम तथा नित्यमुक्त थे. उनकी दृष्टि में शत्रु,मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे. भक्तों के लिये सदैव सहायता के लिये तत्पर रहते थे. उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच नहीं सकता था.

आज भारत में जितने योगी, साधु-सन्यासी तथा सिद्ध पुरुष हुए हैं. उनमें शिरडी के साई बाबा का नाम सबसे ऊपर है. उनके भक्तों और अनुयायियों की इतनी बड़ी संख्या का प्रमुख कारण है. साई बाबा में उनका अटूट विश्वास है. साई बाबा के भक्त उनको सबका मालिक एक मानकर पूजा करते हैं. संसार में सैकड़ों आध्यात्मिक संत, गुरु, अवतार, औलिया और दिव्य चमत्कारी व्यक्तित्व हुए हैं, लेकिन आज भी कई जीवित संत हैं, जो मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं. सभी के अनुसार प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक-सी है, आत्मा परमात्मा की चिंगारी है, जो परमात्मा से ही निकली है और पुनः उन्हीं में लौटकर विलीन हो जाती है. साई बाबा ही ऐसे एकमात्र अवतार पुरुष हुए जिन्होंने यह प्रयोग कई बार करके दिखलाया है कि कैसे प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक-सी है.

हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानव कल्याण और दुष्टों के संहार के लिए होता है. साई बाबा भी उसी कोटि में है, जो कि भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए थे. वे ज्ञानज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्यप्रभा अपूर्व थी. उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था. वे निष्काम तथा नित्यमुक्त थे. उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे. भक्तों के सहायता के लिये सदैव तत्पर रहते थे. उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच नहीं सकता था. अनेक व्यक्तियों की श्री साई बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका. अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शनलाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साई लील-ाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साई-दर्शन की इच्छा पूरी हो जाएगी. भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकता था. इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहां रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था. अतः यह सब उनकी शुभ इच्छा के अनुसार ही होता था.

एक समय काका महाजनी मुंबई से शिरडी पहुंचे. उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था. दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे. उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य-सा हुआ. उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिये उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें. बाबा ने अगले दिन जाने को कहा. बाबा के शब्द कानून थे, जिनका पालन करना आवश्यक था. काका महाजनी ने तुरन्त ही प्रस्थान किए. जब वे मुंबई अपने आफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया. मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिथति अनिवार्य हो गई थी. सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिये भेजा था, वह मुंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया .

दूसरी कथा इस प्रकार है एक बार भाऊसाहेब धुमाल एक मुकदमे के सम्बन्ध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे. मार्ग में वे शिरडी उतरे. उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परन्तु बाबा का आदेश प्राप्त नहीं हुआ. उन्होंने उनको शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया. इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उदर-पीड़ा से ग्रस्त हो गए और इस कारण उनका मुकदमा अगले दिन के लिए बढ़ाया गया. एक सप्ताह बाद भाऊसाहेब को लौटने की अनुमति मिली. इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और चार न्यायाधीशों के पास हुई. फलस्वरुप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया. श्री नाना साहेब निमोणकर जो निमोण के निवासी और न्यायधीश थे और शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे. निमोणकर तथा उनकी पत्नी बहुत-सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे. एक बार ऐसा हुआ कि उनका पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, लेकिन नानासाहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा. वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन बाबा ने सहायता की. शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई और बाबा साठेवाड़ा के समीप नानासाहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े थे. उन्होंने जाकर चरणवन्दना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी. बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबड़ाओ नहीं, शान्त चित्त से बेलापुर में चार दिन सुखपूर्वक रहकर सब सम्बन्धियों से मिलो और उसके बाद शिरडी आ जाना. बाबा के शब्द कितने सामयिक थे कि निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई. हस्तरेखा ज्ञाता होने के कारण, मुले शास्त्री ने बाबा से उनका हाथ देखने की प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने उनकी प्रार्थना न सुनकर उन्हें चार केले दिए उसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए. अब मुले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए. बाबा भी अपने नियमानुसार लेण्डी को पवाना जाते-जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरु लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे. बाबा के शब्दों का अभिप्राय कोई समझ न सका. कुछ समय के बाद बाबा लौटे. अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारम्भ हो गई थी. बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्तों ने उनकी पूजा की. अब आरती प्रारम्भ हो गई. बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ. बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का सन्देश मुले शास्त्री को सुनाया. वे बुरी तरह घबड़ा गए. वे सोचने लगे कि मैं तो एक अग्निहोत्री ब्राहमण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है.

माना कि बाबा महान संत है, लेकिन मैं तो उनका शिष्य नहीं हूं. फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी लेने को आए हैं तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं. इसलिए वे अपने काम को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को गए. वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर, अलग खड़े हो गए और दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर फूल फेंके. एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी विराजमान हैं. अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ. कहीं यह स्वप्न तो नहीं है. मैं पूर्ण जागृत हूं, लेकिन जागृत होते हुए मेरे गुरु महाराज यहां कैसे आ पहुंचे. कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला. उन्होंने अपने को चिकोटी ली और पुनः विचार किया. परन्तु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहंचे. फिर सब सन्देह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे. दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परन्तु मुले शास्त्री अपने गुरु के नाम की ही गर्जना कर रहे थे. फिर सब जाति-पांति का अहंकार तथा पवित्रता अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों पर पुनः गिर पड़े

उन्होंने आंखें मुद ली, लेकिन खड़े होकर जब उन्होंने आंखे खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा. बाबा का आनन्दस्वरुप और उनकी शक्ति देख मुले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए. उनकी आंखे आंसुओं से भरी हुई थी फिर भी प्रसन्नता से नाच रही थी. उन्होंने बाबा को नमस्कार किया और दक्षिणा दी. मुले शास्त्री कहने लगे कि मेरे सब संशय दूर हो गए. आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए. बाबा की अद्भूत लीला देखकर सब चकित रह गए. साई बाबा के सभी भक्त उनके लिए एक समान है. वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. ■

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

अकेलापन घातक है

डॉ. अभय बंग

मार्लन ब्रैंडो की आन द वाटर फ्रंट नामक फिल्म की आस्कर विजेता भूमिका में एक मार्मिक नाम वाक्य है. ब्रैंडो कहता है तुम्हें मालूम नहीं चार्ली मैं भी कोई बन सकता था. मैं जो हूं उसके बजाय कुछ और बनने की मुझे इच्छा है. मैं अभी, इसी क्षण (कोई) तो हूं ही, परन्तु उसमें मुझे संतोष नहीं है.

डॉ. शेरविट्ज व पावेल द्वारा किए गए अध्ययन से बहुत सी दिलचस्प बातें सामने आईं. उन्होंने हृदय के रोगियों का साधारण वार्तालाप व गप्पें टेप कीस्त्रउसके बाद उसमें मैं मेरा मुझको ऐसे स्वयं सम्बंधी जितने उल्लेख थे उन्हें गिना. जो स्वयं में अधिक उलझे हुए थे, जिनकों विचारों एवं संवादों में मैं की उल्लेख अधिक बार था, उनकों आगे हृदय रोग का दौरा अधिक बार परिमाण में आया.

यह मैं हृदयघात प्रतीत होता है, परन्तु क्यों?

दूसरों से दूरी का निर्माण करने वाली बातें मनुष्य में एकाकीपन एवं तनाव का निर्माण करती हैं व उससे कई बार हृदयरोग का सूत्रपात होने लगता है. इसके विपरीत मुनष्य में प्रेम व रिश्ता निर्माण करने वाली बातें मनुष्य को निसर्ग से, विश्व से जोड़ने वाली बातें उसके हृदय को बचाती हैं. मनुष्य का मनुष्य से तो छोड़ें, पालतू जानवर पेड़-पौधों से भावनात्मक नाता भी उसको हृदय रोग से संरक्षण देता है, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात होता है.

संबध मनुष्य को प्रिय होते हैं, इतना ही नहीं, बल्कि एरिक फ्राम नामक विख्यात मनोवैज्ञानिक के अनुसार वह उसके जीने की मूलभूत आवश्यकता है. व्यक्ति केन्द्रित व स्पर्धात्मक आधुनिक सभ्यता (अर्थात अमेरिकन सभ्यता) में मनुष्य अकेला पड़ता जाता है. भीड़ में होते हुए भी अकेला. एक-दूसरे प्रतिस्पर्धी. घर के बाहर व्यावसायिक स्पर्धा, घर में पति-पत्नी की एक ही भूमिका के प्रभुत्व के लिए स्पर्धा. अन्त में अधिक सफलता के लिए अपने आपसे भी स्पर्धा-संस्कृति में जीने के लिए मनुष्य को मैं, मेरा इनका ही जप करना पड़ता है. मैं यही सबसे बड़ी विभूति बन जाती है और रात-दिन उसी की पूजा चलती है. आचार्य रजनीश एक कहानी सुनाते थे, वह याद आई. कुत्तों की दुनिया का एक गणमान्य कुत्ता एक बार दिल्ली की पद यात्रा पर निकला. उसके शिष्यों ने उसे समारोह पूर्वक कोलकाता से विदा किया. मंजिल-दर-मंजिल तय करते-करते तीन महीनों में श्वान महाराज दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा कार्यक्रम तय हुआ था. दिल्ली के अनुयायियों ने जोरदार स्वागत करने के लिए स्वागत समिति भी बनाई. चंदा इकट्ठा किया जाने लगा. तीन महीने में कुत्ते महाराज दिल्ली पहुंचेगे, इसलिए स्वागत की तैयारी शुरू हुई, लेकिन अचानक दसवें दिन दिल्ली आ पहुंचे. महाराज आप कितने महान हैं. आपने नब्बे दिन की यात्रा दस दिन में पूर्ण कर ली. कुत्ते महाराज की जय. अनुयायियों ने जयघोष किया.

महाराज आपने यह चमत्कार कैसे किया और आपके शरीर पर इतने जख्म क्यों हैं. मैं दस दिनों में अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा रे. कोलकाता से निकला. पहले पड़ाव पर पहुंचा. थक गया था. आराम किया जाए, कुछ खाया जाए, इस आशा से गांव में घुसा तो उस गांव के कुत्ते भौंकते हुए मेरे पीछे पड़ गए. उनके डर से भाग निकला. कम से कम अगले गांव में तो आश्रय मिलेगा, इस आशा से वहां पहुंचा. वहां के कुत्ते और क्रुर व भयानक निकले. मेरी बोटियां नोचने के लिए कुद पड़े. अरे, कोलकाता से दिल्ली तक किसी भी जगह मुझे ठौर नहीं मिला. मेरी यात्रा शीघ्र पूरी होने का यह रहस्य है. हांफते-हांफते थके-हारे जख्मी कुत्ते महाराज ने बताया.

ऐसे दौड़ने को ही आज के युग में स्पर्धा और दिल्ली पहुंचने को यश कहते हैं. ऐसा सुना है कि वह कुत्ता जल्दी ही हार्ट अटैक से मर गया. विकसित देशों से ली हुई स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था को सफल होने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के स्वार्थ, लोभ व महात्वाकांक्षा को भड़काना पडता है.

उस आग में तेल डालना पड़ता है. उनसे प्रेरित होकर सफलता के लिए बेतहाशा भागते हुए जो मानसिक तनाव होने लगता है. वह हृदयरोग का कारण बन जाता है. दिल्ली, मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में स्पर्धा का जीवन जीने वालों पर तो यह लागू होता ही है. परन्तु गढ़चिरौली के जंगलों में आदिवासियों के बीच स्वास्थ्य का काम करने वाला समाजसेवक भी इससे बच नहीं पाया था.

मार्लन ब्रैंडो की आन द वाटर फ्रंट नामक फिल्म की आस्कर विजेता भूमिका में एक मार्मिक नाम वाक्य है. ब्रैंडो कहता है तुम्हें मालूम नहीं चार्ली मैं भी कोई बन सकता था. मैं जो हूं उसके बजाय कुछ और बनने की मुझे इच्छा है. मैं अभी, इसी क्षण (कोई) तो हूं ही, परन्तु उसमें मुझे संतोष नहीं है. उससे मेरा नाता नहीं है. मुझे दुख है कि मैं और कुछ अलग क्यों नहीं हुआ. उस मृगतृष्णा के पीछे दौड़ने से मेरा स्वयं भी नाता टूट जाता है. मेरे बड़े व सफल होने का अर्थ है-मै दूसरों से किस प्रकार भिन्न अथवा अधिक संपन्न हूं यह सिद्ध करना. दूसरों जैसा, दूसरों में से एक होने का अर्थ तो साधारण होना है. असाधारण होने के लिए मुझे अलग बनना पड़ता है. दूसरों के साथ समानता की बजाय, एकरूपता की बजाय भिन्नता पर जोर देना पड़ता है. इसमें से ही मेरे अकेले पन का सूत्रपात होता है. उस दीवार को मैं दिन-ब-दिन और मजबूत किए जाता हूं. आखिर वह दीवार बनाने वाला मैं स्वयं ही उस भीतर अकेला कैद हो जाता हूं. दूसरों से दूरी और अकेला पन घातक ही होता है. हृदय को मारने वाला होता है. ■

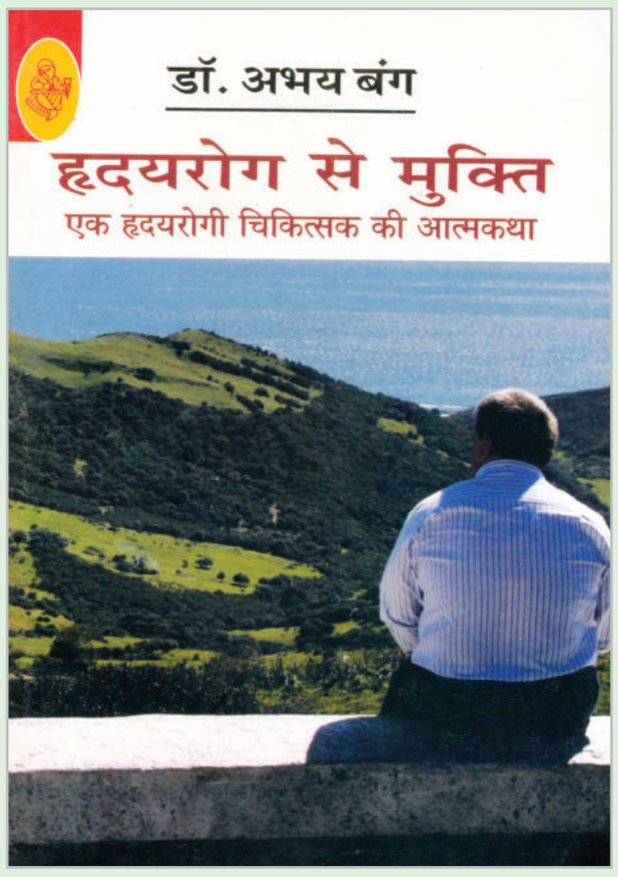

महाराज आपने यह चमत्कार कैसे किया और आपके शरीर पर इतने जख्म क्यों हैं. मैं दस दिनों में अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा रे. कोलकाता से निकला. पहले पड़ाव पर पहुंचा. थक गया था. आराम किया जाए, कुछ खाया जाए, इस आशा से गांव में घुसा तो उस गांव के कुत्ते भौंकते हुए मेरे पीछे पड़ गए. उनके डर से भाग निकला. कम से कम अगले गांव में तो आश्रय मिलेगा, इस आशा से वहां पहुंचा. वहां के कुत्ते और क्रुर व भयानक निकले.

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

साधु और तोता

एक बार एक साधु बाबा ने अपनी कुटिया में कुछ तोते पाल रखे थे और उन सभी तोते को अपनी सुरक्षा हेतु एक गीत सिखा रखा था शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर हम नहीं जाएंगे. एक दिन साधु बाबा भिक्षा मांगने हेतु पास ही के एक गांव में गए. इसी बीच एक बहेलिया वहां उसने देखा कि एक पेड़ पर अनेक तोते बैठे हैं, उसे उन पक्षियों को देख उसे लालच हुआ. वह उन सभी तोते को पकड़ने की योजना बनाने लगा कि तभी तोते एक साथ गाने लगे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा पर हम नहीं जाएंगे. बहेलिया ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गया !! उसने इतने समझदार तोते कहीं देखें ही नहीं थे, उसने सोचा इन्हे पकड़ना असंभव हैं ये तो प्रशिक्षित तोते लगते हैं. बहेलिया को नींद आ रही थी, उसने उसी पेड़ के नीचे अपने जाल में कुछ अमरूद के टुकड़े रख दिए और सो गया, सोचा कि संभवतः कोई लालची और बुद्धू तोता फंस जाए. एक घंटे उपरांत जब वह सोकर उठा, तो देखा कि सारे तोते एक साथ गा रहे थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा पर हम नहीं जाएंगे. पर कहां गा रहे थे जाल के अंदर ! शिकारी उन सब बुद्धू तोते की हाल देख हंस पड़ा और सब को पकड़ कर ले गया. ■

शिक्षा: लालच बुरी बला

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

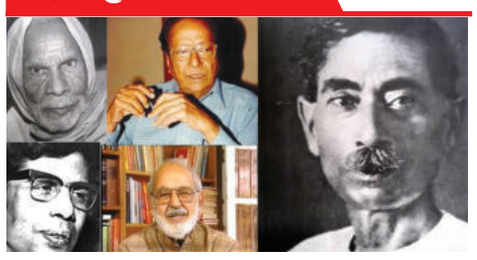

> महात्मा गांधी ने भी 15 अगस्त, 1947 को बीबीसी को दिए एक संदेश में साफ तौर पर कहा था–समाज की जो हम सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, वह यह है कि हमने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के प्रति जो अंधविश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है, उससे स्वयं मुक्त हों और समाज को मुक्त करें.

गांधी जयंती पर विशेष

हिंदी की उपेक्षा क्यों?

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में यह माना जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल की पहली समीक्षा नलिन विलोचन शर्मा ने लिखी थी. लेकिन यह तथ्य नहीं है. फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल' की पहली समीक्षा 15 जुलाई, 1955 के टाइम्स ऑफ इंडिया में अ नॉवेल ऑफ रूरल बिहार शीर्षक से छपी थी और उसे शाम लाल ने लिखा था. उसी लेख से यह भी पता चलता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का यह उपन्यास पहले समता प्रकाशन, पटना ने छापा था और बाद में वो राजकमल प्रकाशन से छपा. आज़ादी के बाद के कई दशक तक अंग्रेज़ी के अख़बारों में हिंदी लेखकों की किताबों पर गंभीर लेख छपा करते थे. स्वयं शाम लाल जैसे अंग्रेज़ी के संपादक ने प्रेमचंद, जैनेंद्र, मुक्तिबोध और निर्मल वर्मा की किताबों पर विस्तार से लिखा, साथ ही उस दौर के कवि और कविताओं पर भी गंभीर लेख लिखा था. शाम लाल तो हिंदी कवियों पर कविता की नई प्रवृतियों पर अस्सी के दशक तक लिखते रहे. उन्होंने भोपाल की एक कवि गोष्ठी के बहाने से पहला सप्तक से लेकर उस वक्त तक की कविताओं पर एक आलोनात्मनक लेख अंग्रेज़ी में लिखा था. उस लेख को पढ़कर गैर–हिंदीभाषी लोग भी हिंदी कवि नेमिचंद्र जैन से लेकर श्रीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण साही से लेकर रघुवीर सहाय की कविताओं से परिचित हो सकते हैं. शामलाल के अलावा अन्य अंग्रेज़ी अख़बारों के संपादक और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी श्रीकांत वर्मा से लेकर अज्ञेय के रचनाकर्म पर गंभीरता से विमर्श किया है.

वह दौर था, जब हिंदी के आयोजनों में अंग्रेज़ी के संपादकों और लेखकों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन सत्तर के दशक के मध्य से अंग्रेज़ी का हिंदी के प्रति भाव उदासीन होने लगा. अंग्रेज़ी अख़बारों में हिंदी के लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों और उनके रचनाकर्म पर छपना कम होता चला गया. जिन अख़बारों में मुक्तिबोध की मृत्यु की ख़बर मुखपृष्ठ पर फोटो के साथ छपी थी, उसी अख़बार ने श्रीलाल शुक्ल की मौत की ख़बर को अंदर के पन्ने पर छोटी सी जगह दी. जो अंग्रजी के लेखक हिंदी की किताबों पर लिखते थे, उन्होंने कन्नी काटनी शुरू कर दी. यह एक बहुत गंभीर सवाल है. आज हम साहित्य के पाठकों की कमी के लिए छाती कूटते हैं, लेकिन उस कमी के मूल कारण में नहीं जाते हैं. आज हम कोई ऐसा उपक्रम नहीं कर रहे हैं जिससे नया पाठक वर्ग संस्कारित हो सके.

आज हिंदी के लेखकों में इस बात को लेकर ख़ासा क्षोभ दिखाई देता है कि उनको मीडिया, ख़ासकर अंग्रेज़ी मीडिया में जगह नहीं मिलती. हालात यह है कि बड़े से बड़ा हिंदी का कवि या लेखक बड़े से बड़ा पुरस्कार पा जाए, उसकी नई कृति आ जाए और वो हिंदी समाज में चर्चित हो जाए या फिर किसी स्थापित लेखक या बुजुर्ग लेखक का निधन हो जाए, अंग्रेज़ी के अख़बार या न्यूज़ चैनल उसकी नोटिस ही नहीं लेते हैं. अव्वल तो ख़बर नहीं ली जाती या फिर अगर ली भी जाती है तो उसको ऐसी जगह दी जाती है, जो एकदम से महत्वहीन होती है और

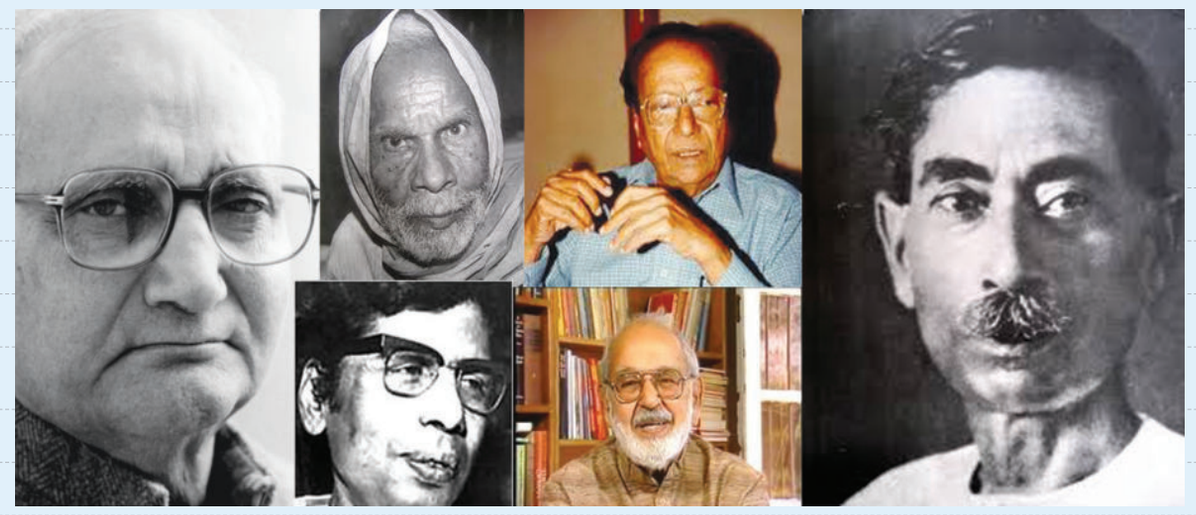

पाठकों की नज़र वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है. हां, अगर लेखक फ़िल्मों से जुड़ा हो या फिर उसकी कोई साहित्येत्तर पहचान हो तो अंग्रेज़ी मीडिया उसको जमकर तवज्जो देता है. कमलेश्वर जी के निधन के बाद अंग्रेज़ी के अख़बारों ने उनपर श्रद्धांजलि के लेख इस वजह से छापे कि वो हिंदी के साहित्यकार के अलावा फिल्म लेखन और दूरदर्शन के शुरुआती दौर से जुड़े थे. थोड़ा बहुत श्रीलाल जी के निधन पर भी अंग्रेज़ी अख़बारों ने छापा. हम कह सकते हैं कि यह स्थिति अचानक से पैदा नहीं हुई. इसके पीछे के कारणों को ढूंढना होगा. आज अगर आप अपनी भाषा और संस्कृति की बात करेंगे तो आपको फ़ौरन से पेशतर संघी क़रार दे दिया जाएगा और वो भी इस तरह से कि आपको लगेगा कि कोई जुर्म हो गया. गोया कि अपनी भाषा और संस्कृति के विकास की बात करना और उसपर गर्व करना गुनाह हो. हुआ यह कि हमने अपनी भाषा और उसकी ताक़त पर गर्व करना छोड़ दिया. इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी भाषा के लोगों को लगने लगा कि हिंदी और हिंदुस्तान की संस्कृति की बात कहने से उनपर भी एक ख़ास किस्म का ठप्पा लग जाएगा. लिहाजा अंग्रेज़ी के लोगों ने हिंदी से किनारा करना शुरू कर दिया.

महात्मा गांधी ने भी 15 अगस्त 1947 को बीबीसी को दिए एक संदेश में साफ तौर पर कहा था–समाज की जो हम सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, वह यह है कि हमने अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा के प्रति जो अंधविश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है, उससे स्वयं मुक्त हों और समाज को मुक्त करें, लेकिन हिंदी समाज ने गांधी की इस बात को नहीं माना और अंग्रेजी के प्रति लगातार हमारा अंधविश्वासपूर्ण सम्मान बढ़ता चला गया. नतीजा यह हुआ कि हम अपनी भाषा को छोड़कर एक विदेशी भाषा में प्रतिष्ठा तलाशने लगे. अंग्रेज़ी को लेकर हिंदी के लोगों में एक ख़ास किस्म की हीन भावना घर कर गई. धड़ल्ले से हिंदी बोलने वाले लोग भी जब किसी मॉल की भव्य दुकान के अंदर जाते हैं तो वहां घुसते ही एक्सक्यूज मी का जयकारा लगाते हैं. शानदार हिंदी बोलने वाले भी टूटी–फूटी अंग्रेज़ी बोलकर अपने को धन्य समझते हैं. इस तरह के वातावरण को देखकर अंग्रेज़ी वालों के मन में हिंदी वालों के प्रति एक उपहास का माहौल बना जो कालांतर में उनको हिंदी साहित्य से दूर लेकर चला गया. इस मानसिकता को प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने बेहतरीन तरीक़े से व्यक्त किया– हमारे अंग्रेज़ी बोलने और सोचने से हमारे दिमाग़ पर इतना बोझ पड़ता है कि हम उससे कभी पूरी तौर पर मुक्त नहीं हो पाते हैं.

हिंदी में कुछ शुद्धतावादी लेखक भी इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं. जब भी जहां भी मौक़ा मिलता है वो हिंदी के नाश के लिए अंग्रेज़ी को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं. उन्हें लगता है कि अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग से हिंदी का नाश हो जाएगा. उनकी ये चिंता जायज़ हो सकती है, लेकिन हिंदी के प्रयोग के आग्रह में वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि अंग्रेज़ी को दुश्मन की तरह पेश करने में जुट जाते हैं. जोश में होश खोते हुए अंग्रेज़ी भगाओ तक का नारा देने में जुट जाते हैं. अंग्रेज़ी के साइनबोर्ड तक पर कालिख पोतने का दौर चलाने लग जाते हैं. इससे नफ़रत का माहौल बनता है. इस तरह की बात अंग्रेज़ी के लोगों तक पहुंचेंगी तो उनकी स्वाभावित प्रतिक्रिया हिंदी को शांति से दरकिनार करने की होगी. आज अगर अंग्रेज़ी के लोग हिंदी को लेकर तटस्थ हैं तो उसके पीछे यह भी एक बड़ी वजह है. आज वक्त आ गया है कि हिंदी को मज़बूत करने के साथ–साथ हमें अंग्रेज़ी के प्रति दुश्मनी के भाव को त्यागना होगा. हिंदी साहित्य के मूर्धन्यों को अंग्रेज़ी के प्रति घृणा का भाव त्यागना होगा. साथ ही अपनी भाषा और संस्कृति पर हमें गर्व करना ही होगा. हमें दूसरों को इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि हिंदी पर लिखे बिना तुम्हारा काम चलनेवाला नहीं है. अपने रचनात्मक विस्फोट से उनका ध्यान खींचना होगा. हिंदी के लिए यह ज़रूरी है कि वो किसी भाषा से नफ़रत न करे और न ही उसके प्रति अंधविश्वासपूर्ण सम्मान प्रदर्शित करें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)
anant.ibn@gmail.com

कविता

एक इतवार का दिन

चेतन कश्यप

इतवार की सुबह...
देह की घड़ी को
मालूम है
आज हड़बड़ी नहीं है
पड़े-पड़े बिस्तर पर
सीधे हो रहे देह-हाथ

आईने में शक़्ल देखी है
चला गया है ध्यान
कान पर चढ़ गए हैं बाल
और अब
अमिताभ बच्चन का फ़ैन दिखने की
उमर भी नहीं रही

सैलून में
गद्दे वाली कुर्सी पर
सर को टिकाए हुए पीछे
गले तक लिपटा हुआ चादरनुमा तौलिया
बैठा हूं आराम से पैर पसारे
मारी गई है फुहार पानी की
चेहरे पर, मुंद गईं हैं आंखें...

कितना सुकून है
अहा!

फिर रही है कंघी बालों में,
थिरक रही है कैंची
कट के गिर रहे हैं
लच्छे के लच्छे बालों के
और लगता है मानो
गिरा जा रहा हो दबाव-तनाव
झर रही हो जैसे
कंधों से सब थकान
आऽऽ हाऽऽ! आऽऽ हाऽऽ!
नींद-सी छाई जा रही है आंखों पर
दूर कोलाहल से, चिंताओं से परे...

फिर से पानी की फुहार चेहरे पर
यानी समय समाप्ति की घोषणा
वापसी की तैयारी फिर से
उसी दिनचर्या में, गो थोड़े हल्के-से
तन-मन से.

गांधी जयंती पर विशेष

सेवाग्राम के दर्शन

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार भारत को भी युद्ध में झोंक दिया. देश भर में इसका विरोध हो रहा था. गांधी जी स्वराज्य की मांग और युद्ध के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे. क्रांतिकारी लेखक यशपाल उस दौरान गांधी जी से मिलने सेवाग्राम गए. गांधी जी द्वारा साम्राज्य–विरोधी युद्ध और स्वराज्य के सार्वजनिक उद्देश्यों से चलाए गए आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप देने और इसके लिए भगवान में विश्वास की शर्त लगाने जैसे सवालों पर यशपाल ने गांधी जी से चर्चा की थी और बाद में लौटकर उस पर लेख लिखा. दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पेश है उस लेख का कुछ अंश...

यशपाल

दूसरा महायुद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की इच्छा के विरुद्ध देश को उस युद्ध में लपेट लिया. सभी राजनीतिक दल युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध थे. मैं उन दिनों *विप्लव* का संपादन कर रहा था. मध्य प्रदेश के वामपक्षी लोगों ने युद्ध के विरोध में आंदोलन को सार्वजनिक रूप देने की मांग के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया. इसी प्रसंग में मैं नागपुर गया था. नागपुर पहुंच कर सेवाग्राम का दर्शन करने की इच्छा हुई. गांधी जी के मुख से ही समझना चाहता था कि साम्राज्य–विरोधी युद्ध और स्वराज्य के सार्वजनिक उद्देश्यों वाले आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप देकर व्यक्तिगत प्रश्न क्यों बनाया जा रहा है? मेरे यजमान पीवाई देशपांडे और कामरेड मोटे भी साथ चले.

हम लोग सेवाग्राम जा पहुंचे. वहां देखा लंबे–चौड़े, धूप से तपते हुए मैदान में दो–तीन वृक्ष हैं. कुटियाएं मामूली तौर पर फूस की हैं. गांधी जी की कुटिया और आश्रम के अस्पताल की दीवारें अलबत्ता मिट्टी की हैं. कुटिया की छत अच्छी मोटी–भारी और मजबूत है. आश्रम में कोई छाया का स्थान न था इसलिए धूप में ही घूमना पड़ा. कुछ मिनट में उनके सेक्रेटरी मशरूवाला ने सूचना दी कि मुलाकात अभी हो सकती है.

गांधी जी की कुटिया ख़ूब ठंडी थी. कुटिया में फ़र्श पर एक ओर बिस्तर लगा था. बिस्तर पर गांधी जी लेटे हुए थे. दूसरी ओर दर्शनार्थ आने वाले सज्जन बैठे थे. सिरहाने मशरूवाला और कृपलानी बैठे थे. गांधी जी के चरणों के समीप बैठी एक बेन छत से लगे हल्के पंखे को जल्दी–जल्दी खींच रही थीं. गांधी जी की दृष्टि के सामने हम लोग भी जा बैठे. एक भीगा कपड़ा गांधी जी के सिर पर, दूसरा पेट पर और एक चिंदी उनकी पांव की उंगली पर बंधी हुई थी. वे चित्त लेटे हुए थे. हमारे आदरपूर्ण नमस्कार का उत्तर गांधी जी ने हाथ जोड़कर दिया. देशपांडे ने बात शुरू की– महात्मा जी, आपकी तबियत तो ठीक है?

तबियत खराब नहीं है– महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह सब स्वस्थ्य बिगड़ने न देने की सावधानी है. यह विश्वास हो जाने पर कि महात्मा जी की तबियत ठीक है, उनकी आज्ञा ले प्रश्न किया– स्वराज्य की मांग राजनीतिक आंदोलन है. राजनीतिक उद्देश्य से स्वराज्य या युद्ध–विरोध पूरे देश की समस्या है. इस आंदोलन को व्यक्तिगत प्रश्न या व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप दे देना कैसे उचित हो सकता है? ऐसा सत्याग्रह करने के लिए भगवान में विश्वास की शर्त लगाना ठीक नहीं. भगवान में विश्वास सार्वजनिक या राजनीतिक प्रश्न नहीं, सांप्रदायिक और व्यक्तिगत प्रश्न है. ऐसी शर्त लगा देने से अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्ता, जो राजनीतिक उद्देश्य से जनहित के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, अहिंसात्मजक आंदोलन की नीति को स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं, सत्याग्रह और आंदोलन में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं. राजनीतिक आंदोलन में भगवान पर विश्वास की धार्मिक या सांप्रदायिक शर्त लगाना कहां तक ठीक है? गांधी जी ने उत्तर दिया–ईश्वर पर विश्वास को आवश्यक समझने के दो कारण हैं. प्रथम तो यह कि सत्याग्रही के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत भगवान के सिवा दूसरा नहीं है. निशस्त्र होकर और शारीरिक रूप से निर्बल होकर भी भगवान के भरोसे ही सत्याग्रही भय का सामना कर सकता है. दूसरा कारण है कि इस समय सत्याग्रह का मार्ग दिखाने का काम मैं ही कर रहा हूं. आशा नहीं कि मैं अधिक दिन तक जी सकूंगा. मेरी ग़ैरहाज़िरी में सत्याग्रहियों को कौन मार्ग दिखाएगा? अपनी ग़ैरमौजूदगी में सत्याग्रहियों से आशा करूंगा कि वे भगवान पर विश्वास कर अपना मार्ग निश्चित करें. इस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप भी इसलिए दिया गया है कि इसमें वे ही लोग भाग लें जिनपर मैं विश्वास कर सकता हूं.

फिर प्रश्न किया– भगवान पर विश्वास करने का उपदेश आप शक्ति और साहस प्राप्त करने के लिए देते हैं, परंतु जो लोग किसी दूसरी शक्ति और साहस प्राप्त करने की आवश्यकता न समझकर स्वयं अपने ऊपर भरोसा करते हैं, उन्हें आप क्यों विश्वास के अयोग्य ठहरा देते हैं? ऐसे व्यक्ति को तो अधिक साहसी समझा

जाना चाहिए. आपके सामने भगत सिंह का उदाहरण है. उसे भगवान से सहारा पाने की आवश्यवकता नहीं थी. जिन्हें आप शारीरिक रूप से निर्बल समझते हैं, उन्हें यदि शारीरिक शक्ति से संघर्ष न कर केवल दृढ़ निश्चय द्वारा अत्याचारी के अत्याचार को सहना है तो उनकी शारीरिक निर्बलता उन्हें सत्याग्रह के मैदान में अयोग्य नहीं बना सकती. जिसे आप भगवान की प्रेरणा कहते हैं, वह भी तो हमारी अपनी ही बुद्धि की समझ और विश्वास है. ईश्वर की प्रेरणा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के विश्वास व संस्कार के अनुसार बदलती रहती है. उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?

गांधी जी ने कहा– मनुष्य को स्वयं अपने से बड़ी शक्ति पर ही भरोसा करना ठीक है. मनुष्य का विवेक भरोसे के योग्य वस्तु नहीं. मैं कह देना चाहता हूं कि आपके मार्ग से सफलता न मिल सकेगी. अनेक कम्युनिस्टों ने मेरे सामने यह स्वीकार किया है.

देशपांडे बोले–महात्मा जी, हम भी आपको निश्चय दिला देना चाहते हैं कि आपका मार्ग किसी भी अवस्था में सफल नहीं हो सकता. दूसरे मार्ग तो इतिहास में अनेक बार सफल हुए हैं, परंतु यह मार्ग कभी सफल नहीं हुआ. मैंने टोक दिया–महत्मा जी, कम्युनिस्टों या दूसरे ऐसे लोगों के लिए, जो भगवान के बजाय विज्ञान पर विश्वास करते हैं, मार्ग सीधा है. उनका मार्ग अपनी बुद्धि से निश्चित किया हुआ है. यदि एक मार्ग से उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वे अपना मार्ग बदल सकते हैं परंतु जो व्यक्ति भगवान की प्रेरणा से मार्ग ग्रहण करता है, उसके लिए मार्ग बदलने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि भगवान ने उसे गलत प्रेरणा दी. वह आपके विश्वास में गलत राह को ही ठीक मान कर अपनी शक्ति समाप्त कर देगा. गांधी जी ने स्वीकार किया– नहीं, भगवान की प्रेरणा को समझने में भी कभी गलती हो सकती है और उस गलती को संभाला भी जा सकता है. मनुष्य भगवान की प्रेरणा को अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है.

हम लोगों को संतोष न हुआ. फिर शंका की– यदि प्रेरणा को गलत या सही समझना मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है, तो मनुष्य की बुद्धि ही प्रधान वस्तु है. भगवान की प्रेरणा यदि मनुष्य की बुद्धि पर ही निर्भर करती है तो यह भी मुमकिन है कि मनुष्य की बुद्धि जैसे आवश्यकतानुसार और पदार्थों को बना लेती है उसी प्रकार भगवान की प्रेरणा को गढ़ सकती है. उसके लिए भगवान का अस्तित्व होना जरूरी नहीं है. वह तो कल्पना की बात है. ऐसी काल्पनिक बात को ठोस राजनैतिक आंदोलन का आधार बनाना और उसके आधार पर कुछ लोगों को, जो ईमानदारी से अपनी बुद्धि का निश्चय मानकर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, राजनीतिक क्षेत्र से बाहर ढकेल देना कहां तक उचित है? भगवान में विश्वास एक सांप्रदायिक बात है. कांग्रेस के आंदोलन में सांप्रदायिकता की शर्त जोड़ना क्या कांग्रेस पर सांप्रदायिक तानाशाही जमा देना नहीं? गांधी जी ने गंभीर मुद्रा में प्रश्न किया– तो आपको इसमें क्या एतराज है?

–हमें इसका प्रयोजन ऐसे सचेत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कांग्रेस से निकाल देना जान पड़ता है जो आपकी सांप्रदायिक तानाशाही को आंख मूंद कर मानने के लिए तैयार नहीं हैं. गांधी जी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा. उन्होंने कुछ और कहना आवश्यक न समझा. उपस्थित सज्जनों ने करवटें बदलीं, मानो वे उकता गए हों. हम समझ गए, हमारी बातचीत या उपस्थिति यहां खल रही है. आदरपूर्ण नमस्कार किया और उठ खड़े हुए. गांधी जी का मुख अब भी दीवार की ओर ही था. वे शायद हमें भूल चुके थे और दूसरी ही बात सोच रहे थे. उन्होंने हमारे नमस्कार का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा. ■

जेनसेटमार्ट.कॉम वेब पोर्टल के माध्यम से आप भारत में सोलर और जेनरेटर उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही 56 कंपनियों के तकनीकि विशेषज्ञों से सीधे चैट कर ऊर्जा से संबंधित किसी भी परेशानी का हल पा सकते हैं.

पोर्टेबल स्पीकर्स से पाएं बेहतरीन साउंड

एक समय था, जब संगीत के दीवानों के लिए रेडियो ही एक मात्र साधन था, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में संगीत आप चलते-फिरते कहीं भी, कभी भी सुन सकते हैं. डिजिटल दुनिया में मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, म्यूजिक प्लेयर, आईपॉड जैसे डिवाइसेज के ज़रिए आप म्यूजिक को अपने साथ लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जब आपको पूरे परिवार के साथ गाने सुनना हो या छोटी-मोटी पार्टी कर रहे हों और आपको म्यूजिक ऑन करना हो तो इन गैजेट्स की आवाज़ धीमी पड़ जाती हैं. कुछ समय से भारतीय बाज़ार में ब्लूटुथ, एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) आधारित पोर्टेबल स्पीकर्स ने काफ़ी धूम मचा रखी है. आप अपने मोबाइल फोन के ज़रिये संगीत इन शानदार पोर्टेबल स्पीकर्स पर प्ले कर सकते हैं. यह स्पीकर ब्लूटुथ के ज़रिए आसानी से मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं. आवाज़ में शानदार और साइज में छोटे इन स्पीकर्स को आसानी से कैरी किया जा सकता है. हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे पोर्टेबल स्पीकर्स के बारे में जो आपको शानदार परफॉर्मेंस देंगे, वो भी आपके बजट में...

1 जेबीएल फ्लिप 2 ब्लूटुथ स्पीकर

स्पीकर, हैंडफोन, डॉक सिस्टम में जेबीएल एक जाना-पहचाना नाम है. कंपनी का जेबीएल फ्लिप 2 ब्लूटुथ स्टीरियो स्पीकर भारतीय बाज़ार में मौजूद है. इस पोर्टेबल स्पीकर को आप ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल फोन के ज़रिए प्ले कर सकते हैं. फ्लिप 2 ब्लूटुथ स्पीकर लिऑन रिचार्जेबल बैटरी पर काम करता है, जो 5 घंटे तक बैकअप देने में सक्षम है. इसके अलावा, इसमें बिल्ट-इन माइक्रोफोन, कॉल-आंसर बटन वगैरह की सुविधा भी दी गई है. ऑनलाइन स्टोर पर इसकी क़ीमत 4,699 रुपए है. ■

2 लॉजीटेक मिनी बूम बॉक्स

कंप्यूटर एक्सेसरी बनाने वाली कंपनी लॉजीटेक ने बाज़ार में कई पोर्टेबल स्पीकर्स उतारे हैं. लॉजीटेक मिनी बूम बॉक्स कंपनी के शानदार पोर्टेबल प्रोडक्ट्स में से एक है, जो ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ काम करता है. कंपनी ने इसके ऊपरी पैनल में लाल इंडिकेशन लाइट्स को शामिल किया है, जो आपको अलग-अलग दिशा-निर्देश देती हैं. इसके अलावा, इससे आप वॉल्यूम और गानों को भी नियंत्रित कर सकते हैं. इसकी क़ीमत 3,599 रुपये है. ■

3 सौनी एसआरएस-बीटीवी 5 ब्लूटुथ

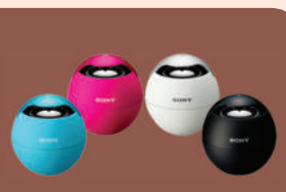

पोर्टेबल वायरलैस स्पीकर में में सोनी अपनी अलग पहचान रखता है. सोनी के शानदार लुक और डिजाइन वाले एसआरएस-बीटीवी5 ब्लूटुथ का जिक्र न हो तो बात नहीं बनती. सोनी ने लगभग साल भर पहले इस स्पीकर को लॉन्च किया था. सोनी के इस पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर की ख़ास बात यह है कि आप इसे ब्लूटुथ के अलावा एनएफसी के ज़रिए भी प्ले कर सकते हैं. माइक्रोयूएसबी के ज़रिए इस स्पीकर को चार्ज किया जा सकता है और इसके अंडाकार डिजाइन के कारण इस स्पीकर को 360 डिग्री एंगल पर सुना जा सकता है. इसकी क़ीमत 3,849 रुपए है. ■

4 क्रिएटिव डी100

क्रिएटिव डी100 पर आप वायरलेस से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. यह स्पीकर किसी भी ब्लूटुथ डिवाइस के साथ आसानी से पेयर हो जाते हैं. इसके अलावा, आप 3.3 एमएम जैक के ज़रिए भी क्रेटिव डी100 पर म्यूजिक सुन सकते हैं. पोर्टेबल स्पीकर की साइज 5.1-15.6.5.3 है और कंपनी ने क्रेटिव डी100 में एएम बैटरी का इस्तेमाल किया है. स्पीकर के फ्रंट पैनल पर ही ब्लूटुथ, वॉल्यूम कंट्रोल और पावर ऑन/ऑफ बटन दिए गए हैं. इसकी क़ीमत लगभग 4,400 रुपए है. ■

5 पोट्रॉनिक्स प्योर साउंड बीटी

कुछ समय पहले ही पोर्टेबल डिवाइस बनाने वाली कंपनी पोट्रॉनिक्स ने पोट्रॉनिक्स प्योर साउंड बीटी के नाम से अपना पोर्टेबल ब्लूटुथ स्पीकर बाज़ार में उतारा है. इस स्पीकर को आप किसी भी ब्लूटुथ सपोर्ट फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा, एयूएक्स, यूएसबी और माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए भी आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं. पोट्रॉनिक्स प्योर साउंड बीटी स्पीकर रिचार्जेबल बैटरी के साथ काम करता है. कंपनी के अनुसार इसे एक बार चार्ज करने पर आप 9-10 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं. ऑनलाइन स्टोर पर इसकी क़ीमत 1395 रुपए है. ■

टीडीसैट का ऐतिहासिक फैसला

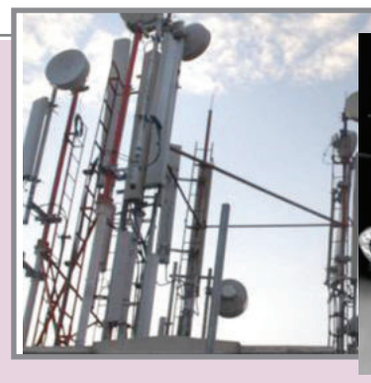

अब केबल ऑपरेटर्स के लिए डिजिटाइजेशन आसान होने जा रहा है. इससे सभी केबल ऑपरेटर्स को लाभ मिलेगा और भारत सरकार की नई डिजिटाइजेशन की नीति को बल मिलेगा.

टीडीसैट के ऐतिहासिक फैसले से देश में डिजिटाइजेशन की मुहिम को नई गति मिलेगी. इस फैसले से देश में लगभग साठ हजार केबल ऑपरेटर्स के लिए डिजिटाइजेशन आसान हो जाएगा. दो सदस्यों वाली टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में जी ग्रुप और स्टार ग्रुप की संयुक्त कंपनी मीडिया-प्रो को एनएसटीपीएल के हिट्स प्लेटफार्म जैन हिट्स पर पे चैनल्स के सिग्नल राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. फैसले का स्वागत करते हुए जैन टीवी ग्रुप के चेयरमैन और एनएसटीपीएल के संस्थापक जेके जैन ने कहा कि यह फैसला बडे कंटेंट एग्रीगेटर्स का एकाधिकार समाप्त करेगा तथा उनके द्वारा की जा जाने वाली दबंगई का भी अंत करेगा. क्योंकि हिट्स के जरिये वह सभी पे-चैनल, जिनकी मांग है, जिसे चाहिए, सभी के लिए उपलब्ध होंगे. उल्लेखनीय है कि जैन हिट्स के लॉन्च के बाद एनएसटीपीएल ने जी और स्टार के कई चैनल के कंटेंट का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मीडिया-प्रो से संपर्क कर लगभग 75 टीवी चैनल्स के सिग्नल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. लेकिन अलग-अलग आधारों का हवाला देकर मीडिया-प्रो ने प्रक्रिया को साल भर से ज्यादा लटकाए रखा. हाल ही में उन्होंने एनएसटीपीएल को अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर उन तकनीकी जरूरतों को थोपने की कोशिश की जो टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी द्वारा तय किए गए रेग्यूलेटरी और कानूनी संरचना से बाहर थे. ट्रिब्यूनल ने मीडिया-प्रो की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने जैन हिट्स प्लेटफार्म से पाइरेसी की संभावना जताई थी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

जेनसेटमार्ट.कॉम

बिजली की किल्लत का स्मार्ट सॉल्यूशन

दुनिया जितनी विकसित होती जा रही है, हम उसी रफ्तार से आधुनिक जीवन-शैली के आदी होते जा रहे हैं. आजकल हर काम बिजली से हो रहा है. हमारी निर्भरता बिजली पर बढ़ती ही जा रही है. ख़ास तौर पर कृषि और उद्योग धंधों की इकाइयां, लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि हमारे देश में बिजली की खपत जितनी ज़्यादा है, उत्पादन उस मात्रा में नहीं हो पा रहा है. लिहाज़ा क्या शहर और क्या गांव, हर जगह बिजली की कमी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहद प्रभावित होती है. ऐसे में जेनरेटर सेट्स या सोलर एनर्जी प्लांट ही बिजली उत्पादन का ज़रिया बन कर, बिजली की कमी को पूरा कर रहे हैं. बाज़ार में कई बड़ी कंपनियां हैं, जो जेनरेटर बनाती हैं. पर आम लोगों की परेशानी यह है कि उन्हें विभिन्न कंपनियों के जेनरेटर सेट्स की तकनीकि ख़ूबियों की जानकारी नहीं होती. जेनरेटर ख़रीद लेने के बाद उसकी सर्विसिंग कैसे कराएं, कोई तकनीकी परेशानी हो तो उसके जानकार से कैसे संपर्क करें, नया जेनरेटर कैसे और कहां से खरीदें या फिर पुराना जेनरेटर सही क़ीमत पर कैसे बेचें, सोलर एनर्जी प्लांट कैसे इंस्टॉल कराएं इत्यादि. आपकी इन्ही सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मार्केट में पहली बार इस किस्म का एक वेब पोर्टल जेनसेटमार्ट.कॉम के नाम से लांच किया गया है. इस वेब पोर्टल के ऑपरेशन हेड अभिषेक तिवारी का कहना है कि यह वेब पोर्टल लोगों को टेक्निकल सपोर्ट, रेटिंग कार्ड, सेलिंग-बाईंग, मेकेनिक्स, सर्विस और ऑपरेशन संबंधित सारी परेशानियों का हल चुटिकयों में उपलब्ध कराएगा. इस वेब पोर्टल के माध्यम से आप भारत में सोलर और जेनरेटर उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही 56 कंपनियों के तकनीकि विशेषज्ञों से सीधे चैट कर किसी भी परेशानी का हल पा सकते हैं. ■

सिनर्जी
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
विश्वस्तरीय स्वास्थ सेवायें
सर्वे सन्तु निरामया:

रोगियों की सेवाओं एवं सुविधाओं पर केन्द्रित
सम्पूर्ण चिकित्सा सेवायें एक जगह पर
विश्वस्तरीय स्वास्थ गुणवत्ता मानकों के अनुरूप
उच्च प्रशिक्षित एवं अनुभवी पूर्णकालिक चिकित्सा टीम
समाज के हर वर्ग की पहुँच में

विश्वस्तरीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

ARTIS ZEE SIEMENS FLAT PANEL CATH LAB

24 HRS. EMERGENCY & TRAUMA

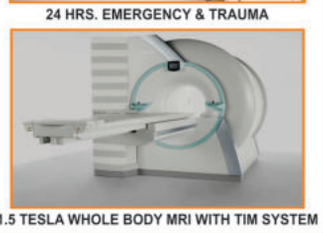
1.5 TESLA WHOLE BODY MRI WITH TIM SYSTEM

सिनर्जी अस्पताल - मुख्य विशेषताएं
- 140 बैड पूर्णतयः वातानुकूलित मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
- अर्न्तराष्ट्रीय गुणवत्ता मानको के अनुरूप चिकित्सा सेवायें
- शहर के बीचो बीच स्थित, घंटाघर से मात्र 3 किमी की दूरी पर
- 28 पूर्णकालिक सीनियर कन्सलटैन्ट और 36 विजिटिंग कन्सलटैन्ट
- 18 पूर्णकालिक ओ.पी.डी. 400 व्यक्तियों की बैठने की सुविधा
- 6 मोडयूलर लेमिनार एयर फ्लो आपरेशन थियेटर हीपा फिल्टर युक्त
- 55 आई.सी.यू. बैड, वेन्टीलेटर व अन्य जीवन रक्षक प्रणाली युक्त
- एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त पैथोलोजी एवं माइक्रोबायोलॉजी लैब
- 1.5 टेस्ला टिम युक्त सम्पूर्ण शरीर की एम.आर.आई.
- 4डी अल्ट्रासाउण्ड, डेक्सा स्कैन, मैमोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे
- विश्व की सर्वोत्तम 3डी इको और कलर डॉपलर, डी.एम.टी., हॉल्टर
- फुल फ्लैट पैनल कैथ लेब, एंजीयोग्राफी एवं एंजीयोप्लास्टी
- कार्डियक बाईपास सर्जरी, हार्ट वाल्व सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी
- उच्चस्तरीय एन्डोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी
- स्ट्रोक यूनिट, हैड इंजरी यूनिट, न्यूरो लैब ई.ई.जी., ई.एम.जी., ई.पी.
- डायलिसिस, लिथोट्रिप्सी, टी.यू.आर., यूरोफ्लोमैट्री, एण्डोयूरोलॉजी
- अत्याधुनिक गैस्ट्रो सर्जरी, लेपरोस्कोपिक सर्जरी एवं कैन्सर सर्जरी
- अपर जी.आई. एण्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एवं ई.आर.सी.पी.
- आर्थोप्लास्टी, आर्थोस्कोपी एवं सभी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी
- सबसे व्यापक उच्चस्तरीय ट्रॉमा टीम, लेवल 3 ट्रॉमा सर्विसेज
- उच्चस्तरीय प्रसुति सेवायें, स्त्री रोग एवं इनफर्टिलिटी सेवायें
- पिडियाट्रिक्स एवं नीयोनेटोलॉजी, एन.आई.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू.
- ब्रोंकोस्कोपी, स्लीप लैब, पल्मोनरी लैब और थोरोकोस्कोपी
- मधुमेह के सम्पूर्ण उपचार के लिए डायबिटिक क्लीनिक
- त्वचा रोग, कॉस्मैटोलॉजी और रिकन्सट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी
- माइक्रो इ.एन.टी. सर्जरी, सभी प्रकार की नेत्र रोग सेवायें
- फिजीयोथैरेपी, साइकोथैरेपी एवं विभिन्न काउन्सिलिंग सेवायें
- 24 घण्टे फार्मेसी, रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी सेवायें
- 24 घण्टे आई.सी.यू. एम्बूलैंस एवं इमरजेंसी सेवायें
- 24 घण्टे कैफेटिरिया, ई.एम.आर. एवं टेलीमेडिसिन नेटवर्क

HEMO DIALYSIS UNIT

STATE OF THE ART ICU

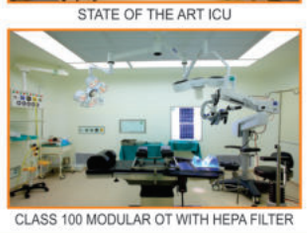
CLASS 100 MODULAR OT WITH HEPA FILTER

DEPARTMENTS
न्यूरोलॉजी | न्यूरो सर्जरी | कार्डियोलॉजी | कार्डियक सर्जरी | थौरेसिक सर्जरी | नेफ्रोलॉजी | एन्डो-यूरोसर्जरी | गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी | गेस्ट्रो सर्जरी | आर्थोपेडिक्स | ज्वाइंट सर्जरी | ऐनेस्थिसिया | क्रिटिकल केयर | पेन मैनेजमेंट | पेथोलॉजी | माइक्रबॉयोलॉजी
रेडियोलॉजी | पल्मोनरी मेडिसन | ओब्स एवं गायनी | पिडियाट्रिक्स | पिडियाट्रिक्स सर्जरी | ई.एन.टी. सर्जरी | आफ्थेल्मिक्स | डरमटोलोजी | प्लास्टिक सर्जरी | एन्डोक्राईनोलाजी | वैस्कूलर सर्जरी | साइकेट्री | फिजीयोथेरेपी | डायटेटिक्स

बल्लूपुर कैनाल रोड, देहरादून हेल्प लाईन नं. 0135 - 222 6000 - 249 (लाईन) | Email us: info@synergyhealthcare.in | Visit us at: www.synergyhealthcare.in

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

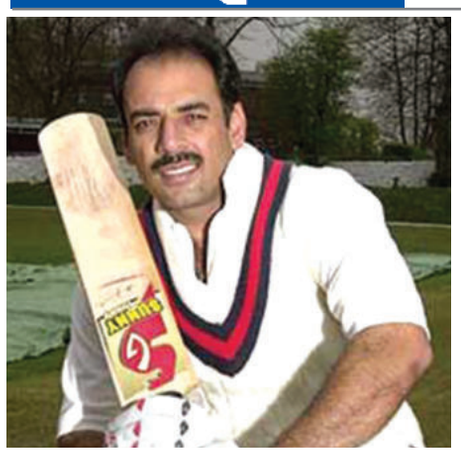

जो भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी क्षमता पर किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता. उस स्तर तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों के खेल का स्तर और क्षमता लगभग एक जैसी होती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी बहुत कम ही खिलाड़ियों को सचिन और धोनी जैसी लोकप्रियता हासिल हो पाती है या पैसा मिल पाता है. कई खिलाड़ियों को पूरे करियर में एक भी व्यक्तिगत विज्ञापन नहीं मिल पाता है.

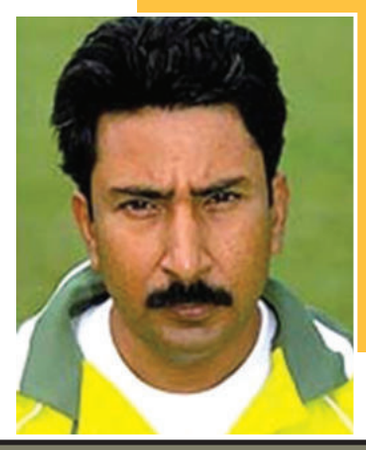

फिक्सिंग रोकने की मांग डिलीट हो सकते हैं खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स

विश्व क्रिकेट में फिक्सिंग के लगातार हो रहे खुलासों के बावजूद आईसीसी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है और न ही इस पर रोक लगाने के लिए कोई स्थाई हल ढूंढ पा रही है. नतीजतन बुकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों पर भी डोरे डालने लगे हैं. अब ज़रूरत है कि फिक्सिंग में लिप्त पाए गए खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाए और क्रिकेट को फिक्सिंग के चंगुल से मुक्त कराया जाए.

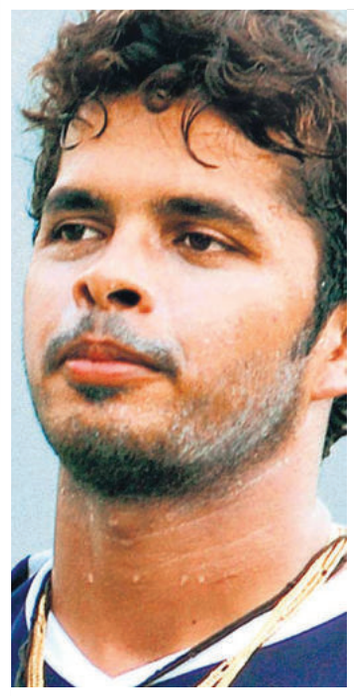

नवीन चौहान

हाल ही में बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने तेज गेंदबाज सांताकुमारन श्रीसंत और अंकित चव्हाण के क्रिकेट खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है. दोनों खिलाड़ियों पर आईपीएल–6 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग करने के आरोप लगे थे. इसके बाद बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने आरोपों की जांच की और अपनी छानबीन में आरोपों को सही पाया. समिति ने आरोप सिद्ध होने पर श्रीसंत और अंकित चव्हाण पर आजीवन प्रतिबंध, अमित सिंह पर पांच साल का और सिद्धार्थ त्रिवेदी पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है. हरमीत सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है. अजीत चंदीला के खिलाफ समिति बाद में फैसला सुनाएगी. फिक्सिंग में लिप्त पाए गए खिलाड़ियों को भारत सरकार सलाखों के पीछे पहुंचाने में इस बार भी कामयाब हो या न हो, लेकिन बीसीसीआई ने उनका करियर खत्म कर दिया है. अब आरोपी खिलाड़ी किसी भी तरह के क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे.

एक बार फिर फिक्सिंग के आरोपी खिलाड़ियों में से कुछ पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिए गए तो कुछ पर एक से पांच साल तक क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुछ को सबूतों के अभाव में आरोप से बरी कर दिया गया. हर बार फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद बीसीसीआई की जांच समिति ऐसे ही कुछ प्रतिबंधों के साथ सामने आती है. यहां सवाल यह उठता है कि क्या बीसीसीआई द्वारा उठाया गया यह कदम भविष्य में फिक्सिंग पर पूरी तरह रोक लगा पाने में कारगर होगा. मेरी समझ में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, जिससे फिक्सिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके. विश्व क्रिकेट में लगातार फिक्सिंग के खुलासे होने के बाद भी आईसीसी इस पर रोक लगाने के लिए कोई स्थाई समाधान अब तक नहीं ढूंढ पाई है. हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी घटना के घटित होने के बाद हम उस विषय पर समीक्षा करने बैठ जाते हैं और यह नहीं सोचते कि ये घटना आखिर घटी क्यों?

क्रिकेट जैसे–जैसे फिक्सिंग के जाल फंसता जा रहा है, उससे इस खेल की लोकप्रियता और विश्वसनीयता दोनों को गहरी चोट पहुंच रही है. भले ही बीसीसीआई और आईसीसी अपनी–अपनी तिजोरियां भरती दिखाई पड़ रही हों, लेकिन हकीकत में क्रिकेट की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है. क्रिकेट के प्रति लोगों में अब वो पैशन नहीं दिखाई देता है, जो 90 के दशक में दिखाई देता था. मैच के दौरान रास्ते सूने हो जाते थे, लेकिन अब क्रिकेट केवल मनोरंजन का साधन रह गया है. जब से टी–20 क्रिकेट की शुरुआत हुई है, तब से सट्टेबाजी से जुड़े लोगों की क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी हो गई है. उनके लिए यह कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का साधन बन गया है. जब से आईपीएल की तर्ज पर हर देश में टी–20 लीग्स की शुरुआत हुई है, तब से फिक्सिंग ज्यादा होने लगी है. अब पहले की तरह मैच के परिणाम फिक्स नहीं होते हैं, अब मैच के कुछ स्पॉट फिक्स होते हैं. मसलन किस ओवर की कौन सी गेंद नो बॉल अथवा वाइड बॉल होगी या किस गेंद पर चौका या छक्का लगेगा. इस तरह की फिक्सिंग से खिलाड़ियों के पकड़े जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है. मैच के कई स्पॉट पहले ही फिक्स कर लिए जाते हैं और बुकी उन्हीं स्पॉट्स पर सट्टा खेलकर मोटी कमाई करना चाहते हैं.

पिछले एक दशक में देश–विदेश के कई क्रिकेट खिलाड़ियों को फिक्सिंग के आरोपों के कारण प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनये, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक और सलमान बट्ट, भारतीय क्रिकेटर अजय शर्मा, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अताउर रहमान आदि के नाम प्रमुख हैं. हालांकि अजहरुद्दीन को 2012 में उच्चतम न्यायालय ने फिक्सिंग के आरोपों से बरी कर उन पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि खिलाड़ियों पर इन प्रतिबंधों के बावजूद फिक्सिंग में लिप्त पाए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इज़ाफा क्यों हो रहा है?

जो भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी क्षमता पर किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता. उस स्तर तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों के खेल का स्तर और क्षमता लगभग एक जैसी होती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी बहुत कम ही खिलाड़ियों को सचिन और धोनी जैसी लोकप्रियता हासिल हो पाती है या पैसा मिल पाता है. कई खिलाड़ियों को पूरे करियर में एक भी व्यक्तिगत विज्ञापन नहीं मिल पाता है. उनकी आय का स्रोत केवल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस होती है. कुछ खिलाड़ियों को यह बात कचोटती है कि उनको कम पैसे क्यों मिलते हैं और यहीं से वे फिक्सिंग के मायाजाल में फसने लगते हैं. वे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना चाहते हैं. इसके लिए वे कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं.

बहुत से पूर्व खिलाड़ियों ने फिक्सिंग पर पूरी लगाम लगाने के लिए रिकॉर्ड बुक्स से खिलाड़ियों के रिकॉर्ड हटा देने की पैरवी की है. इनमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अनिल कुंबले भी शामिल हैं, जिन्होंने सपॉट फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की अपातकालीन बैठक में स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाए गए खिलाड़ियों का रिकॉर्ड हटा देने का सुझाव रखा था. कुंबले के अनुसार, फिक्सिंग के मामले में बीसीसीआई की जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए. बैठक के दौरान कुंबले ने अंतरराष्ट्रीय सायकिल संघ द्वारा लांस आर्मस्ट्रांग के खिलाफ की गई कार्रवाई का उदाहरण दिया

फिक्सिंग की फांस से पहले ही क्रिकेट बहुत बदनाम हो चुका है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, कीनिया आदि देशों के खिलाड़ी फिक्सिंग के जाल में फंस चुके हैं. कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसके खिलाड़ियों से कभी बुकीज ने फिक्सिंग के लिए संपर्क न किया हो. कभी-कभी नजदीकी रिश्तेदार और मित्र भी फिक्सरों के संपर्क में आ जाते हैं और खिलाड़ियों से संबंधित सूचनाएं बुकी को उपलब्ध करा देते हैं, जिससे खिलाड़ी अप्रत्यक्ष रूप से फिक्सिंग के फेर में आ जाते हैं, जैसा कि आईपीएल-6 में हुआ.

था. अंतरराष्ट्रीय सायकिल संघ ने आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रदर्शन को बेहतर कर देने वाली दवाओं के सेवन की बात स्वीकार करने के बाद उनके नाम दर्ज सारे रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड बुक्स से हटा दिया था. कुंबले ने बीसीसीआई के उच्चाधिकारियों से कहा कि यदि दूसरे खेल संघ खेल के सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके रिकॉर्ड्स हटाने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे हैं तो बीसीसीआई इस मामले में पीछे क्यों है? आखिर बीसीसीआई इन खिलाड़ियों के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखाता है? हो सकता है कि तकनीकी तौर पर खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स हटा पाना संभव न हो, लेकिन इसके लिए आईसीसी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. क्रिकेट एक टीम गेम है, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन भी कहीं न कहीं दूसरे खिलाड़ियों के साथ जुड़ा होता है. किसी खिलाड़ी की गेंद पर कोई कैच लेता है तो कोई खिलाड़ी रन आउट करता है. यहां एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने से दूसरे खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी प्रभावित होता है. सामान्य तौर पर यदि किसी खिलाड़ी के नाम कोई रिकॉर्ड दर्ज है और वह फिक्सिंग में लिप्त पाया जाता है तो रिकॉर्ड बुक्स में उसके नाम की जगह अननोन या अन्य कुछ लिख देना चाहिए, जिससे कि विश्व में अब तक के सभी फिक्सिंग में लिप्त खिलाड़ियों का डेटा एक जगह एकत्रित हो जाएगा. उनके द्वारा जीते गए मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज और प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता टीम के सदस्य के रूप में मिलने वाले पुरस्कार सहित सभी पुरस्कार उनसे वापस ले लिए जाने चाहिए. किसी भी रिकॉर्ड में उनका नाम, यहां तक कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची में भी उनका नाम नहीं होना चाहिए. यहां तक कि सम्मान समझी जाने वाली पहली टेस्ट अथवा एकदिवसीय कैप भी उनसे वापस ले ली जानी चाहिए. हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सभी कदम क्रूर लगें, लेकिन जो लोग करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, उनके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए. कोई भी खिलाड़ी खेल से ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए आने वाली पीढ़ी उन खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करने वाले खिलाड़ी के रूप में जाने और ऐसा कुछ करने से पहले हजार बार सोचे, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं.

फिक्सिंग की फांस से पहले ही क्रिकेट बहुत हद तक बदनाम हो चुका है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, कीनिया आदि देशों के खिलाड़ी पहले ही फिक्सिंग के जाल में फंस चुके हैं. कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसके खिलाड़ियों से कभी बुकीज ने फिक्सिंग के लिए संपर्क न किया हो. कभी–कभी नजदीकी रिश्तेदार और मित्र भी फिक्सरों के संपर्क में आ जाते हैं और खिलाड़ियों से संबंधित सूचनाएं बुकी को उपलब्ध करा देते हैं, जिससे खिलाड़ी अप्रत्यक्ष रूप से फिक्सिंग के फेर में आ जाते हैं, जैसा कि आईपीएल–6 में हुआ. इसलिए खिलाड़ियों के लिए अपने नजदीकियों से भी सावधान रहने की भी जरूरत है. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जिंदगी भर की मेहनत खराब हो जाती है. ऐसे में खिलाड़ी खुद चौकस रहकर अपने को और खेल को बचा सकते हैं.आईसीसी को सभी देशों के साथ मिलकर फिक्सिंग के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा. इसके साथ ही उभरते युवा खिलाड़ियों को फिक्सिंग के खतरों के बारे में आगाह करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना होगा. बीसीसीआई ने इसके लिए पहल शुरू भी कर दी है. अतंरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के अलावा अब घरेलू खिलाड़ियों की तरफ भी बुकी नजर डालने लगे हैं. घरेलू खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत से पहले ही उन पर बुकी डोरे डालना शुरू कर देते हैं. उन्हें इससे बचाने के लिए भी बीसीसीआई को और सघन प्रयास करने होंगे, जिससे क्रिकेट पर लगे इस बदनुमा दाग को मिटाया जा सके और क्रिकेट की लोकप्रियता को फिर से स्थापित किया जा सके. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

फिल्म बेशर्म में रणबीर कपूर एक ऐसे मैकेनिक के किरदार में नज़र आएंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर कार भी चुरा लेता है. इस फिल्म के एक गाने में वह उसी कास्ट्यूम में नज़र आएंगे, जो कि फिल्म क़र्ज़ के हिट सॉन्ग ओम शांति ओम में उनके पापा ऋषि कपूर ने पहना था. वह पूरी फिल्म में रेट्रो लुक में नज़र आएंगे.

...अब अक्षय भी फिल्म बनाएंगे

खिलाड़ी अक्षय कुमार अब ऐक्टिंग के साथ फिल्म मेकिंग में भी उतर आए हैं. शाहरुख खान, अजय देवगन और जॉन अब्राहम के बाद अब अक्षय कुमार भी फिल्म बनाएंगे. वे करण जौहर के साथ गुटका नाम से एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ अर्जुन कपूर और करीना कपूर भी हैं. हालांकि जल्द ही अक्षय की फिल्म द बॉस भी रिलीज होने वाली है. साउथ की रीमेक सुपरहिट फिल्म राउडी राठौर के बाद अक्षय एक और रीमेक फिल्म में नज़र आ रहे हैं. अक्षय इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि वह इसे साउथ का टोटल रीमेक नहीं मानते. वे कहते हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट में पूरा-पूरा बदलाव किया गया है. उनका कहना है कि अगर आप साउथ की कोई सुपरहिट फिल्म ही क्यों न ले रहे हों, लेकिन जब तक आप बनाते समय नॉर्थ के बिकाऊ मसाले फिट नहीं करेंगे, तो वह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी. भारत में 16 सौ से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और अब उन्हें बड़े पर्दे पर पहचान मिलने लगी हैं. अब फिल्मकार उन जगहों का कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, जो अब तक सिनेमा जगत में नहीं उठाया गया था. फिल्म ओ माई गॉड गुजराती कल्चर को लेकर बनी थी. हर साल तमिल, तेलुगू, मलयालम सहित दूसरी भाषाओं की सात-आठ सुपरहिट फिल्मों को हिंदी में बनाया जाता है. अक्षय कहते हैं कि हालांकि बॉलीवुड में भी अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी और मनीष शर्मा जैसे क्रिएटिव फिल्म मेकर्स हैं. वे ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनाते हैं, जो दूसरी भाषाओं में अभी भी नहीं बनतीं, लेकिन फिर भी इन दिनों बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का चलन ज़ोरों पर है. ■

साउथ के सुपरस्टार

बॉलीवुड में कितने कामयाब !

कभी इन्होंने भी साउथ में काम किया था...

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में साउथ की फिल्में की थीं, लेकिन आज वे बॉलीवुड की पहचान बन गए हैं.

अमोल पालेकर : अपने शुरुआती दिनों में अमोल पालेकर ने कुछ मलयाली फिल्मों में काम किया था. उनमें से एक ओलंगल है.

अनिल कपूर : अनिल कपूर ने टॉलीवुड में भी काम करने की कोशिश की. उन्होंने तेलुगू फिल्म वस्मावक्षं में काम किया था.

सोनू सूद : सोनू सूद ने कई बॉलीवुड फिल्में की हैं, लेकिन इससे पहले वह साउथ की फिल्मों में काम कर चुके हैं. वह वहां के जाने-माने विलेन हैं.

अक्षय कुमार: करियर की शुरुआत में अक्षय कुमार ने भी एक कन्नड़ फिल्म में काम किया था. इस फिल्म का नाम था विष्णु विजय. इसमें उनके साथ थे कन्नड़ सुपरस्टार विष्णुवर्धन.

प्रियंका तिवारी

इन दिनों बॉलीवुड में साउथ की मसाला फिल्मों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, वहां की सुपरहिट फिल्मों की एक के बाद एक रीमेक बन रही हैं. साथ ही वहां के अभिनेताओं को भी अब बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया जाने लगा है. साउथ स्टार धनुष और रामचरण तेजा के बाद अब बॉलीवुड में साउथ के अभिनेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब बॉलीवुड में साउथ के अभिनेताओं के अभिनय की तारीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन उन्हें मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में काम करने का मौक़ा कम ही मिल पाता था. अगर एकाध फिल्में मिल भी जाती थीं तो वह भी साइड अभिनेता के रूप में. रजनीकांत, कमल हसन, नाना पाटेकर, चिरंजीवी, नार्गाजुन और वेंगटेस जैसे साउथ के कई कलाकारों ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई. उनके अभिनय को काफ़ी पसंद भी किया गया, लेकिन फिल्मकारों ने उन्हें मेनस्ट्रीम हीरो के तौर पर किसी फिल्म में लेने की जोखिम नहीं उठाया. पर साउथ के सुपरस्टार राम चरण तेजा और धनुष के बाद साउथ के अभिनेताओं की पूछ बॉलीवुड में बढ़ गई है. इन्होंने न सिर्फ़ लीड हीरो का किरदार निभाया, बल्कि रामचरण तेजा को तो सलमान ने अपनी अगली फिल्म का ऑफर भी दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है.

पिछले कुछ सालों में साउथ का प्रभाव बॉलीवुड में इस तरह बढ़ा है कि अब साउथ के अभिनेताओं को मेनस्ट्रीम फिल्मों में भी लिया जाने लगा है. हालांकि साउथ की एक्ट्रेसज को शुरू से ही बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया जाता रहा है. वैजयंती माला, रेखा, हेमा मालिनी, जया प्रदा और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों ने अपने समय में बॉलीवुड पर राज किया, उसी दौरान साउथ के टॉप मेल ऐक्टर्स ने भी बॉलीवुड में किस्मत आजमाई. 1980 में कमल हसन ने एक-दूजे के लिए, रजनीकांत ने 1983 में अंधा क़ानून में, चिरंजीवी ने 1992 में आज का गुंडा राज में अभिनय किया. ये फिल्में सफ़ल रहीं, लेकिन इन फिल्मों के ज़रिये ये बॉलीवुड में ख़ुद को स्थापित नहीं कर पाए. तेलुगू स्टार नागार्जुन को 1962 में बनी फिल्म क्रिमिनल से थोड़ी बहुत सफ़लता तो ज़रूर मिली, लेकिन वह भी असफ़ल ही रहें. बाद में तमिल सुपरस्टार सूर्या ने रक्त चरित्र(2010), सिद्धार्थ ने रंग दे बसंती और सुदीप ने मक्खी जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया. मलयालम एक्टर पृथ्वीराज ने भी हाल ही में रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अइय्या में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. मात्र माधवन ही एक ऐसे तमिल स्टार हैं, जिनके नाम कई हिट फिल्में दर्ज हैं. माधवन जितने लोकप्रिय साउथ में हैं, उतने ही बॉलीवुड में भी. सवाल यह है कि आख़िर क्यों बॉलीवुड में साउथ एक्टर्स को मान्यता नहीं मिलती. इसके जवाब में डांसर और निर्देशक प्रभुदेवा कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह भाषा है. हिंदी फिल्मों में काम कर रहे ऐक्टर्स दर्शकों के दिल के ज़्यादा क़रीब होते हैं. उनके साथ भाषा की कोई समस्या नहीं होती. वे दिल से हिंदी बोलते हैं. दूसरी वजह वहां के कलाकारों की त्वचा की रंगत भी है, जबकि अभिनेत्रियों के साथ ऐसा नहीं है. साउथ की अभिनेत्रियों की ब्यूटी को बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया जाता रहा है. इसलिए अभिनेत्रियों को ख़ुद को स्थापित करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती. साउथ के अभिनेता बॉलीवुड में काम करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं. इसकी वजह यह है कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करके वे एक बड़े कैनवॉस पर अपनी अभिनय का लोहा मनवाना चाहते हैं, नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं, उन्हें एकाध फिल्में मिल तो जाती हैं, पर वह कुछ ख़ास नहीं कर पाते. हालांकि आज के समय में साउथ और बॉलीवुड का कनेक्शन ख़ूब देखने को मिल रहा है. सच तो यह है कि अब साउथ, बॉलीवुड की एक तरह से ज़रूरत बनता जा रहा है. साउथ की फिल्मों की रीमेक से लेकर अब वहां के ख़ूबसूरत लोकेशंस में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होने लगी है. ऐसे में वहां के कलाकारों को भी हिंदी फिल्मों से जोड़ना एक तरह से अनिवार्य हो गया है. दूसरी वज़ह यह है कि बदलते वक़्त के साथ अब दर्शकों की पसंद भी बदल रही है. साउथ का रहन-सहन वहां की भाषा दर्शकों को काफ़ी भाने लगा है. अब बॉलीवुड को उनकी रंगत और भाषा से कोई ऐतराज नहीं, बल्कि वे इसे काफ़ी एंज्वॉय कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

बेशर्म

डायरेक्टर	:	अभिनव कश्यप
प्रोड्यूसर	:	हिमांशु मेहरा संजीव गुप्ता
बैनर	:	रिलायंस इंटरटेनमेंट
पटकथा	:	अभिनव कश्यप
लेखक		राजीव बरनवाल
स्टार्टिंग	:	रनवीर कपूर पल्लवी शारदा ऋषि कपूर नीतू सिंह
म्यूजिक	:	ललित पंडित
रिलीज डेट	:	2 अक्टूबर, 2013
लागत	:	50 करोड़

अभिनव कश्यप निर्देशित इस फिल्म में पहली बार रणवीर कपूर भांगड़ा करते दिखेंगे. इस फिल्म के एक गाने में रणबीर 70 स्टाइल में नज़र आएंगे. रणवीर कपूर पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी एक भी फिल्म में देसी भांगड़ा नहीं किया है, पर इस फिल्म में वह देसी भांगड़ा करते नज़र आएंगे. यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसकी ख़ास बात यह है कि फिल्म में रणवीर कपूर अपने मम्मी-डैडी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह के साथ नज़र आएंगे. इसमें ऋषि कपूर एक पुलिस की भूमिका में दिखेंगे, यह रोल कुछ ऐसा ही है जैसा फिल्म दबंग में चुलबुल पांडेय बने सलमान ख़ान का था. वहीं नीतू सिंह भी महिला कॉन्स्टेबल के रूप में पर्दे पर नज़र आएंगी. रणबीर कपूर एक मैकेनिक के किरदार में नज़र आएंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर कार भी चुरा लेता है.

इस फिल्म में एक और ख़ास बात देखने को मिलेगी और वह यह है कि इस फिल्म के एक गाने में वह उसी कास्ट्यूम में नज़र आएंगे, जो कि फिल्म क़र्ज़ के हिट सॉन्ग ओम शांति ओम में उनके पापा ऋषि कपूर ने पहना था. वह इसमें रेट्रो लुक में नज़र आएंगे. रणवीर इस फिल्म में (बबली जान), पल्लवी शारदा (तारा जान), ऋृषि कपूर (हेड कॉन्स्टेबल चुलबुल चौटाला), कमल किरी (ड्रग सप्लायर) की मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. कॉकटेल और रेस 2 के बाद गायक हनी सिंह का गाना इस फिल्म में भी सुनने को मिलेगा. अभिनव कहते हैं कि इस फिल्म की कहानी लिखने में जितना समय उन्हें लगा, उससे भी कम समय में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई. फिल्म की कहानी लिखने में उन्हें 180 दिन का समय लगा, जबकि शूटिंग मात्र 100 दिन में ही पूरी हो गई. ■

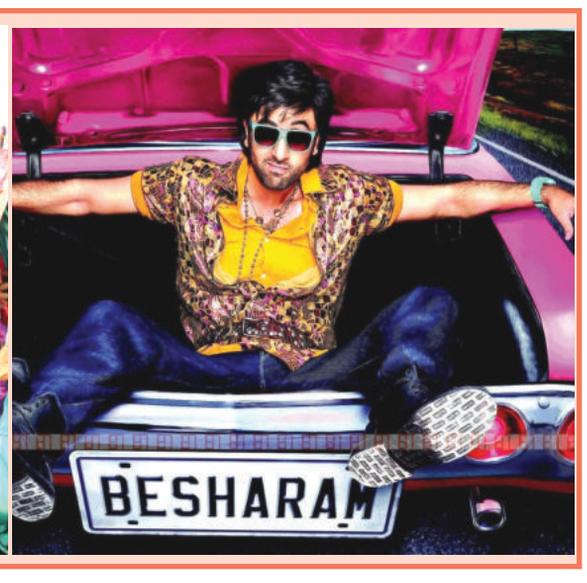

चौथी दुनिया

30 सितंबर-06 अक्टूबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार – झारखंड

विधायक फिर ठगे गए

विधायक निधि के दो करोड़ के फंड को नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था. इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा था कि यह फंड भ्रष्टाचार का स्त्रोत बन गया है. अब एक बार फिर से विधायक फंड को बहाल कर दिया गया है. विधायकों को साढ़े सात लाख तक का काम करवाने की इजाज़त सरकार ने दे तो दी है, लेकिन इसमें विधायकों की मनमानी को लगाम लगाने के लिए बाक़ायदा टेबल टेंडर होगा. इस बात को लेकर लेकर विधायकों में काफ़ी असंतोष है.

सरोज सिंह

विधायक फंड को लेकर विधायक एक बार फिर ठगे जा रहे हैं. पहली बार दो करोड़ के फंड को नीतीश कुमार ने बंद कर दिया था, तब इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इस फंड के बंटवारे में विधायकों को काफ़ी परेशानी हो रही है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है. तब सरकार के इस फ़ैसले पर विधायकों में जबरदस्त नाराज़गी थी. जदयू व भाजपा के विधायक तो सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर इस मामले को लेकर वे गुस्से में थे. विपक्षी विधायकों ने तो सरकार के इस फ़ैसले का पूरज़ोर विरोध भी किया. कई दफ़ा विधानसभा में भी इसे लेकर ग़रमाग़रम बहस हुई. विरोधियों ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने सभी विधायकों को ही चोर बना दिया. अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो इसे ख़त्म करना ज़रूरी है न कि फंड को ही ख़त्म कर दिया जाए. गौरतलब है कि विधायक फंड से विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में अपनी इच्छा से छोटी मोटी योजनाओं को पूरा कराते थे. इन कामों में उनके कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता दी जाती थी. स्वाभाविक है कि जो कार्यकर्ता चुनाव में नेताजी के साथ लगा रहता है, उसकी इच्छा ज़रूर होती है कि चुनाव बाद विधायक जी के आशीर्वाद से कुछ कमा लिया जाए. विधायक फंड ही एक ऐसा ज़रिया था, जिसके माध्यम से विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रख पा रहे थे, लेकिन इस फंड के बंद हो जाने के बाद तो लगा कि विधायक अपने ही क्षेत्र में अकेले पड़ गए हैं. इलाक़े में कोई जिंदाबाद का नारा लगाने वाला भी नहीं बचा. विधायक महोदय की यह पीड़ा कई दफ़ा सदन में भी गूंजी, लेकिन नीतीश सरकार ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया. जब भाजपा से जदयू का रिश्ता टूटा तो विश्वास मत यानी 19 जून, 2013 के दिन नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री जी, याद करिये, मैं बोल रहा हूं यह बात, शायद कोई मंत्री बोलें या न बोले, लेकिन आपको मालूम हो कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बार-बार आपसे कहता था कि विधायक फंड ख़त्म कर जो योजना आप लागू करना चाहते हैं, वह ग़लत है. आपको पचास मिनट लगा था, मुझे समझाने में. आप ही बताइये क्या हम चोर हैं? सदन में यह मामला उठने के बाद सरकार की नींद टूटी और कुछ दिनों बाद सरकार ने यह फ़ैसला किया कि साढ़े सात लाख तक के काम विधायक जी अपने फंड से करवा सकते हैं. इस फ़ैसले से ऐसा लगा कि सरकार ने विधायकों की भावनाओं का ख्याल रख सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन विधायक फंड को एक बार फिर से बहाल कर दिया, लेकिन अब इस फंड को लेकर जो बात सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि विधायक एक बार फिर इस मामले में ठगे जा रहे हैं. साढ़े सात लाख तक का काम करवाने की इजाजत सरकार ने दे तो दी है, लेकिन पता चलता है कि यह काम विधायक जी अपनी मर्जी से अपने लोगों को नहीं दिला पाएंगे. इन कामों का बजाप्ता टेबल टेंडर होगा और सक्षम पाए जाने वाले ठीकेदार को ही कार्यपालक अभियंता काम आवंटित कर सकते हैं. मतलब विधायक जी की मनमर्जी नहीं चलेगी. राजद विधायक सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब टेंडर हो ही गया तो फिर विधायकों की मर्जी का क्या मतलब. अब तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी. पहले तो फंड नहीं था, तब हम कार्यकर्ताओं को समझा लेते थे, लेकिन अब किसे हां कहेंगे और किसे ना. चौधरी कहते हैं कि अब तो कार्यपालक अभियंता को तय करना है कि संबंधित काम किसे मिलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न केवल जनता, बल्कि विधायकों के आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रही है. राजद के ही तेजतर्रार विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार ने साढ़े सात लाख की योजना लागू कर कार्यकर्ताओं को विधायकों के ख़िलाफ़ उकसाने का काम किया है. केवल पेपर में टेंडर नहीं आएगा तो इससे क्या होगा. कार्यालय के सूचना पट्ट पर तो यह चस्पा होगा ही, हम किसे मना करेंगे टेंडर नहीं डालने के लिए. वीरेंद्र कहते हैं कि यह ठगने वाली सरकार है और विधायकों को भी नहीं छोड़ रही है. नीतीश कुमार तो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ते नहीं है, फिर उन्हें क्या पता कि जनता की भावना क्या होती है. हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमें चुनती है. चुनाव में कार्यकर्ता जी जान लगा देते हैं, इसलिए हमें उनके दर्द का अहसास है. कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद होना चाहिए. उजियारपुर के विधायक दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि विधायक फंड के साथ मनमानी किया जा रहा है. आज से दो साल पहले मैंने अपने कोटे से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 39 पंचायत और एक नगर पंचायत में पुस्तकालय निर्माण की अनुशंसा की थी, लेकिन आज की तारीख में इन अनुशंसाओं पर रोने का दिल करता है. कोई काम नहीं हो रहा है. केवल शिलापट्ट में नाम लिखवाने की राजनीति चल रही है. साढ़े सात लाख वाली स्कीम मात्र झूनझूना है. जब विधायकों के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर विशेषाधिकार कैसा और मर्जी कैसी. इन बातों से विधायकों की पीड़ा आसानी से समझी जा सकती है. अफसर उनकी बात सुनते नहीं और कार्यकर्ताओं के लिए वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ले देकर एक विधायक फंड था, इस पर भी अपनी मर्जी नहीं चल रही है. माननीय महोदय आख़िर करें तो क्या करें. चुनाव नजदीक आ रहा है, आख़िर क्या कहकर विधायक अपने कार्यकर्ताओं से जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे. डर सता रहा है कि कहीं जिंदबाद का नारा मुर्दाबाद में न बदल जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षक भीख मांगने को मजबूर हैं

समाज और राष्ट्र की दिशा व दशा बदलने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई सेवा हमेशा याद की जाती है. लेकिन जिस समाज में शिक्षक ही हाशिए पर हो और सरकार, शिक्षा विभाग व प्रबंधन समिति की दोहरी नीति का शिकार हो व फटेहाल ज़िंदगी गुजारने को मज़बूर हो तो फिर उस समाज का क्या होगा?

बिहार के विभिन्न ज़िलों में स्थित साढ़े सात सौ अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में दशकों से पदस्थापित हज़ारों शिक्षकों व कर्मचारियों का बिहार की सुशासन सरकार शिक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है. राज्य सरकार पंचायत स्तर तक उच्च विद्यालय खोलने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती रही है, लेकिन वर्षों से उम्मीद पर कायम इन शिक्षकों के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाती, जिस कारण इन विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं और हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन करने लगे हैं. बावजूद इसके, सरकार व विभाग की नज़र उन पर नहीं पड़ रही है, जिससे शिक्षकों की हालात बदतर होती जा रही है. जानकार बताते हैं कि इन विद्यालयों को अभी तक मात्र दो बार वर्ष 2008 व 2009 में ही अनुदान की राशि मिल पाई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2010-011, 2011-012 व 2012-013 का अनुदान की राशि अभी तक नही पहुंची है.

– शेष पृष्ठ संख्या 19 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

औचक निरीक्षण

चतरा अनुमंडलाधिकारी सतीश चंद्रा के औचक निरीक्षण से ज़िले के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के लापरवाही पर लगाम लगता नज़र आ रहा है. वहीं अचानक निरीक्षण में कई राज खुलकर सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला हंटरगंज प्रखंड गिद्धौर, सिमरिया टंडवा एवं प्रतापपुर में देखा गया. यहां के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति मुख्यालय से एमओ ग़ायब नहीं रहेंगे. वहीं कालाबाज़ारी की सूचना मिलने पर संबंधित पदाधिकारी एवं डीलर बच नहीं पाएंगे. डीलरों की शिकायत पर एसडीओ ने कम चावल मिलने की बात एमओ को बताया तथा चावल के बोरे की तौली गोदाम पर करवाया गया, जिसमें 51 किलो के जगह पर 48 किलो चावल पाया गया.

चतरा एएसपी को शौर्यचक्र मिला

चतरा ज़िले में कार्यरत अभियान के एएसपी आर मिश्रा को 15 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति ने साहस और वीरता के लिए शौर्यचक्र से सम्मानित किया. सम्मान मिलने से चतरा पुलिस अधिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा, वहीं पूरे झारखंड में उनके वीरता की चर्चा है. मिश्रा ने कहा कि मैंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है. मैंने जीवनभर शादी नहीं करने का निर्णय लिया है. इसके पूर्व भी उन्हें चार बार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. **– अमरेन्द्र सिंह**

ज्योति हुई पुरस्कृत

पिछले दिनों रांची में आयोजित राज्यस्तरीय नि:शक्तता चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया गया. प्रतियोगिता के उपरांत राज्यपाल डॉ. सैय्यद अहमद के हाथों जीवन संस्थान बास्ताकोला, धनबाद के मानसिक रूप से नि:शक्त बच्ची ज्योति कुमारी को प्रथम स्थान आने पर पुरस्कृत किया गया. संस्थान के अधिकारियों, कर्मियों व बच्चों ने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. **– हैदरअली**

प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ
डॉ. सुनील कुमार गुप्त
M.Sc. (Bot.), B.A.M.S. (आयुर्वेदाचार्य)
पता- थाना चौक, खगड़िया मो.:9430042547

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सत्याग्रह के जनक महात्मा गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं व अभिभावकों का ...
तारकेश्वर प्रसाद वर्मा महाविद्यालय
डॉ. रामप्रताप नीरज (प्राचार्य) टी.पी.वर्मा कॉलेज
नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण -845455

ठंडा पानी से दूर रहें
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo-XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo-XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

अख्तरुल इमान

बरून सिंह

दिलीप जायसवाल

गोपाल अग्रवाल

नीरज सिंह/ कुलभूषण

सीमांचल

रेल परियोजनाओं पर ग्रहण

सीमांचल की रेल परियोजना को लगता है किसी की नज़र ही लग गई. नेपाल-बांग्लादेश की सीमा के निकट स्थित लगभग 110 किमी लंबी गलगलिया-अररिया, 50 किमी लंबी जलालगढ़-कानकी (बंगाल), 60 किमी लंबी कुर्सेला-बिहारीगंज के बीच नई रेल लाइनों को बिछाने के अलावा धमहरा घाट-कत्यानी स्थान पर 800 मी. सड़क बनाने की परियोजनाओं कब पूरी होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

सीमांचल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी का विश्वास था कि सरकार में होने का लाभ उनके क्षेत्र को अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने ही सरकार में उनकी उपेक्षा हुई. गलगलिया-अररिया रेल लाइन निर्माण के लिए धन का आवंटन तो दूर उनके क्षेत्र में पड़ने वाले अलुआबाड़ी-ठाकुरगंज-गलगलिया रेलखंड के कई महत्वपूर्ण पुराने स्टेशनों पोठिया, तैय्यबपुर पिपरीथान आदि के दर्जे को घटाकर हाल्ट स्टेशन बना दिया गया, जिससे इस क्षेत्र की जनता आंदोलित है. इसके विरोध में ठाकुरगंज सर्वदलीय रेलवे संघर्ष समिति द्वारा 26 अगस्त, 2013 को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस रेलखंड से होकर एक भी लंबी दूरी के ट्रेनों का परिचालन नहीं होना, इस क्षेत्र के साथ सौतेलापन है. आर्थिक पिछड़ेपन के चलते प्रत्येक दिन इस क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में मजदूरों का पलायन, पंजाब, दिल्ली समेत देश के अन्य भागों में होता है. सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोजपा प्रदेश महासचिव किशन बाबू पासवान, लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंजर आलम, महेश पासवान, भाजपा के संजय पोद्दार पूर्व मुखिया गणेश राय, भाजपा युवा मोर्चा के अनिल महराज समेत सैकड़ों लोगों ने कटिहार डीआरएम से ग़रीब-नवाज़, कैपिटल एक्सप्रेस महानंदा, आनंद बिहार समेत नई ट्रेनों को इस रेलखंड से होकर चलाने की मांग की. भाजपा के विधान पार्षद सह कोषाध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि किशनगंज समेत सीमांचल से कांग्रेस के तीन विधायक और एक सांसद हैं, फिर भी यह इलाक़ा रेल परिवहन, राजीव गांधी विद्युतीकरण और प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के मामले में फिसड्डी है. किशनगंज को

भारत का चिकेन नेक कहा जाता है, पड़ोसी मुल्कों की गिद्ध दृष्टि इस पर लगी रहती है. सीमा पार चीन की सीमावर्ती क्षेत्र में नए रेल और सड़क मार्गों के निर्माण से हलचल है. वहीं गलगलिया-अररिया रेल परियोजनाओं का कार्य अधर में लटक गया है. [illegible]

कोचाधामन (किशनगंज) के राजद विधायक अख़्तरुल ईमान का कहना है कि [illegible]

[illegible] हुआ. अररिया-गलगलिया रेलवे परियोजना को लेकर बहादुरगंज के लोगों में कुछ आशा जगी, लेकिन [illegible] सिंह ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद इस रेल परियोजना को पूरा करवा जाएगा. पूर्णिया के भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने सीमांचल के साथ हमेशा भेदभाव पूर्ण रवैया किया है. [illegible] भाजपा के पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष ज्योति रानी का कहना है कि [illegible] पूर्णिया जिला भाजपा कार्यकारणी सदस्य संजय मिश्रा का कहना है कि [illegible] इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ज्योति रानी

मो. असरारुल हक़

संजय कुमार

उदय सिंह

किशनगंज को भारत का चिकेन नेक कहा जाता है, पड़ोसी मुल्कों की गिद्ध दृष्टि इस पर हमेशा लगी रहती है. यहां सीमा पार चीन की सीमावर्ती क्षेत्र में नए रेल और सड़क मार्गों के निर्माण से हलचल है. वहीं गलगलिया-अररिया रेल परियोजना का कार्य अधर में लटक गया है. देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ख़ुफ़िया रिपोर्ट में इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन मेची नदी पर एक पुल का निर्माण करवा कर ज़मीन अधिग्रहण का कार्य अधर में लटका हुआ है. गलगलिया-अररिया रेलवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण की राशि बंगाल स्थानांतरित हो गई. अंग्रेजों के ज़माने के अलुवाबाड़ी-गलगलिया रेलखंड को उपेक्षित कर दिया गया.

» एक नज़र «

छात्रों को रोजगार मिलेगा

मधुबनी शहर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आरके कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी. यह बात कम्यूनिटी कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉ. कुंवर जी राउत ने कही. उन्होंने बताया कि कॉलेज को रिटेल मैनेजमेंट हेल्थ केयर डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है. एक साल के डिप्लोमा कोर्स में शत-प्रतिशत जॉब गारंटी का यह कोर्स है. दोनों ही विषयों में बीस-बीस छात्रों का नामांकन होगा. डॉ. राउत ने बताया कि इन प्रोग्रामों की परीक्षा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, पटना परीक्षा आयोजित कर छात्रों को प्रमाण-पत्र देगा. इस डिप्लोमा कोर्स के साथ कम्यूनिटी कॉलेज में ग़रीब युवाओं के कौशल का विकास किया जाएगा, जिससे उन्हें सौ प्रतिशत रोजगार मिल सकेगा. **– नितेश कुमार**

जदयू नेता सम्मेलन में बरसे

बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद जदयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा से खटास की सच्चाई से लोगों को अवगत कराने का मुहिम शुरू कर दिया है. पिछले दिनों सीतामढ़ी शहर स्थित राजेंद्र भवन में आयोजित सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जनता दल (यू) ने कोई विश्वासघात नहीं किया है. पार्टी ने अमन और विकास का वादा लोगों से किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया. अब गठबंधन टूटने के बाद सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. शिवानंद तिवारी ने कहा कि भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता को किनारा कर नमो नाम का जाप करने लगी है. डुमरा प्रखंड जदयू अध्यक्ष प्रदीप सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह ने की. मौक़े पर सांसद अर्जुन राय, अनिल साहनी, कहकशा परवीन, पूर्व सांसद नवल किशोर राय, विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, विधायक डॉ. रंजू गीता, राम बालक पासवान, भरत प्रसाद, रामबली सिंह कुशवाहा, उपेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद यादव, मो जुनैद, गोपेशनंदन सिंह, अरुण कुमार गोप, शंकर बैठा, विकाइ महतो, उमेशचंद्र झा, किरण गुप्ता, नगर अध्यक्ष शोभा देवी समेत अन्य थे. वहीं परिहार प्रखंड के नरंगा जिलाध्यक्ष रामजीवन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं के अलावा प्रखंड अध्यक्ष शंभू शरण यादव, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष ईश्वर नारायण साह, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह व सुरेंद्र पटेल समेत अन्य थे. **– ब्रजेश**

वंदना को मुक़ाम मिला

किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर लगन व मेहनत सच्ची हो तो सफलता पाना मुश्किल नहीं है. सीतामढ़ी ज़िले के डुमरा प्रखंड के विश्वनाथपुर गांव निवासी जदयू नेता अरुण कुमार गोप की दूसरी पुत्री वंदना ने इस पंक्ति को सार्थक कर दिखाया है. हाल ही में एसबीआई में पीओ पद के लिए चयनित वंदना को प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजा गया है. शहरी ताम-झाम में उच्च शिक्षा की कवायद करने वालों के लिए सामान्य किसान परिवार की यह बेटी एक उदाहरण है. गांव के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने वाली वंदना वर्ष 2002 में स्थानीय कमला बालिका उच्च विद्यालय से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की. वर्ष 2007 में राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज से विज्ञान संकाय में 80.5 प्रतिशत अंक लाकर बाबा साहब बिहार विश्व विद्यालय में तीसरा स्थान पाने में सफल रही. सफलता पर कॉलेज में एक समारोह का आयोजन कर उसे डॉ. रेणु चटर्जी पुरस्कार से नवाजा गया. उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाख़िला के लिए चयनित वंदना को संस्था ने वर्ष 10-12 के पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट में 92 प्रतिशत अंक लाने पर गवर्निंग बोर्ड की ओर से गोल्ड मेडल दिया गया. रुलर मैनेजमेंट में तीसरा स्थान पाने पर पुन: गोल्ड मेडल दिया गया. वंदना की लगातार सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पिता अरुण कुमार गोप का कहना है कि बेटा-बेटी में अंतर मानने वालों को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए. प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, जो परिवार, समाज व राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकता है. **– अभिलाषा**

पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई

गोस्वामी स्वाभिमान सभा द्वारा मोतिहारी ज़िला स्कूल के मैदान में भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई. समारोह का उद्घाटन स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने किया. मंच का संचालन स्वाभिमान सभा के संस्थापक मुन्ना गिरी ने किया, जबकि अध्यक्षता योगेंद्र गिरी ने की. समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राधामोहन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया. उन्होंने गोस्वामी समाज से भी एकजुट होने की अपील की और कहा कि समाज को मिला आरक्षण अभी अधूरा है. यह समाज जब तक अति पिछड़ा में शामिल नहीं होता, तब तक सपना पूरा नहीं होगा. समारोह को विधायक सचिंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील मणि तिवारी, नेपाल के वन विभाग के चेयर मैन राम चंद्र गिरी, स्वाभिमान सभा के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ गिरी, अभय गोस्वामी, राजन गिरी, मनोज गिरी, सुभाष गिरी, प्रभुनारायण गिरी, विपिन गिरी, अशोक गिरी, चुन्ना गिरी, सुनील गिरी, ओंकार नाथ गिरी आदि ने संबोधित किया. इस अवसर पर सर्व सम्मति से विश्वनाथ गिरी को स्वाभिमान सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया. **– इंतेज़ारुल हक़**

नीतीश फेल हुए

उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव संजय वर्मा, रामबिहारी सिंह, प्रधान महासचिव शंभू कुशवाहा, विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव, पार्टी पदाधिकारी तारणी प्रसाद सिंह, मनोज यादव, नूरहसन आज़ाद, संजू प्रिया, रविरंजन चौधरी एवं सुदर्शन सिंह के साथ ज़िले का दौरा कर रहे है. नीतीश की आलोचना करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे संकुचित विचारधारा एवं मानसिकता तथा तानाशाही रवैये के कारण हर मोर्चो पर असफ़ल हो चुके हैं और आगामी लोक सभा चुनाव में भी असफ़ल होंगे. नीतीश कुमार ग़रीबों एवं मजदूरों के मान-सम्मान की रक्षा करने बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार मुहैया कराने में सर्वथा विफल रहे हैं. ■ **– संदीप कुमार**

बब्लू बनाएंगे-बिगाड़ेंगे कई समीकरण

जुबैर अंबारी

छातापुर विधायक नीरज कुमार (बब्लू) ने कटिहार कोर्ट में आत्मसर्मपण कर राजनीतिक गलियारे में जदयू के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है. सुपौल ज़िले में इसे लेकर तरह-तरह के चर्चाओं का बाज़ार गर्म है. बब्लू के विरोधियों को लंबे अर्से बाद उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलने का मौक़ा मिल गया है. एक चर्चा यह भी है कि बब्लू इधर खुल कर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के पक्ष में बयानबाज़ी कर रहे थे, जो आलाकमान को पसंद नहीं आया. मालूम हो कि सुपौल ज़िले में कुल पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और पांचों विधायक जदयू के हैं. वर्तमान सुपौल लोक सभा सीट पर जदयू के ही सांसद क़ाबीज़ हैं. छातापुर विधायक बब्लू सिंह के बारह साल बाद आत्मसर्मपन करना कई सवालों को जन्म दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के ज़िला उपाध्यक्ष तनवीर आलम का कहना है कि नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आने लगा है. इस बार यहां राष्ट्रीय जनता दल की ही जीत होगी. उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने जिस उम्मीद पर भाजपा से सत्रह साल का रिस्ता तोड़ा है, वह पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों के सच्चे रहनुमा लालू प्रसाद यादव ही हैं और मुस्लिमों का वोट राजद को ही जाएगा. वहीं लोजपा के दलित सेना ज़िला अध्यक्ष सह त्रिवेणीगंज लोजपा उम्मीदवार विजय पासवान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार दलित-महादलित को तोड़ने का काम किया है. इस बार आम चुनाव में जनता उन्हें क़रारा जवाब देगी. जदयू से जुड़े लोग किन-किन मामलों में शामिल हो रहे हैं, ये बातें अब सामने आने लगी हैं.

मुकेश कुमार

तनवीर आलम

बिजय कुमार

नीरज कुमार (बब्लू)

भूतपूर्व सांसद रंजीत रंजन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव का दौरा दिन-रात कर रही हैं. उनके पति राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जेल से बाहर हैं और जगह-जगह सभा कर फिर से राजनीति में नया भूचाल लाना चाहते हैं. पप्पू यादव के बाहर रहने से युवाओं में काफ़ी खुशी की लहर है. कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का आम चुनाव जदयू के लिए आसान नहीं है, जबकि युवा शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ़ पप्पू ने कहा कि सबसे निष्क्रिय सांसद विश्व मोहन कुमार हैं, जिन्हें जनता इस बार के चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा देगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का इस बार कोई जादू नहीं चलेगा. बहरहाल आम चुनाव में अभी छ: महीने का समय बाक़ी है. ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. विधायक नीरज सिंह के आत्मसमर्पण को लेकर एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले वह अपने ऊपर सभी मुक़दमों को ख़त्म करा लेना चाहते हैं, ताकि बेदाग़ होकर लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकें. गौरतलब है कि नीरज कुमार की पूरे ज़िले में बहुत ही मजबूत पकड़ है ओर अगर वह लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरते हैं तो मिथिलांचल में बहुत सारे नए समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं. फिलहाल इंतज़ार बब्लू के बाहर आने का हो रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जयकुमार और रामधनी आमने-सामने

ममता चौहान

विवादों से चोली दामन का संबंध रखने वाले रोहतास ज़िला जदयू में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है. पिछले चार महीने से जदयू में छाई खामोशी तुफान से पूर्व आने वाली तबाही की तरह दिख रही थी, जो अंतत: 13 सितंबर को नासरीगंज के कार्यकर्ता सम्मेलन में सतह पर आ ही गई. अचानक नोखा विधान सभा के इस सम्मेलन में कुछ कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और मंच पर मौजूद राज्य के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने लगे. पता चला कि ये लोग दिनारा विधान सभा क्षेत्र के दिनारा, सूर्यपुरा, और दावथ प्रखंड में जदयू के अध्यक्ष पद से हटाए गए लोग और उनके समर्थक हैं. बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. कार्यकर्ता सम्मेलन के बीच से ही विधायक रामधनी सिंह अपने समर्थकों के साथ निकल गए, उन्होंने समाचार पत्रों में एक बयान भी दिया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इन प्रखंड अध्यक्षों को हटाकर पार्टी संविधान के ख़िलाफ़ काम किया है.

अत: उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. मामला प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का नहीं था. बाद में पता चला कि पूर्व से ही दिनारा विधायक जयकुमार सिंह और करगहर विधायक रामधनी सिंह के बीच पार्टी के ज़िला संगठन को लेकर रस्सा-कस्सी चल रही थी, जिसे पाटने के लिए पार्टी आला कमान ने काराकाट के जिलाअध्यक्ष राजेश्वर राज को ज़िम्मेदारी दी थी, फिर भी स्थिति जस की तस बनी रही. चूंकि पहले से ही अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में प्रखंड अध्यक्षों के चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे थे. ज़्यादा सदस्य बनाने वाले लोग प्रखंड अध्यक्ष बनने से वंचित रहे तो कहीं जबरन कुछ लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी शिकायत जयकुमार सिंह की लॉबी ने पार्टी के निर्वाची पदाधिकारी ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानु जी से की थी. उसके बाद चुनाव को निरस्त करते हुए पूरी प्रक्रिया को प्रदेश नेतृत्व ने अपने हाथ में ले लिया था. उसी बीच करगहर विधायक रामधनी सिंह और उनके समर्थकों ने मंगल कुशवाहा को पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया, जिसे लेकर पार्टी का दूसरा धड़ा फिर प्रदेश नेतृत्व के पास पहुंचा. विवाद प्रखंड अध्यक्षों को लेकर था, इसलिए प्रदेश नेतृत्व नें जिलाध्यक्ष के रूप में राजेश्वर राज को मनोनित कर निर्देश दिया कि प्रखंड अध्यक्षों का निष्पक्ष चुनाव और मनोनयन करते हुए पार्टी पदाधिकारियों की एक संतुलित सूची जारी की जाए. जब सूची ज़ारी हुई तो इसमें कई प्रखंड अध्यक्ष और राज्य परिषद सदस्य के नाम भी शामिल थे, जिन पर पहले से ही विवाद चला आ रहा था. इसे लेकर एक बार फिर जयकुमार सिंह की लॉबी ने प्रदेश नेतृत्व का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके आलोक में दिनारा, सूर्यपुरा और दावथ के प्रखंड अध्यक्षों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को मनोनित कर दिया. फिर क्या था, रोहतास ज़िला जदयू में एक और घमासान शुरू हो गया. एक तरफ़ जदयू के वरीय विधायक रामधनी सिंह और उनके समर्थक खड़े दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ़ दिनारा विधायक जय कुमार सिंह और उनके समर्थक खड़े थे. उधर प्रदेश नेतृत्व से संकेत मिले हैं कि अभी भी सासाराम, नोखा और डेहरी विधान सभा के प्रखंड अध्यक्षों के अलावा चेनारी के राज्य परिषद सदस्य आदि के त्रुटिपूर्ण मनोनयन और चुनाव के ख़िलाफ़ पार्टी विचार कर रही है.

रामधनी सिंह

जयकुमार सिंह

अगर आलाकमान की तरफ़ से इन पदाधिकारियों पर गाज गिरी तो यह कार्रवाई आग में घी का काम करेगी, क्योंकि उन्हें मनोनित करने वाला धड़ा पूरा अक्रामक रूप अख्तियार किए हुए है, जिसकी एक बानगी विधायक रामधनी सिंह ने अख़बारों में बयान देकर प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफ़े की मांग करने के साथ अपने तेवर दिखा दिए हैं. इस मामले में जब विधायक रामधनी सिंह से संपर्क किया गया तो वे सीधे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के दबाव में आकर विधायक जय कुमार सिंह के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा किया गया कार्य बताते हैं. पहले दिन तो कई विवादित बयान आए थे, लेकिन बाद में रामधनी सिंह और उनके समर्थक कुछ संभलकर बोलने लगे, जिसे देखकर लगा की शायद ऊपर से कोई हिदायत मिली है. उधर विधायक जयकुमार सिंह कहते हैं कि पहले से ही संगठन में प्रखंड अध्यक्षों के चुनाव को लेकर गड़बड़ी हो रही थी, जो लोग बहुमत में थे, उन्हें हटाकर अल्पमत वालों को अध्यक्ष बनाया गया. इस पर अगर प्रदेश नेतृत्व ने क़दम उठाया है तो इसमें लोगों को क्या परेशानी हो रही है. प्रदेश नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है और आगे लेगा, वह वह सबको मानना पड़ेगा. चाहे कोई लाख छाती पीट ले. प्रदेश नेतृत्व से बड़ा न तो कोई विधायक है न ही जिलाध्यक्ष. विरोध करने वाले लोग पार्टी संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं. हम उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मधुबनी और झंझारपुर की तस्वीर धुंधली है

नीतेश कुमार

कोसी, कमला और बलान नदियों से त्रस्त मधुबनी ज़िला हमेशा से अपने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार रहा है. एक से एक दिग्गज यहां से चुने गए, पर यहां के हालात जस के तस रहे...

आज़ादी के बाद यहां के लोकसभा से पहले सांसद अनिरूद्ध सिंह थे. पहले समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा तीनों ज़िले एक थे और इसे लोग दरभंगा के नाम से जानते थे. मधुबनी लोकसभा के वर्तमान सांसद हुकुमदेव नारायण यादव हैं. यहां से बीजेपी से उनका एक बार फिर लड़ना लगभग पक्का ही माना जा रहा है. कांग्रेस से डॉ. शकील अहमद उम्मीदवार हो सकते हैं. राजद से अब्दुलबारी सिद्दीकी संभावित उम्मीदवार हैं. मधुबनी से जदयू संजय झा पर दांव लगा सकती है. नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आगामी लोकसभा चुनाव में हुकुमदेव नारायण यादव की स्थिति अच्छी मानी जा रही है. वैसे ब्राह्मणों की संख्या को देखते हुए जदयू के संजय झा भी उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं. अब्दुलबारी सिद्दीकी मुसलमानों के वोट पर और यादवों के समर्थन पर एक दमदार उम्मीदवार साबित हो सकते हैं. इस ज़िले में झंझारपुर भी एक संसदीय क्षेत्र है. इस क्षेत्र से कांग्रेस के किसी भी ब्राह्मण उम्मीदवार के होने की संभावना है. यदि ताराकांत झा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता चुनाव में उतरते हैं, तो ब्राह्मणों के अतिरिक्त अनेक जातियों के वोट भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं. जनता दलयू से अगर उदय कांत चौधरी जैसे कद्दावर नेता मैदान में आते हैं, तो वे भारी पड़ सकते हैं. राजद से मंगनी लाल मंडल के चुनाव लड़ने की चर्चा है. मंगनी लाल मंडल विद्वान और सर्वसुलभ नेता बिहार प्रांत में माने जाते हैं. देवेंद्र यादव आख़िर किस दल से चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसे लेकर भी यहां चर्चा गर्म है. उनकी दावेदारी से ही इस इलाक़े का चुनावी गणित समझने में आसानी होगी. जानकार बताते हैं कि ये दोनों नेता अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं. ये दोनों सही समय का इंतजार कर रहे हैं. हो सकता है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद तस्वीर कुछ साफ़ हो. वैसे सभी दलों ने अपनी-अपनी तैयारी मधुबनी और झंझारपुर में शुरू कर दी है. कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है. कांग्रेस भी इस इलाक़े में सबसे ज़्यादा सक्रिय है. वह भी चाहती है कि इन दोनों सीटों पर इस बार उसका झंडा लहराए, लेकिन कांग्रेस भी हवा का रुख़ अभी साफ़ होने का इंतज़ार कर रही है. ■

देवेंद्र यादव

मंगनीलाल मंडल

संजय झा

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

शिक्षक भीख मांगने को मजबूर हैं

नीतीश सरकार हो या पूर्व की सरकारें, सबों ने केवल उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया है और उनके भविष्य पर तलवार चलाया है. जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2008 में वित्तरहित विद्यालयों को वित्त संपोषित बनाकर छात्रों के परफॉरमेंस के आधार पर अनुदान देने का फ़ैसला लिया था और वर्ष 2009 में इन विद्यालयों को अनुदान की राशि आवंटित की थी, तब शिक्षकों व कर्मियों में एक बड़ी उम्मीद जगी थी और उन्हें लगा था कि शायद नीतीश की इस सरकार में वर्षों का उनका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई राशि नहीं आई. ऐसे में वे बदहाली की ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं. ऐसी बात नहीं है कि इन विद्यालयों के लिए राशि का आवंटन नही हुआ. राशि आवंटित तो हुई, लेकिन वह राशि अफ़सरशाही की भेंट चढ़ गई और जांच व अन्य कारणों के नाम पर उलझ कर रह गई.

अब आलम यह है कि आर्थिक तंगी से जुझते-जुझते ये शिक्षक व कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं और अपनी सच्चाई को आम जनता के सामने ला रहे हैं. शिक्षक दिवस के मौक़े पर एक तरफ़ सरकारी व गैरसकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में खुशी का माहौल था और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन को याद किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ़ ये शिक्षक कहीं भिक्षाटन कर रहे थे तो कहीं धरना पर बैठे हुए थे. भिक्षाटन में शामिल पूर्वी चंपारण ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित 38 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के बदहाल शिक्षकों व कर्मचारियों की यह हालत देख शहरवासी भी भौंचक्क रह गए और सरकार की वर्तमान शिक्षानीति पर सवाल खड़े करने लगे. भिक्षाटन कर रहे अनुदानित माध्यमिक शिक्षक संघ के राजेंद्र प्रसाद यादव, किशोरी शरण सिंह, प्रद्युम्न पांडेय, रामजी प्रसाद, रामजी पांडेय, मदन गोपाल चौधरी, सुरेश भगत, मो. इक़बाल हुसैन, जलंधर प्रसाद साथी, रामविनय प्रसाद, मो. हसीमुद्दीन एकाक अहमद, पुण्यदेव प्रसाद यादव व विभीषण प्रसाद यादव आदि सभी से जब इस बाबत पूछा गया तो उनकी आंखें नम हो गई और सरकार की इस शिक्षा नीति की वास्तविक स्थिति सामने आ गई. आख़िर सरकार व शिक्षा विभाग का रवैया इन शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों है? अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे है और जनता इस मुद्दे पर बहस भी एक दूसरे के साथ कर रही है. क्या इन शिक्षकों के पास अन्य विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की तुलना में योग्यता में कमी है या वे सरकारी नीति के अनुकूल नहीं हैं? अगर नही हैं तो सरकार को इस बाबत ठोस क़दम उठानी चाहिए, जबकि कड़वा सच यह है कि बोर्ड की परीक्षा में यहीं के छात्र अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और बेहतर अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रौशन करते हैं. दूसरी तरफ़ स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के संस्थापक सचिव कृष्णा प्रसाद बताते हैं कि अनुदान नहीं मिलने से शिक्षक अनेक कठिनाइयों से जुझ रहे हैं. राशि नहीं मिलने से उनके बच्चों की पढ़ाई तक ठीक से नहीं हो पा रही है. ■

भिक्षाटन करते शिक्षक

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
... CINERARIA MARITIMA REPL ...
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बीते दिनों खगड़िया नगर भवन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा लोकसभा संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था. उपेंद्र कुशवाहा के मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर रालोसपा ने सम्मेलन की शुरुआत की. इस मौक़े पर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तथा उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों के होठों पर मुस्कान हो, यही हमारा लक्ष्य है.

अलाउद्दीन बिस्मिल

दिलीप राय

मनोज कुमार

राम श्रेष्ठ खिरहर

शिव शंकर प्रसाद यादव

सीता राम यादव

सूर्यदेव राय

सीतामढ़ी

चुनावी तैयारी में राजद के दावेदार

बिहार में एनडीए -1 की सरकार ने विकास योजनाओं का ऐसा ख़ाका खींचना शुरू कर दिया कि राजद के पास सिवाय इंतज़ार करने का कोई विकल्प ही नहीं बचा, लेकिन एनडीए-2 के कार्यकाल ने सुस्त पड़ चुके राजद कार्यकर्ताओं को एक बार फिर अपना जौहर दिखाने का अवसर देना शुरू कर दिया. इससे लोकसभा चुनाव 2014 की दुंदुभी बजने के पहले ही एनडीए आपसी तक़रार के चलते दो फांक हो गया.

वाल्मीकि कुमार

लोकसभा चुनाव 2014 का समय जैसे-जैसे क़रीब आने लगा है संभावित प्रत्याशियों की चहलक़दमी भी बढ़ने लगी है. सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में एनडीए समर्थित जदयू के अर्जुन राय ने राजद के तत्कालीन सांसद सीताराम यादव को पराजित कर सीट पर क़ब्ज़ा कर लिया था. वर्ष 2010 के विधान सभा चुनाव में ज़िले के 8 में से एक सीट पर भी राजद को सफलता नहीं मिल पाई. एनडीए, जदयू व भाजपा ने चार-चार सीट पर जीत हासिल कर राजद का हौसला पस्त कर दिया. अब राजद कार्यकर्ताओं के पास कटी पतंग की तरह रहने की विवशता बन गई है. बिहार में एनडीए- 1 की सरकार ने विकास योजनाओं का ऐसा खाका खिंना शुरू कर दिया है कि राजद के पास सिवाय इंतज़ार करने के और कोई विकल्प ही नहीं बचा है, लेकिन एनडीए- 2 के कार्यकाल ने सुस्त पड़ चुके राजद कार्यकर्ताओं को एक बार फिर अपना जौहर दिखाने का अवसर देना शुरू कर दिया है. अब हालत यह है कि लोकसभा चुनाव 2014 की दुदुंभी बजने के पहले ही एनडीए आपसी तक़रार में दो फांक हो गया है. मौक़े की तलाश में बैठे ज़िला राजद में एक उत्साह का प्रवाह शुरू हो गया है. इसके साथ ही चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी भी शुरू हो गई है. पूर्व सांसद सीताराम यादव व राम श्रेष्ठ खिरहर, पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव जैसे पार्टी नेताओं की चुनावी तैयारी अघोषित रूप से चलने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी सुप्रीमो की चुनाव में युवाओं को मौक़ा देने की घोषणा ने युवा कार्यकर्ताओं को भी एक बार आजमाने का मौक़ा दे दिया है. वैसे पार्टी नेतृत्व टिकट किसे देती है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ज़िले की राजनीति में राजद के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार, प्रदेश युवा राजद के महासचिव दिलीप राय, सोनबरसा प्रखंड के दलकावा के दिलीप राय, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव तारकेश्वर प्रसाद यादव, युवा राजद जिलाध्यक्ष चंद्रजीत प्रसाद यादव के अलावा ज़िला राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अलाउद्दीन बिस्मिल समेत तक़रीबन एक दर्जन राजद कार्यकर्ताओं के दावेदारी की चर्चा है. मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गणेश प्रसाद यादव के भी सीतामढ़ी के चुनावी अखाड़े में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं. मजे की बात तो यह है कि अब तक चर्चाओं के केंद्र में रहने वाले अधिकांश कार्यकर्ता एक मात्र यादव जाति के ही है. इनमें एक वैश्य समाज के मनोज कुमार और अलाउद्दीन बिस्मिल हैं. पार्टी सूत्रों पर भरोसा करें तो चुनाव का समय क़रीब आने तक अभी और भी दावेदारों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. चर्चा है कि पुराने चेहरों से तंग आ चुके पार्टी कार्यकर्ता इस बार के चुनाव में नया और युवा नेतृत्व चाहता है. इस बार के चुनाव में राजद को भाजपा के प्रधानमंत्री पद के घोषित प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का विरोधी वोट भी मिलने की पूर्ण उम्मीद की जा रही है. साथ ही अल्पसंख्यकों के पूर्ण समर्थन की उम्मीद भी राजद कार्यकर्ताओं को है. चुनावी दौर शुरू होने के बाद भी वक़्त अभी काफ़ी है. सीतामढ़ी ज़िले में अपनी खोई ताक़त को वापस लाने को लेकर राजद नेतृत्व कौन सा पासा फेंकेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नए चेहरे की उम्मीद में संभावित प्रत्याशियों ने ख़ुद को आगे रखना शुरू कर दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बैरगनिया

जमुरा घाट बनेगा चुनावी मुद्दा

नाव से पार होते लोग

अनशन में शामिल लोग

विनोद कुमार

भारत-नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी ज़िले के बैरगनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर हुई 20 नवंबर, 1997 की घटना को भुलाया नहीं जा सकता. जब बागमती नदी पर पुल निर्माण समेत अन्य मांगों को लेकर भकुरहर निवासी स्वतंत्रता सेनानी बंशी साह ने आत्मदाह किया था. घटना के बाद उपजे आक्रोश का नतीजा यह हुआ कि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान दो व्यक्ति बब्लू व मुन्ना समेत तीन अन्य की मौत पुलिस की गोली से हो गई. साथ ही दर्जनों लोग घायल भी हुए थे, जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल का शिलान्यास कर बंशी सेतू का निर्माण कराया. इसके साथ ही सीतामढ़ी-शिवहर के बीच आवागमन का सुगम मार्ग प्रशस्त हो सका, लेकिन वोट की राजनीति ने बैरगनिया स्टेशन से महज 12 किलोमीटर दक्षिण स्थित बागमती व लालबकेया नदी के मिलन स्थल पर पुल निर्माण को एक सिरे से किनारा रखा. गुलामी के दिनों में भी अंग्रेजी सरकार ने सामरिक महत्व को देखते हुए उक्त स्थान पर पुल निर्माण की आवश्यकता समझी थी. अंग्रेजी सरकार का मानना था कि बैरगनिया से पूर्वी चंपारण के चकिया तक वनझूला नदी पर पुल निर्माण के बाद सैनिक पथ घोषित किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकतानुसार चीनी सेना को जवाब देने के लिए पटना-चकिया-बैरगनिया होते फौज भारत-नेपाल सीमा तक आसानी से पहुंच सके, लेकिन आज़ाद भारत में किसी भी सरकार अथवा जनप्रतिनिधि के लिए उक्त पुल निर्माण महत्वपूर्ण नहीं समझा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के उत्तर बिहार क्षेत्रीय समिति के संयोजक शत्रुघ्न साहू ने आंदोलन का ऐलान करते हुए पांच दिवसीय आमरन अनशन कर लोगों को जागरुक करने का काम किया है. ऐसा नहीं है कि इस स्थान पर पुल निर्माण को लेकर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन दुखद यह रहा कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र से लेकर पूर्व मंत्री राम दुलारी सिन्हा, स्व. हरि किशोर सिंह, पूर्व सांसद सीताराम सिंह, आनंद मोहन व मो अनवारुल हक़ समेत अन्य की सभा में यह मसला महज भाषण का हिस्सा ही बना रहा. और तो और वर्तमान भाजपा सांसद रमा देवी व क्षेत्रीय विधायक मोतिलाल प्रसाद ने तो उक्त स्थान पर पुल निर्माण को लेकर कसमें तक खाईं. बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मडपा मिशन के कार्यक्रम में जमुआ पुल बनाने का वादा जनता से किया था, लेकिन अब तक पुल निर्माण की दिशा में कारगर पहल नहीं की जा सकी है. आलम यह है कि लोगों को अब भी नाव के सहारे जान जोखिम में डाल कर नदी पार करने की विवशता बनी हुई है. गंभीर समस्या निदान को लेकर क्षेत्र की जनता अब एक मंच पर एकत्र होने लगी है. जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्से का इजहार करते हुए लोग आगामी चुनाव में मतदान न करने का भी मन बना रहे हैं. समस्या की गंभीरता को लेकर जटाशंकर आत्रेय, पुरन प्रसाद शाही, राज कुमार साह, रामाश्रय प्रसाद, सोनेलाल दिवाकर, अरविंद कुमार, जय प्रकाश सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, कासीम, हेरारुल हक़, जीतेंद्र प्रसाद, मो. इशा अंसारी, वार्ड सदस्य राजू देवी, सीमा जायसवाल, तारा देवी, चुन्नू देवी, गंगिया देवी, गीता देवी समेत सैकड़ों लोगों ने जनप्रतिनिधियों के झूठे वादों पर रोष का इजहार करते हुए आगामी चुनाव में प्रत्याशियों को सबक सिखाने का संकल्प लिया है. चुनाव के समय तक लोगों के संकल्प की दिशा क्या होगी? फिलहाल कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर लोगों की एकजुटता बनी रही तो किसी भी प्रत्याशी के लिए मामला सिरदर्द साबित हो सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया

उलझा चुनावी गणित

मनेन्द्र कुमार

खगड़िया संसदीय क्षेत्र में सभी दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. भाजपा व जदयू ने जहां विधानसभा सम्मेलन आयोजित कर अपने इरादे साफ़ कर दिए हैं, वहीं रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी दमदार उपस्थिति इस इलाक़े में दर्ज करा दी है. खगड़िया नगर भवन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा लोकसभा संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुशवाहा समाज की अत्यधिक भागदारी होने के कारण नगर भवन में जगह की कमी पड़ गई. आख़िर उपेंद्र कुशवाहा के मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर रालोसपा ने सम्मेलन की शुरुआत की. इस मौक़े पर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तथा उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों के होठों पर मुस्कान हो, यही हमारा लक्ष्य है.

कुशवाहा ने गठबंधन पर चर्चा करते हुए कहा कि हम अपनी शर्तों पर ही गठबंधन करेंगे. उपेंद्र कुशवाहा के सम्मेलन से खगड़िया में इस पार्टी की उपस्थिति ने कई दलों का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या इस संसदीय क्षेत्र में लगभग दो लाख है. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता धर्मेंद्र के द्वारा किए जा रहे मेहनत ने भी कई दलों के वोट बैंक में सेंध लगा दिया है. ऐसे तो धमाराघाट हादसा में सभी दलों ने अपनी-अपनी बातें रखी, लेकिन डॉ. विवेकानंद के नेतृत्व में धमारा स्टेशन पर जो अनशन हुआ, इससे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को विवश होकर उनकी मांग माननी पड़ी. इस अनशन में धर्मेंद्र, नागेंद्र सिंह त्यागी तथा लोक गायक सुनील छैला बिहारी समेत दर्जनों लोग थे. डॉ. विवेकानंद का कहना है कि मानसी-बदला-कोपरिया सड़क मार्ग तथा सोनवर्षा पुल की मांग को लेकर वर्षों से अनवरत आंदोलन जारी था, लेकिन अब जाकर जनता के सहयोग से इस मांग को मजबूरी में राज्य सरकार ने पूरा किया. आम आदमी पार्टी का खगड़िया लोकसभा से धर्मेंद्र को प्रत्याशी बनाना लगभग तय है. बता दें कि धर्मेंद्र को बीते विधानसभा चुनाव में खगड़िया विधानसभा से बारह हजार मत प्राप्त हुए थे. वहीं जदयू द्वारा आयोजित विधानसभा सम्मेलन तो अशुभ ही साबित हुआ, क्योंकि खगड़िया विधानसभा सम्मेलन के दिन दो समुदायों के बीच संघर्ष ने पूरे राजनीतिक माहौल को बिगाड़ दिया. अलौली विधानसभा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट तथा स्थानीय लोगों का विरोध खुलकर सामने आया. आख़िरकार जदयू को इस बात से सबक लेना होगा, क्योंकि बीते चुनाव का

गणित जदयू के पास नहीं है और अपने ही दलों के लोगों का सांसद के प्रति विरोध आने वाले चुनाव की सफलता में खलल पैदा कर सकता है. चाहे मामला जो भी हो, लेकिन आने वाले संसदीय चुनाव में जदयू की राह आसान नहीं है. वहीं राजद तथा भाजपा के द्वारा गांव-गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है. भाजपा अलौली, परबत्ता, बेलदौर के विधानसभा सम्मेलन आयोजित कर चुनावी शंखनाद शुरू कर चुकी है. भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की घोषणा होने के बाद युवाओं का आकर्षण भाजपा की ओर बढ़ा है. भाजपा मोदी के नेतृत्व में खगड़िया लोकसभा चुनाव अपार बहुमत से जीतेगी. वहीं राजद के अंदर टिकट को लेकर मारा-मारी की नौबत है, लेकिन यहां परबत्ता विधायक राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है. हालांकि आम आदमी पार्टी तथा रालोसपा का चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से ज़िले का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. साथ ही साथ कई दलों का जातीय गणित भी बिगड़ गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

30 सितंबर–06 अक्टूबर 2013

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

अजय कुमार

सपा के काम आए बसपा के वफादार

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की हालत बदतर होने के बाद बसपा राज से सबक़ लिया जा रहा है. अनुभवी और होशियार अफसरों की तलाश हो रही है. हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलें. बसपा राज में कौन आईपीएस कहां था, किस बसपा नेता के क़रीब था, अखिलेश सरकार के लिए यह बात अब गुज़रे ज़माने की हो सकती है. अब अफसर की क़ाबिलियत और अनुभव को महत्वपूर्ण तैनाती का आधार बनाया जाएगा. किसी भी क़ीमत पर क़ानून व्यवस्था में सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता है.

उत्तर प्रदेश सुलग रहा है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे सांप्रदायिक दंगों, बिगड़ती कानून व्यवस्था, समाज में तनाव बढ़ाने वाले फैसलों, पार्टी के वफादार नौकरशाहों की मनमानी, ईमानदार अफसरों को बिना वजह के कटघरे में खड़ा करने की सरकारी साजिश से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अनुभवहीनता और उनके करीबी अधिकारियों की दगाबाजी और सरकार को गुमराह करने की फितरत ने युवा सीएम को कहीं का नहीं छोड़ा है. स्थिति यह है कि अखिलेश सरकार के कई मंत्री, मठाधीशी करने वाले नौकरशाह और पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री से गाइड होने की बजाय स्वयं उन्हें गाइड कर रहे हैं. मुख्यमंत्री को आधी–अधूरी जानकारी दी जाती है. ऐसा कई मौकों पर देखने में आया है. चाहे निलंबित आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल का मामला हो या फिर मुजफ्फरनगर हिंसा का मामला अथवा अन्य कई मसलों पर सही और सटीक जानकारी नहीं मिलने के कारण अखिलेश को बैकफुट पर जाकर कई फैसलों को बदलना पड़ जाता है. वोट बैंक साधने के चक्कर में अखिलेश अपनी सरकार चलाने की जिम्मेदारी तक भूल गए हैं. इसी कारण दागियों को गले लगाया जा रहा है और ईमानदारों को हाशिये पर डाला जा रहा है. नौकरशाहों और पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग उनकी जात देखकर की जाती है, न कि काम देखकर. इसी का खामियाजा मुजफ्फरनगर में सपा सरकार को भुगतना पड़ा. दंगा प्रभावित इलाके शामली में पुलिस अधीक्षक (आईपीएस) की कुर्सी पर बैठे अब्दुल हमीद अगर धर्म का ठेकेदार बनने की जगह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो हो सकता है कि छोटी सी छेड़छाड़ की घटना के बाद हुई तीन मौतों का मामला इतना तूल न पकड़ता, लेकिन हमीद को तो अपने राजनीतिक आका पर भरोसा था कि वह कुछ भी करेंगे, उनको राजनीतिक शरण मिल जाएगी. एसपी साहब खुले आम लोगों से कहते थे, मैं आईपीएस बाद में हूं, पहले मुसलमान हूं. शायद अब्दुल को अपनी जिम्मेदारी और सच्चा मुसलमान क्या होता है, दोनों ही बातों का ज्ञान नहीं है. अन्यथा इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते.

शामली और कवाल में छेड़छाड़ के बाद हत्या और फिर इस पुलिस अफसर की लचर भूमिका ने दंगे को भड़का दिया. सवाल प्रदेश सरकार पर उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को पनाह कौन दे रहा है? अब्दुल हमीद की दंगे में मारे गए आईबीएन–7 के पत्रकार से भी कुछ दिनों पूर्व झड़प होने की चर्चा है. इसी तरह से सफाईकर्मियों और अल्पसंख्यकों के बीच भी एक बार तनाव पैदा हो गया था. हमीद ने तब भी एकतरफा कार्रवाई की थी, बाद में मामला काफी बढ़ गया और एडीजी को लखनऊ से जाकर मामला संभालना पड़ा. हमीद बसपा राज में लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र के एसपी हुआ करते थे. तब भी उनकी छवि कुछ ऐसी ही थी, लेकिन तत्कालीन एडीजी लॉ एंड आर्डर बृजलाल इन पर लगाम लगाए रहते थे. उनकी ऐसी ही छवि औरैया और हापुड़ में तैनाती के दौरान भी कई बार सामने आई. कुछ दिनों पूर्व ही हमीद को शामली से (सफाईकर्मियों और मुसलमानों के बीच झगड़े के बाद) और बाराबंकी के एसपी वसीम अहमद को बाराबंकी से एसपी पद से हटाया गया था. हमीद को पीएसी में नई तैनाती मिली थी, लेकिन मंत्री आज़म ख़ान से हमीद की क़रीबी के कारण एसपी का तबादला रुक गया था, लेकिन दंगे के बाद जब अखिलेश सरकार को यह लगने लगा कि विवादित छवि के कारण एसपी को शामली से हटाना जरूरी है तो उन्हें सरकार ने चलता कर दिया. आज़म की नाराज़गी की एक वजह यह भी है. हमीद को शामली से चलता कर दिया गया और उनके इशारे पर लिखाई गई एक एफआईआर (छेड़छाड़ की शिकार युवती के घर वालों के खिलाफ) को भी रद्द कर दिया गया. इसी कारण वह सरकार से दूरी बना कर चल रहे हैं. वहीं वसीम का भी तबादला पीएसी से संशोधित करके शाहजहांपुर के एसपी के पद पर कर दिया गया था.

मुजफ्फरनगर और शामली में अब हालात सुधरने लगे हैं. इसका सारा श्रेय इन अधिकारियों को जाता है, जिनकी बसपा राज में क़ानून व्यवस्था को लेकर तूती बोला करती थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके करीबियों से फीडबैक मिला कि उन अफसरों के कंधों पर बिगड़े हालात संभालने का जिम्मा सौंप जाए, जो अनुभवी हों. ये वही अफसर थे, जिनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी अहमियत दी थी. मेरठ जोन भेजे गए एडीजी तकनीकी सेवाएं भवेश कुमार बसपा सरकार में भी आईजी क़ानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं. आईजी मेरठ के दौरान ही एडीजी पद पर प्रोन्नत हुए थे. अनिल राय भी इस वक्त एएसपी फैज़ाबाद थे और अभी जल्द ही आईपीएस बने हैं. सहारनपुर के कमिश्नर बनाए गए भुवनेश कुमार भी मेरठ के डीएम और कमिश्नर रह चुके हैं.

कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होने के बाद बसपा राज से सबक लिया जा रहा है. अनुभवी और होशियार अफसरों की तलाश हो रही है. हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलें. बसपा राज में कौन आईपीएस कहां था, किस बसपा नेता के करीब था, अखिलेश सरकार के लिए बात अब गुजरे ज़माने की हो सकती है. अब अफसर की काबिलियत और अनुभव को महत्वपूर्ण तैनाती का आधार बनाया जाएगा. किसी भी क़ीमत पर कानून व्यवस्था में सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता है.

बसपा का पांच वर्षों का कार्यकाल दंगाविहीन रहा था. उनके राज में मात्र दो–चार वारदातें ही हुई थीं, लेकिन इस पर भी मुस्तैदी के साथ नियंत्रण कर लिया गया था. बरेली में सांप्रदायिक दंगा और आगरा सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों अलीगढ़ (टप्पल), भट्टा पारसौल, मुरादाबाद में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों के आंदोलन के दौरान भी थोड़ा बहुत तनाव फैला था, लेकिन यह मामला राजनीतिक ज़्यादा था.

बहरहाल, नई तैनाती की बात की जाए तो मेरठ जोन के एडीजी बनाए गए भवेश कुमार बसपा सरकार में ही प्रतिनियुक्ति से लौटे थे, तब डीजीपी बृजलाल हुआ करते थे. भवेश कुमार आईजी कानून व्यवस्था के पद पर थे. मेरठ के आईजी रहे और वहीं तैनाती के दौरान ही एडीजी पद पर प्रोन्नति मिली. हालांकि सपा सरकार में भी उन्हें शुरुआत में अच्छी तैनाती मिली, लेकिन फिर उनपर बसपा करीबी होने का ठप्पा लगवाकर कुछ नेताओं ने किनारे करवा दिया था. पीसीएस से आईपीएस बने अनिल राय पूर्व बसपा सरकार में एएसपी फैजाबाद थे. मुजफ्फरनगर में दंगे को नियंत्रित करने के लिए जिन तीन आईपीएस को भेजा गया, उन पर भी पूर्व बसपा सरकार के करीबी होने का ठप्पा लगा था. मुसीबत में इन अधिकारियों पर

(शेष पृष्ठ 18 पर)

बेनी बाबू आज भी मुलायम पर आग बबूला हैं

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में खनन माफियाओं द्वारा लोनी कटरा थाना क्षेत्र में एक बीडीसी की हत्या के प्रकरण को लेकर इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मुलायम को खरी–खरी सुनाई. एक समय कुर्मियों पर एकछत्र अधिकार रखने वाले बेनी वर्मा मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे. राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुलायम सिंह अच्छे मित्र हैं, दोस्ती निभाते हैं तो अंत तक निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि कोई इनसे ज्यादा बड़े होने की हिमाकत दिखाए तो वे कभी उसकी इस गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. वे बिना कुछ कहे–सुने ही उसके पर कतरने में देर नहीं लगाते. चाहे वे अमर सिंह रहे हों या बेनी वर्मा. इन दोनों ही नेताओं ने इनकी राजनीति में चार चांद लगा दिए. उनको मजबूत करने में कोई कोताही नहीं की. सपा को उठाने में उनका प्रमुख हाथ माना जाता है, लेकिन यह वक्त–वक्त की बात है कि आज सपा में न तो बेनी हैं और न ही अमर सिंह. बेनी बाबू तो मुलायम सिंह को दगेबाज नेता मानते हैं. मौकापरस्त बताते रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने पलटकर उनकी ओर नहीं देखा और न ही उनको तरजीह ही दी. हां, एक बार जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया था, जब बेनी ने मुलायम पर आतंकवाद के मामले में टिप्पणी की थी, इसके लिए मुलायम सिंह ने बेनी को आड़े हाथों लेते हुए संसद में आवाज उठाई थी. इस पर स्वयं सोनिया गांधी ने अपनी सीट से उठकर सपा प्रमुख को समझा बुझाकर शांत किया था. इसलिए कि कांग्रेस को समर्थन देने वालों में मुलायम बहुत अहम हैं. कांग्रेस पर उनका एहसान है. बाद में कांग्रेस के दबाव के चलते बेनी को माफी मांगनी पड़ी थी. बाद में बेनी बाबू विदेश यात्रा पर चले गए थे. बेनी बाबू कभी मुलायम सिंह के इतने मुरीद हो जाते हैं कि उनके कसीदे पढ़ने लगते हैं और उनके बेटे अखिलेश को अपना भतीजा समझने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें मुलायम सिंह द्वारा की गई दगाबाजी की याद आ जाती है तो वह मुलायम को खरी–खोटी सुना डालते हैं.

बाराबंकी में पहली बार बेनी के साथ संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मंच साझा किया. बेनी ने कहा कि मैं शरीर से बूढ़ा जरूर हो गया हूं, पर मेरा दिल अभी जवान है. मैं इस आंदोलन को प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद ही खत्म करूंगा. मुलायम सिंह यादव मुलायम साजिशकर्ता हैं. शायद ही उनका कोई ऐसा सहयोगी रहा हो, जिसकी पीठ में छूरा न भोंका हो. मुलायम ने आडवाणी से सांठगांठ करके उत्तर प्रदेश में दंगे कराए थे, अब उन्होंने मोदी से हाथ मिला लिया हैं. बेनी वर्मा ने कहा कि अयोध्या में कारसेवकों को उत्तेजित करने के साथ थाना रामजन्म भूमि बनाने का काम भी मुलायम सिंह यादव ने किया. इस बार मुसलमानों के दम पर उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभाली है, मगर डेढ़ वर्ष में लगातार दंगे व सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल कराकर ये सरकार अल्पसंख्यकों को दहशत में रखना चाहती है. उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने ही जौरास में खनन रोकने वाले कुर्मी बिरादरी के राममनोरथ की हत्या करा दी. अब उन्हें पांच लाख के मुआवजे के रूप में

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

बेनी बाबू आज भी मुलायम पर आग बबूला हैं

पृष्ठ 1 का शेष

रिश्वत दी जा रही है. सीबीआई जांच के अलावा कुछ मंजूर नहीं है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे स्वयं आमरण–अनशन पर बैठेंगे. प्रधानमंत्री का सपना देख रहे मुलायम सिंह की जनता लोकसभा चुनाव में ही राजनीतिक विदाई कर देगी. पहली बार बेनी ने खुलासा किया कि वे 1992 में ही सपा छोड़ने को तैयार थे. जब भाजपा और विहिप नेताओं के साथ सांठगांठ करके मुलायम ने अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिरा दिया और बाद में मुसलमानों को भरमा कर उनका वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल कर ली थी. मुलायम ने मुसलमानों को आरक्षण आदि के झूठे वायदे करके धोखा ही दिया है. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा सपा का प्रायोजित दंगा था. उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन वह केंद्र सरकार से सपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग नहीं करेंगे. उन्होंने साफ–साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया और उनकी बहू डिम्पल के अलावा कोई भी सपा उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला नहीं हैं. उन्होंने व्यंग्य किया कि प्रदेश सरकार संभालने में असमर्थ रहे लोगों को केंद्र में प्रधामनंत्री बनने का सपना नहीं देखना चाहिए. मुसलमानों के घर फूंके जा रहे हैं. मोदी और मुलायम एक राशि हैं. राष्ट्रपति शासन लगाने के सारे कारण मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनको यह कलंक मोल लेना पड़े. सपा सरकार का पतन खुद हो जाएगा. बहरहाल, बेनी के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय बने रहे पीएल पुनिया, जो कांग्रेस के सांसद भी हैं. पुनिया ने 15 सितंबर को अपने आवास पर पत्रकारों से इस कार्यक्रम में पहुंचने का वायदा किया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा के काम आए बसपा के वफादार

पृष्ठ 1 का शेष

सरकार ने भरोसा जताया तो यह लोग भी पूरी तरह से सरकार की कसौटी पर खरे साबित हुए. तीन आईजी स्तर और तीन एसपी स्तर के अफसरों को मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के दंगाग्रस्त इलाके में भेजा गया. पुलिस महानिरीक्षक एटीएस राजीव सब्बरवाल को मुजफ्फरनगर, अभय कुमार प्रसाद को शामली, जेएनसिंह को बागपत और चंद्रप्रकाश को सहारनपुर की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. इसके अलावा राजू बाबू सिंह और विजय भूषण को भी यही ज़िम्मेदारी दी गई. डीजी पद पर तैनात एक आईपीएस कहते हैं कि हालात इतने भयावह न होते, यदि अफसर समझदारी से काम लेते. धर्म और जाति में न फंसकर एक आईपीएस की भूमिका में रहते तो दंगे की नौबत न आती. बसपा राज में अच्छा काम करने वाले आईपीएस अधिकारियों रघुवीर लाल, चंद्र प्रकाश, विजय भूषण, ब्रजभूषण शर्मा, प्रवीण कुमार, दीपक रतन को उनके कामों के लिए फिर याद किया जा रहा है. बसपा राज में नाम कमाने वाले अशोक मूथा जैन को डीआईजी सहारनपुर की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है. बसपा राज में अपनी हनक और धमक से अपराधियों में ख़ौफ़ पैदा करने वाले मायावती के करीबी बृजलाल की भी चर्चा हो रही है. ऐसे समय क़ानून व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त रखने में बृजलाल की भूमिका अहम हुआ करती थी. कई मौक़ों पर तो सरकार की तरफ़ से तत्कालीन डीजीपी करमवीर सिंह से अधिक अहमियत बृजलाल को मिलती दिखती थी. 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती सपा के जंगलराज को मोहरा बना कर ही सत्ता की सीढ़िया चढ़ी थीं. यही वजह थी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बसपा राज में कई नये प्रयोग भी देखने को मिले थे. माया ने पुलिस महकमे को काम करने की पूरी छूट दे रखी थी, वह सिर्फ नतीजों पर नजर रखती थीं. सत्ता शुरुआत मायावती ने अपने ही सांसद उमाकांत को अपने घर से गिरफ्तार कराके की, जिसका प्रभाव उनके पूरे कार्यकाल में देखने को मिला. … तो की, लेकिन खोई हुई साख अखिलेश कहां से लाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया साप्ताहिक अखबार के सफलतम प्रकाशन पर हार्दिक शुभकानाएं

- डी.पी. यादव, राष्ट्रीय महासचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- जे.पी. सिंह, राष्ट्रीय सचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- मूरत राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैंपेन फॉर मनरेगा
- डॉ राजेश कुमार यादव, प्रभारी, आरटीआई टास्कफोर्स उत्तर प्रदेश
- डॉ शैलजा राय, अध्यक्ष, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- संगीता जायसवाल, महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- सरोज पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग)
- ओमकार नाथ मेहता, एडवोकेट
- हंसराज तिवारी एडवोकेट, कानूनी सलाहकार हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति)

संस्था का सदस्य बनने अथवा संस्था के विषय में जानकारी के लिए संपर्क करें
Email : awsar3334@gmail.com
अथवा कॉल करें 09455209120, 09453517597,07668952813

सपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय समिति संपन्न

आज़म ने बिगाड़ा आगरा का समां

संजय सक्सेना

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ठीक एक वर्ष बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा मोहब्बत की नगरी आगरा में देखने को मिला. मौका था समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक का. विश्व प्रसिद्ध ताजनगरी आगरा में देश की वर्तमान आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से पार्टी की रणनीति पर विचार करने के लिए जब यहां समाजवादी नेता जुटे तो उनके चेहरे पर तनाव था. दोनों ही दिन इस तनाव ने सपा नेताओं का पीछा नहीं छोड़ा. पिछले वर्ष कोलकाता में जो खुशी का माहौल था, वह एक वर्ष में काफूर हो चुका था. समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक आगरा समाजवादियों का सबसे अधिक पसंदीदा स्थान रहा है. यह और बात है कि मोहब्बत की नगरी आगरा में आजम खान की गैर मौजूदगी ने बैठक का माहौल खराब कर दिया. खैर, आगरा में सबसे ज्यादा बार सपाई एकत्रित हुए हैं. जनवरी, 1996 एवं जुलाई, 2000 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मार्च, 2003 एवं अगस्त, 2009 में विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन और जून 2011 में राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में हो चुके हैं. आगरा में सपा के कई रंग अतीत में देखने को मिले हैं. मुलायम के धुर विरोधी कल्याण सिंह की आश्चर्यजनक रूप से समाजवादी मंच पर उपस्थिति, समाजवादी सोच के विपरीत पंच सितारा होटलों में सपा के कार्यक्रमों की शुरुआत, कल्याण के सपा के करीब आने के बाद आजम खान की नाराजगी, एक दौर में अमर सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी को हाईजैक कर लेने का आरोप, 2011 में अखिलेश को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में आगे करने की चर्चा, मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश की धर्मपत्नी डिंपल यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाने जैसे तमाम अहम फैसलों और सपा के उतार–चढ़ाव का आगरा मूक गवाह रहा है.

अबकी बार भी सपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक चर्चा में है, लेकिन इस बार सपा नेताओं में विपरीत विचारधारा बह रही है. एक वर्ष पूर्व कोलकाता में अखिलेश को लेकर समाजवादियों में उत्साह था. वह उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे और उनका सपना पूरा हो गया था. मगर अब युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाकामी ने सपा के एक धड़े को यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि अखिलेश को कमान सौंप कर नेताजी ने कोई गलती तो नहीं कर दी. अनुभव की कमी अखिलेश के आड़े आ रही है. वह यही नहीं समझ पा रहे हैं कि राजनीति करना और सरकार चलाना दोनों अलग–अलग मसले हैं. अखिलेश की अनुभवहीनता, आजम खान की बैठक को लेकर बेरुखी, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का आजम खान की अनुपस्थिति को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया, प्रदेश में बढ़ता दंगा–फंसाद, लचर कानून व्यवस्था, मुस्लिम संगठनों का […]

> अखिलेश यादव की नाकामी ने सपा के एक धड़े को यह सोचने को मजबूर कर दिया हैं कि अखिलेश को कमान सौंप कर नेताजी ने कोई गलती तो नहीं कर दी? अखिलेश यही नहीं समझ पा रहे हैं कि राजनीति करना और सरकार चलाना दोनों अलग-अलग मसले हैं. अखिलेश की अनुभवहीनता, आजम खान की बेरुखी, सपा महासचिव राम गोपाल द्वारा आजम पर कड़ी प्रतिक्रिया, बढ़ते दंगे-फंसाद, लचर कानून व्यवस्था आदि समाजवादी पार्टी नेतृत्व के लिए मुसीबत का सबब हैं.

[…] दी. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ–साथ लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का रास्ता साफ कर दिया. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की योजना पुन: प्रारंभ कर दी. जेल में बंद बेकसूर मुसलमान युवकों की रिहाई की योजना पर अमल किया. व्यापारियों एवं दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई. […] ■

feedback@chauthiduniya.com

आतंकी खालिद–कासिमी को क्लीन चिट का मामला

निमेष आयोग के फैसले से गदगद सपा सरकार

अजय कुमार

संकट से जूझ रही समाजवादी सरकार के हाथों में निमेष आयोग ने एक नया हथियार थमा दिया है. सपा की बल्ले–बल्ले हो गई है. निमेष आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सीरियल बम ब्लास्ट में पकड़े गए दो आतंकी निर्दोष थे. उन्हें साजिशन फंसाया गया था. रिपोर्ट आने के बाद सपाई ताल ठोंककर कर कहने लगे हैं कि जेल में बंद बेगुनाह अल्पसंख्यक युवाओं को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा. सपा खुश होकर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सपा नेताओं को इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि माया राज में गठित इस एक सदस्यीय आयोग ने आतंकी खालिद और कासिमी को क्लीन चिट देकर सपा के पंखों को उड़ान दे दी है. दूसरी ओर बसपा शासनकाल में गठित किए गए निमेष आयोग की रिपोर्ट ने आतंकवाद पर नई बहस और राजनीति छेड़ दी है. उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जहां सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद के नाम पर भी खूब राजनीति होती है. कोई पक्ष में खड़ा दिखाई देता है तो कोई विरोध में. मकसद एक ही होता है, किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा उठाना. खासकर, समाजवादी सरकार पर तो अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि वह आतंकवाद और दंगों के नाम पर खूब राजनीति करती है. भाजपा को सपा की यह करतूत रास नहीं आती है. वह सपा के इस रवैये को अक्सर ही तुष्टीकरण की राजनीति करार देती है. वहीं कांग्रेस और बसपा भले ही अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करने में पीछे न रहती हों, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बच के निकल जाने का रास्ता उन्हें ज्यादा रास आता है. चाहे बात मुजफ्फनगर दंगों की हो या फिर अयोध्या […] ■

feedback@chauthiduniya.com

मैं राखी धर्म पूरी तरह निभाऊंगी : जयाप्रदा

दर्शन शर्मा

सपा के लिए लगातार असुविधा का कारण बन रहे आजम खान चौतरफा घिरते नजर आए तो रामपुर की सांसद जयाप्रदा का भाई प्रेम उमड़ पड़ा. अपने मुंह बोले भाई आजम खान को राखी बांधने वाली जया उनके लिए मुखर हो उठी हैं. उनका कहना है कि इस नाजुक समय में वह उनके साथ हैं. भले ही उनका आजम के साथ 36 का आंकड़ा क्यों न रहा हो. जया प्रदा का कहना है कि मैं अपने भाई के उन एहसानों को कभी नहीं भुला सकती. मुझे वह दिन आज भी याद है जब वह मुझे पहली बार रामपुर लेकर आए थे. मैं जया बच्चन नहीं हूं, जिन्होंने अमर सिंह के एहसानों को भुलाकर उन्हें दरकिनार कर दिया. भाई आजम ने सपा के लिए क्या नहीं किया. वह सपा के संस्थापक सदस्य हैं. एक तरह से पार्टी के मालिक हैं. उनके लिए रामगोपाल और नरेश अग्रवाल टिप्पणी कर रहे हैं. यह शोभा नहीं देता. नरेश अग्रवाल से बड़ा मौकापरस्त कोई नहीं, वे तो नेताजी को छोड़कर बसपा में चले गए थे. मैं भाई की पीड़ा को समझ रही हूं. मुझे जब पार्टी से निलंबित किया गया था तो बहुत दुख हुआ था. मुलायम सिंह, रामगोपाल, नरेश अग्रवाल तो मौकापरस्त लोग हैं. गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए लोगों के प्रति आजम खफा इसलिए हैं कि सरकार के अफसरों ने दंगे को दबाने के लिए त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की. सरकार में मंत्री होने के बावजूद आजम ने कानून व्यवस्था को […]

[…] ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है महाराजगंज

पूजा श्रीवास्तव

जनपद महाराजगंज घोषित होने के 14 वर्ष बाद भी पिछड़े जिले में शुमार किया जाता है, जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद नेपाल और बिहार से सटा है. भारत नेपाल को जोड़ने वाला कृषि प्रधान महत्वपूर्ण जिला है. जिले में विकास गंगा–यमुना बहाने वाले जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार है. यदि एक नजर में यहां की प्रशासकीय मशीनरी पर नजर डाली जाए तो शासन की कलई भी खुलती नजर आ रही है. जिले में विकास कार्यों का संपादन करने वाले अधिकारीविहीन इस जिले पर महीनों बाद मुख्य विकास अधिकारी की पोस्टिंग माह सितंबर में हुई. इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दुग्ध विकास प्रबंधक, सहायक निदेशक बचत तथा जिला कृषि अधिकारी विहीन है. वहीं समाज कल्याण अधिकारी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी आदि महत्वपूर्ण विभाग प्रभारियों के भरोसे चलाए जा रहे हैं. इसे प्रभारियों की साजिश कहा जाए कि प्रशासनिक उपेक्षा. या फिर […] ■

> जिले की मशीनरी पर नजर डाली जाए तो कलई खुल जाती है. यहां विकास कार्यों को चलाने वाले अधिकारी नहीं हैं. अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दुग्ध विकास प्रबंधक, सहायक निदेशक, बचत तथा जिला कृषि अधिकारी भी नहीं हैं. समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी आदि महत्वपूर्ण विभाग प्रभारियों के भरोसे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

बेरोजगारों के लिए सरकार की पहल

दर्शन शर्मा

युवाओं के बल पर बनने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए जुट गई है. प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज करीब 70 लाख बेरोजगारों के लिए सरकार कौन सा रास्ता अख्तियार करे, इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश चिंतित थे. इसलिए उन्होंने उपायों पर अमल करते हुए प्रदेश की कौशल विकास नीति को मंजूरी दे दी है. प्रदेश में इस नीति की बदौलत करीब 45 लाख युवाओं को रोजी–रोटी कमाने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त होंगे. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन के अनुसार, प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की भारी संख्या को देखते हुए समुचित रणनीति बनाई गई है. सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कौशल विकास नीति बनाई है, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है. प्रदेश के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है कि यह अनुमोदन औद्योगिक घरानों की सहमति का आधार बनाकर किया गया है.

एलएंडटी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजन मल्होत्रा, संजू जॉन, मारुति के महाप्रबंधक एमके गुप्ता और एकेडेमिक्स की निदेशक अंजनी सिंह से काफी विचार विमर्श के बाद इसको अमलीजामा पहनाने की पहल शुरू हुई है. इससे प्रदेश के नवयुवकों के भविष्य […] ■

feedback@chauthiduniya.com

तबाह हुए प्रदेश में नेताओं की मौजमस्ती

राजकुमार शर्मा

उत्तरखंड में दून स्थित यमुना कालोनी स्थित कांग्रेस के मंत्री का सरकारी आवास इन दिनों अपराध के अड्डे के रूप में सुर्खियों में है. उत्तराखंड के मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के यमुना कालोनी स्थित आवास पर विधानसभा सत्र की शुरुआत से ठीक पहली रात्रि हुई गोलीबारी की घटना ने भाजपा को बैठे–बिठाए एक नया मुद्दा थमा दिया है. खासकर सत्तापक्ष के ही एक विधायक और दर्जा प्राप्त मंत्री का नाम आरोपी के तौर पर सामने आने से भाजपा अब इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है. पार्टी ने इस मसले को कांग्रेसी नेताओं के अराजक रवैये व कानून व्यवस्था से जोड़कर सदन में उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा. इस मामले में बहुगुणा सरकार की वरिष्ठ मंत्री इंदिरा हृदयेश ने जिस तरह आरोपी नेता को बचाने के लिए बयान दिया, इससे पूरी सरकार की मंशा की कलई खुल गई है. इंदिरा ने कहा कि यह एक जश्न में मनने वाली सामान्य घटना है, जिसमें विधायक द्वारा गैर इरादतन गोली चलाई गई, जो पार्टी के नेता को लगी, जिसे गोली लगी, उन्हें कोई कार्रवाई की दरकार नहीं है, फिर कार्रवाई क्या की जाए.

उनके इस बयान की चारों ओर किरकिरी हो रही है. ऐसे समय में जब पूरा राज्य आपदा झेल रहा है, कांग्रेस के नेता जश्न मना रहे हैं. मंत्री जी ने स्वयं अपने बयान में सरकार द्वारा जश्न मनाने की बात स्वीकार कर सरकार का संकट […]

>
>
> मंत्री आवास में फायरिंग की घटना बताती है कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति पंगु है. सत्तापक्ष के एक विधायक का गोली चलाना साबित करता है कि इस राज्य में कांग्रेसी निरंकुश होकर कानून को पैरों तले रौंद रहे हैं. सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए. सदन में हम जनता की ओर से सरकार से जवाब मांगेंगे.
> *–रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड*
>
>
>
> प्रदेश भीषण दैवीय आपदा से जूझ रहा है और सत्तापक्ष के विधायक–मंत्री इस तरह दावत उड़ा रहे हैं. यह बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचायक है और आपदा के शिकार लोगों के प्रति अन्याय भी. इस तरह के आयोजन में गोली चलने की घटना, और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक द्वारा, अत्यंत गंभीर मामला है. पार्टी इस मामले को सत्र आरंभ होते ही सदन में उठाएगी.
> *–तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड भाजपा*
>
>
>
> पहले तो आपदा के माहौल में एक मंत्री द्वारा इस तरह दावत का आयोजन ही शर्मनाक घटना है और फिर इस रात्रिभोज में इतने मंत्री–विधायकों की मौजूदगी में गोली चलने की घटना होती है. गोली चलाने का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के ही एक विधायक पर लगता है, जो अत्यंत शर्मनाक है. जब मंत्री आवास में ही लोग सुरक्षित नहीं तो आम जनता का हाल समझा जा सकता है. पुलिस भी लीपापोती का प्रयास कर रही है. हम इस मुद्दे को जोर–शोर से सदन में उठाएंगे.
> *–अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखंड*

[…] निभा रही है, इससे राज्य की जनता भी सकते में है. बहुगुणा सरकार अपनी रक्षा के लिए हर गलत हथकंडे का सहारा ले रहे हैं, सरकार की आपदा की मदद पर जश्न मनाना प्रतिपक्ष के लिए इन दिनों खास मुद्दा बन गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

30 सितंबर-06 अक्टूबर 2013

संसद की एक स्थायी समिति के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनरेगा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. उत्तर प्रदेश में प्रति परिवार मजदूरी के औसत दिनों की संख्या निराशाजनक स्तर पर महज 26 है. समिति की राय में तो इसमें तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, वरना इसको बंद ही कर देना चाहिए.

मनरेगा पर अमल नहीं हो रहा

मार्कंडेय प्रसाद सिंह

केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उत्तर प्रदेश समेत में ठीक से अमल नहीं हो रहा है. ग्रामीण गरीबों की मदद करने के लिए बनाई गई इस योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सफल नहीं रहा. राज्य सरकार न सिर्फ मजदूरों को समय पर पूरी मजदूरी देने में नाकाम रही है, बल्कि योजना का काम देखने के लिए रखे गए प्रशासनिक कर्मचारियों को वेतन समय पर न दे पाने की वजह से उसे न्यायालय में चुनौती भी दे दी गई है. एक माह पहले लखनऊ उच्च न्यायालय ने सरकार को करीब 40 हजार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए कहा. इन कर्मचारियों में ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक और कंप्यूटर सहायक शामिल हैं. ये वे लोग हैं, जिनका पिछले आठ महीने से लेकर दो साल तक का वेतन बकाया है. प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं, जिन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है. उनके पास विरोध प्रदर्शन व अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई चारा नहीं है. कैंपेन फॉर मनरेगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूरतराम कहते हैं कि बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, गोंडा, प्रतापगढ़, वाराणसी, बांदा समेत अनेक ऐसे जिले हैं, जहां तैनात जूनियर इंजीनियर को दो साल से कोई पैसा नहीं मिला है. इन जिलों के लोग ही सरकार के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं. उत्तर प्रदेश मनरेगा टेक्निकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुनाथ पटेल का कहना है कि उनको एक साल से कोई भुगतान नहीं मिला है. पटेल बांदा जिले में इस योजना के तहत बतौर जूनियर इंजीनियर का काम कर रहे हैं. आश्चर्य की बात यह है कि मनरेगा को चलाने के लिए जिन लोगों को रखा गया है. वे केवल वेतन से ही वंचित नहीं, बल्कि उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जा रहा है. पटेल जैसे जुनियर इंजीनियर को हर महीने 8 हजार रुपये वेतन मिलता है. वहीं मध्य प्रदेश में 21 हजार रुपये दिए जाते हैं और राजस्थान में 12 हजार रुपये. जबकि बिहार में तकनीकी सहायक को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं और ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन में भी काफी फर्क है. उत्तर प्रदेश में हर महीने जहां सिर्फ 3,500 रुपये दिए जाते हैं. वहीं बिहार में यह राशि 5 हजार रुपये है, जबकि मध्य प्रदेश में 8 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है.

गोरखपुर निवासी तथा कैंपेन फॉर मनरेगा के उत्तर प्रदेश-बिहार प्रभारी विजय कुमार मिश्र कहते हैं कि मनरेगा के साथ समस्या यह है कि राज्यों के पास धन ही नहीं है, जिसके कारण राज्य कम कार्य उपलब्ध करा पाते हैं. लिहाजा, प्रशासनिक खर्च के लिए निर्धारित रकम का प्रतिशत भी कम हो जाता है और वेतन भुगतान अटक जाता है. संसद की एक स्थायी समिति के एक अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनरेगा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. उत्तर प्रदेश में प्रति परिवार मजदूरी के औसत दिनों की संख्या निराशाजनक स्तर पर महज 26 है. समिति की राय में तो इसमें तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, वरना इसको बंद ही कर देना चाहिए. ■

यूपी में होंगे मनरेगा लोकपाल

संदीप कश्यप

भविष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में अब किसी के लिए भी घोटालों को अंजाम देना आसान नहीं होगा. मनरेगा में लगातार मिल रही धांधली की शिकायतों और काफी हद तक केंद्र के दबाव के बाद अखिलेश सरकार ने मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए करीब दो दर्जन जिलों में मनरेगा लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रथम चरण पूरा कर लिया है. आगे से प्रदेश में जिला स्तर पर मनरेगा के सभी काम मनरेगा लोकपाल की निगरानी में होंगे. शिकायत मिलने पर वह इसकी सुनवाई करेगा. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर 22 जिलों में मनरेगा लोकायुक्त के नामों की घोषणा कर दी गई है. इन नियुक्तियों पर आम लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं. अगर कोई ठोस आधार लेकर नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति नहीं दर्ज हुई तो उन्हीं नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी. केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में लोकपाल की तैनाती के लिए काफी पहले ही दिशा-निर्देश जारी किया था. विज्ञापन के जरिये नाम मांगने और फिर आवेदन पत्रों की पड़ताल के पश्चात चयन समिति ने 22 जिलों में मनरेगा लोकपालों के नाम की संस्तुति ग्राम्य विकास विभाग को भेजी हैं. इनमें लखनऊ, गोंडा, कासगंज, आगरा, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर में दो-दो नामों की संस्तुति की गई है, जबकि बाकी जिलों में एक-एक नाम तय किए गए हैं. ग्राम्य विकास विभाग ने इन नामों की सूची सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से इन पर आपत्तियां मांगी हैं. लोग लखनऊ में वरिष्ठ उपायुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास विभाग के सामने तीन अक्टूबर तक आत्तियां कर सकते है. प्राप्त आपत्तियों को परीक्षण के लिए फिर चयन समिति को भेजा जाएगा. चयन समिति इनका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट गाम्य विकास विभाग की देगी. इसके बाद अपर आयुक्त मनरेगा आपत्तियों पर अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराएंगे. शासन इस पर विचार कर अंतिम तौर पर मनरेगा लोकपालों की नियुक्ति करेगा. ■

बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश की समस्याएं

शिवनाथ चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का करीब डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा होने को है. इस दौरान सपा सरकार पर 2014 के आम चुनाव को देखते हुए वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति करने और प्रशासनिक लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं. वहीं राज्य की कानून व्यवस्था में ही लगातार गिरावट आई. नोएडा में नियुक्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मसले पर भी राज्य सरकार की खासी किरकिरी हुई. हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा अखिलेश सरकार के दामन पर लगा एक ऐसा काला धब्बा है, जो जल्दी छुटने वाला नहीं है. प्रदेश की समस्याएं हर रोज और ज्यादा उलझती लग रहीं हैं. ऐसा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जिन राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के हाथों में है, वे उन्हें सुलझाना भी चाहते हैं. मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में उमड़ने वाली भारी भीड़ यह भी बता रही है कि राज्य का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है. लोगों की मामूली समस्याओं तक का निपटारा थाने, तहसील और जनपद स्तर पर नहीं हो पा रहा है. उन्हें इसके निपटारे के लिए भागकर लखनऊ आने पर विवश होना पड़ रहा है. समाजवादी पार्टी के आला प्रतिनिधियों तक की अफसर अनदेखी कर रहे हैं. बेलगाम तथाकथित समाजवादी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सक्रिय और सशक्त हो गए हैं और ईमानदार अफसरों को अपने हाथ की कठपुतली बना देने पर आमादा हैं. जगह-जगह दबंगों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं घोषणाओं तक सिमट कर रह गई हैं. एक वर्ष बीतने के बाद भी सरकार घोषित अन्य योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहना सकी. कहना गलत न होगा कि उत्तर प्रदेश के बदतर हालात के लिए एक मात्र अखिलेश सरकार दोषी है. मुख्यमंत्री की निष्क्रियता की वजह से ही प्रदेश में भ्रष्टाचार को पर लगे हैं और कानून व्यवस्था रसातल में है. उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था इस वक्त विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है. राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान लोगों की तीखी आलोचनाओं के केंद्र में है और समाजवादी पार्टी की सरकार पर से जनता का भरोसा पूरी तरह से डगमगा गया है. ■

उच्च शिक्षा को लगा ग्रहण

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गाड़ी पटरी पर आए कैसे? सरकार की उदासीनता ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बल्कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की गति पर भी ग्रहण लगा रखा है. उच्चतर शिक्षा आयोग जहां चार साल से एक भी नियुक्तियां नहीं कर सका है, वहीं लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों पर विवादों का साया भारी पड़ रहा है. उच्च शिक्षा के रिक्त पदों की भर्ती के लिए गठित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की यह विडंबना ही है कि उसे एक अध्यक्ष पद तक नहीं मिल पा रहा है. महीनों से यह पद खाली है. आयोग में सदस्य के छह पद होते हैं. पछले एक साल से उनका कोरम पूरा होने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है. इसका असर पूर्व में विज्ञापित हो चुके 1100 पदों पर पड़ा है, जिनकी नियक्तियां अधर में हैं. इससे पहले आयोग ने दो विषयों अर्थशास्त्र व वाणिज्य के प्रवक्ता की लिखित परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया था.

उच्च शिक्षा का हाल ये है कि प्रदेश में शिक्षकों के तीन हजार से अधिक पद लंबे समय से खाली हैं. इससे महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है. यही स्थिति रही तो छात्र-छात्राओं को अगले सत्र में भी शिक्षकों के कमी का सामना करना पड़ेगा. उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों की मांग संबधी पत्रावलियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है. निदेशालय ने तकरीबन 1500 और शिक्षकों की भर्ती के लिए सूची तैयार की है, लेकिन आयोग में सब कुछ ठप रहने के कारण प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी असर आया है. आरक्षण के विवादास्पद फैसले में सरकार की निद्रा इतनी देर में टूटी कि स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी. यहां तक कि रिजल्ट तैयार करके साक्षात्कार की तैयारी भी शुरू करा दी गई. अंतत नये सिरे से रिजल्ट तैयार करना पड़ा. इस पूरे विवाद में कई महीने लगे और पीसीएस मुख्य परीक्षा 2011 का साक्षात्कार अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है. इस आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन सचिव की नियुक्ति के प्रति सरकार उदासीन है. सरकार ने मणिप्रसाद मिश्र और अजय कुमार सिंह को सचिव के पद पर नियुक्त जरूर किया, लेकिन उन्होंने ज्वॉइन ही नहीं किया. ■ *(मा.प्र.सिंह)*

काले धन से काट रहे मलाई

बलिया में अवैध तरीके से अर्जित धन ने प्रॉपर्टी डीलिंग के खेल को न सिर्फ मलाईदार बनाया है, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसकी चकाचौंध से बड़े-बड़ों की आखें भी चौंधियां गई हैं. इससे ताकतवर धनाढ्यों ने काली कमाई अर्जित करने की चाह में तिजोरी का मुंह खोल दिया है. इस खेल में सिर्फ जिला मुख्यालय पर 10 हजार करोड़ रुपये लगे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि पर्दे के पीछे अवैध तरीके से चल रहे इस खेल की भनक किसी को नहीं है.

औने-पौने दाम पर जमीन की खरीद ने रातों-रात प्रॉपर्टी कारोबारियों को करोड़पति बना दिया. बिचौलियों के कान तब खड़े हो गए, जब उन्होंने चंद समय में ही व्यावसायियों की जेब भारी होते देखी. क्रय-बिक्रय में दोनों पक्षों से दो प्रतिशत कमीशन लेने वालों ने इस खेल को नई ऊंचाई दी. नतीजतन कुकरमुत्ते की भांति तथाकथित प्रॉपर्टी डीलरों की तादाद शहर में बढ़ गई. हालत यह है कि लोगों को चूना लगाकर लाखों-करोड़ों का वारा-न्यारा हो रहा है. अचानक बेराजगार युवक भी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं. वे अविवादित भूमि को भी विवादित बताकर अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते. हालांकि, प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर कुछ ही लोग पंजीकृत हैं. उनकी आड़ में करीब पांच हजार दलाल अवैध धन अर्जित करने की होड़ में हैं. *- (शि. च.)*

जनता के हित में योजनाओं की बहार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के भवन और अन्य निर्माण में लगे श्रमिकों के हितार्थ निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वे कर्मकार उठा सकते हैं, जो भवन, मार्गों, सड़कों, रेल पथ, बांध, सुरंग, तटबंध, सेतुओं, जल सेतुओं, जलाशयों, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, तेल/गैस प्रतिष्ठान, विद्युत उत्पादन, वितरण, विद्युत लाइनें, सिंचाई, जल निकासी, बढ़ई, बाल वाइंडर, वेल्डर्स, लोहार, कंक्रीट, पंप ऑपरेटर, क्रेन आपरेटर, मजदूर, कुली आदि पदों पर कार्यरत हो. लाभ केवल पंजीकृत मजदूरों को मिलेगा. पंजीकरण भी उसी मजदूर का हो सकेगा, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होगी तथा निर्माण गतिविधि में वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों तक नियोजित रहा हो. पंजीकरण कार्य जिला स्तर पर श्रम विभाग कार्यालय द्वारा किया जा रहा है. लाभार्थी निर्धारित शुल्क 100 रुपये के साथ 3 नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल साथ में 90 दिन कार्य करने का नियोजन प्रमाण पत्र श्रम कार्यलय में जमा कर अपना पंजीयन करा सकते हैं. पजीयन के पश्चात निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठाने को हकदार होंगे.

दुर्घटना सहायता योजना के अंर्तगत हितलाभ की धनराशि अधिसूचना बढ़ी दर से लागू कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु की स्थिति में 1 लाख रुपये, पूर्ण अपंगता पर अनुग्रह 75 हजार और अपंगता विकलांगता की स्थिति में 40 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा. मातृत्व हितलाभ योजना के अंर्तगत सभी पंजीकृत महिला निर्माण कर्मकार पात्र होंगी तथा अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक 12 हजार रुपये का एकमुश्त भुगतान प्रसव के उपरांत किया जाएगा. शिशु हितलाभ योजना के अंर्तगत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नवजात शिशुओं को दो वर्ष की आयु तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराए जाने हेतु पुत्र होने की स्थिति में 10 हजार रुपये तथा पुत्री होने पर 12 हजार रुपये की वार्षिक दर से भुगतान किया जाएगा.

इसके अलावा राज्य में तमाम योजनाएं चल रही हैं. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना, एंबुलेंस सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजनाएं चल रही हैं. निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसके तहत 20 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी. निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाना है. अक्षमता पेंशन योजना के अंर्तगत पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण अक्षम होने पर 1000 रुपये पेंशन देय होगी. औजार क्रय सहायता योजना के अंर्तगत श्रमिकों को औजार क्रय हेतु दो किस्तों में 1000 रुपये, अधिकतम 5000 रुपये तक देय होगा. निर्माण कामगार आवास योजना के अंर्तगत पंजीकृत श्रमिक के परिवार के नाम न्यूनतम 20 वर्ग मीटर भूमि हो एवं पक्का आवास न होने की स्थिति में 45 हजार रुपये देय होंगे. *- (मा. प्र. सिंह)*

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366